लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation 6-7-92
Fumigated On 9.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 12 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/ CONTENTS

अंक 8, बुधवार, 21 फरवरी, 1968/ 2 फाल्गुन, 1889 (शक)

No. 8, Wednesday, February 21, 1968/ Phalguna 2, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S.Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
181.	कोहिमा में नागा नेताओं का सम्मेलन / Conference of Naga Leaders in Kohima	991—992
192.	नागाओं द्वारा एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की मांग / Nagas' demand for International Commission	992—996
182.	राजकोट और कलकत्ता के लिए ट्रांसमीटर / Transmitters for Rajkot and Calcutta	996—997
183.	पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार / Anti-Indian propaganda by Pakistan	998—1003
185.	बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच / Enquiry into charges against former Chief Minister of Bihar	1004—1006

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.		
184.	ब्रिटेन से सुपरसानिक लड़ाकू बाम्बर विमानों की खरीद / Purchase of Supersonic Fighter Bombers from Britain	1006

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
186.	चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के सम्बन्ध	India's Relations with China and Pakistan	1006
187.	प्रेस परिषद्	Press Council	1006—1007
188.	वाणिज्यक विज्ञापनों के लिए टेलीविजन कार्यक्रम	T. V. Programme for Commercial Adveri-tisements	1007
189.	आयुध कारखानों में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की छंटनी	Retrenchment of Apprentices trained in Ordinance Factories	1007—1008
190.	पाकिस्तान के साथ बातचीत	Talks with Pakistan	1008
193.	रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस और रेडियो मास्को से प्रसारण	Broadcasts from Radio Peace and Progress and Radio Moscow	1008—1009
195.	बस्तियों का आदान प्रदान	Exchange of Enclaves	1009
196.	आकाशवाणी से प्रसारणों के लिये संहिता	Code for A. I. R. Broadcasts	1009—1010
197.	आकाशवाणी राजनैतिक वार्ता	Political Talks on All India Radio	1010
198.	आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट	Staff Artists in A. I. R.	1010—1011
199.	संयुक्त अरब गणराज्य के सहयोग से विमान निर्माण कारखाने की स्थापना	Establishment of Aircraft Factory with UAR Collaboration	1011
200.	चाइल में भारतीय दूतावास के एक अधिकारी द्वारा कारों की बिक्री	Sale of Cars by an Officer of Indian Em-bassy in Chile	1011
201.	पख्तूनिस्तान	Pakhtoonistan	1012
202.	मद्रास में राष्ट्रीय छात्र सेना दल के प्रशिक्षण का बन्द किया जाना	Suspension of N. C. C. Training in Madras	1012
203.	नेपाल को सहायता	Aid to Nepal	1013
204.	पूर्व-पाकिस्तान में हिन्दू	Hindus in East Pakistan	1013- 1014
208.	भारत की सैनिक आवश्यकताओं के बारे में अमरीका की प्रतिक्रिया	USA's Response to India's Military Needs	1014

ता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
209. छोटे समाचार-पत्रों से अभ्यावेदन	Representations from small News Papers	1014-1015
210. आणविक 'टिप' लगी हुई चीनी पनडुब्बियां	Equipment of Chinese Submarines with Nuclear Tips	1015

अता० प्रश्न संख्या

U.S.Q.Nos.

1397. सैनिक क्लबों के लिये समाचार-पत्र और पत्रिकाय	Newspapers and Magazines for Military Clubs	1015
1398. आकाशवाणी साप्ताहिक	Akashvani Weekly	1015
1399. आकाशवाणी साप्ताहिक पत्रिका की छपाई	Printing of Akashvani Weekly	1016
1400. आकाशवाणी साप्ताहिक पत्रिका के लिए खर्च हुआ कागज	Paper consumed for Akashvani	1016
1401. महाराष्ट्र में पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Areas in Maharashtra	1016
1402. टेलीविजन सेटों का निर्माण	Manufacture of Television Sets	1016-1017
1403. एक्स-रे ट्यूबों का निर्माण	Manufacture of X-Ray Tubes	1017
1404. राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक	National Development Council Meeting	1017-1018
1405. विमान उद्योग	Aircraft Industry	1018
1406. खान अब्दुल गफार खां	Khan Abdul Ghaffar Khan	1018
1407. जम्मू श्रीनगर राजपथ	Jammu-Srinagar Highway	1018-1019
1408. नेताजी की कथित मृत्यु के बारे में नये सिरे से जांच	Fresh Inquiry into the reported death of Netaji.	1019
1409. जर्मन गणतंत्र दिवस में भारतीय वाणिज्य दूत	Indian Consulate in G. D. R.	1019
1410. हरयाना की एक फर्म द्वारा टेलीविजन सैटों का निर्माण	Manufacturing of T. V. Sets by Haryana Firm	1020
1411. गणतंत्र दिवस की परेड के निमंत्रण-पत्र	Republic Day Parade Invitation Cards	1020-1021

अता० प्रश्न सं०

U. S.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1412.	नोबोस्ती के साथ करार	Agreement with Novosti	1021
1413.	नोबोस्ती के साथ करार	Agreement with Novosti	1021—1022
1415.	अणु शक्ति का शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये प्रयोग	Peaceful uses of Atomic Energy	1022
1416.	भारत की नौसेना	Indian Navy	1022—1023
1417.	दूतावास के कर्मचारियों द्वारा शराब की बिक्री	Sale of Liquor by E mbassy Officials	
1418.	धारवाड़ और गुलबर्ग रेडियो स्टेशनों से उर्दू कार्यक्रम रिले किये जाना	Relay of Urdu Programmes from Dharwar and Gulaburga Radio Stations	1023
1419.	भारत के व्यापार प्रतिनिधियों का भाषा सम्बन्धी ज्ञान	Linguistic Knowledge of India's Trad Representatives	1024
1420.	रक्षा सामग्री का निर्माण	Manufacture of Defence Articles	1024
1421.	समाचारपत्रों की बिक्री के आंकड़े	Circulation Figures of Newspapers	1024—1025
1422.	गोपालपुर क्षेत्र (उड़ीसा) में परमाणु सामग्री का सर्वेक्षण	Suvey of Atomic Materials in Gopalpur Area (Orissa)	1025
1423.	ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीविजन का विस्तार	Expansion of T. V. in Rural Areas	1025—1026
1424.	टेलीविजन सेट लगाना	Television Net Work	1026
1425.	राजस्थान में कोटा डिवीजन में रिडयो स्टेशन की स्थापना	Setting up of a Radio Station in Kotah Division Rajasthan	1027
1426.	हिन्दी फिल्में	Hindi Films	1027
1427.	ईरान में भारतीय फिल्में	Indian Films in Iran	1027—1028
1428.	पाकिस्तान से प्रतिनिधिमंडल	Delegation from Pakistan	1028
1429.	गणतंत्र दिवस समारोह के लिये निमंत्रण पत्र	Invitation Cards for Republic Day Function	1028—1029
1430.	भारत पूर्व पाकिस्तान सीमा का सीमांकन	Demarcation of Indo East Pak. Border	1029—1030
1431.	उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और मद्रास में परियोजनाएं	Projects in Uttar Pradesh West Bengal and Madras	1030

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1432.	फिरोजपुर में पाकिस्तानी गुब्बारा	Pak. Balloon in Ferozepur	1030-1031
1433.	बिहार योजना	Bihar Plan	1031
1434.	लेफ्टीनेंट जनरल कौल द्वारा लिखित अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक	The Untold Story by Lt. Gen. Kaul	1031
1435.	राष्ट्रपति टीटो के आगमन पर आकाशवाणी से आंखों देखा हाल का प्रसारण	Commentry on the arrival of President Tito	1031-1032
1436.	बी० ई० एल० कम्पनी में रेडियो के पुर्जों का निर्माण	Manufacture of Radio Parts at BEI	1032-1033
1437.	मसानी समिति	Masani Committee	1033
1438.	चीनियों द्वारा नेपाल में सड़क का निर्माण	Construction of Road in Nepal by Chinese	1033-1034
1439.	बिहार में नये रेडियो स्टेशन	New Radio Stations in Bihar	1034
1440.	अजीज ओलोग जेड का रक्षात्मक अभिरक्षण	Protective Custody of Aziz Oulag Zade	1034-1035
1441.	परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना	Non-proliferation of Nuclear Weapons	1035
1442.	भारत तथा श्रीलंका के प्रधान मन्त्रियों की बैठक	Meeting of Indian and Ceylon Prime Ministers	1035-1036
1443.	चंडीगढ़ में डिफेंस कालोनी	Defence Colony at Chandigarh	1036
1444.	रूसी समाचार एजेंसी "नौ वोस्ती" के प्रेस प्रतिनिधि	Press Representative of Soviet News Agency Novosti	1036-1037
1445.	भारतीय वायुसेना के विमान	Indian Air Force Planes	1037
1446.	उत्तर प्रदेश के लिये योजना सम्बन्धी नियतन	Plan allocation for UP	1037
1447.	मध्य प्रदेश को सस्ते रेडियो सेटों की सप्लाई	Supply of cheap radio sets to Madhya Pradesh	1037-1038
1448.	सिक्किम में भारत का राजनैतिक कार्यालय	Indian's Political Office in Sikkim	1038

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. Nos.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1449. राजस्थान में प्रेषण (ट्रांसमिशन) प्रणाली	Transmission System in Rajasthan	1038
1450. नाथु ला में चीनियों का प्रचार	Chinese progaganda at Nathu La	1039
1451. भारतीय राजदूतों के रिक्त पद	Posts of Indian Ambassadors lying vacant	1039
1452. सैनिक भूमि तथा छावनी सेवा	Military Lands and Cantonment Service	1039
1453. टंगस्टेन धातु की खरीद	Purchase of Tungsten Metal	1040
1454. विदेशों में नजरबन्द भारतीय लोग	Indians under detention in foreign countries	1040
1455. सुरक्षा दल टुकड़ियों के बीच गलतफहमी के कारण गोलीबारी	Mistaken Firing between Security Force Units	1040—1041
1456. तारापुर परमाणु बिजलीघर	Tarapur Atomic Power Station	1041
1457. कोचीन नौसैनिक अड्डे के असैनिक कर्मचारी	Civilian employees of Cochin Naval Base	1041—1042
1458. बर्मा तथा श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले भारतीय	Indian repatriates from Burma and Ceylon	1042
1459. एर्णाकुलम में प्रतिरक्षा सम्बन्धी मन्डप	Defence Pavilion at Ernakulam	1042
1460. रेयर अर्थ्स एल्लूर, केरल	Rare Earths, Eloor, Kerala	1042—1043
1461. केरल के त्रावनकोर देवास्वम बोर्ड से ज्ञापन	Memorandum from Travancore Devaswam Board Kerala	1043
1462. संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए प्रतिनिधि मन्डप	Delegation to UNO	1043—1044
1463. दक्षिण कोरिया की समस्यायें	Problems of South Korea	1044
1464. वैज्ञानिक तरीके से कृषि सम्बन्धी फिल्म	Films on Scientific methods of Agriculure	1044
1465. दार्जिलिंग में अर्जित की गई जमीनों के लिये मुआवजा	Compensation for Lands Acquisition Darjeeling	1044—1045
1466. भारत में बनी फिल्में	Indian Made Films	1045

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1467.	मन्त्रिमंडल की नई प्रतिरक्षा समिति	New Defence Committee of the Cabinet	1045—1046
1468.	सेना में वामपंथी साम्यवादियों का आ जाना	Left Communist Infiltration in the Army	1046
1469.	नये प्रसारण केन्द्र	New Boradcasting Stations	1046
1470.	व्यापारिक प्रसारण	Commercial Broadcast	1046—1047
1472.	बड़ोदा में रेडियो स्टेशन	Radio Station in Baroda	1047—1048
1473.	पश्चिम पाकिस्तान में राजपूतों पर अत्याचार	Atrocities committed on Rajputs in West Pakistan	1048
1474.	पिछड़े क्षेत्रों के विका के लिये कार्यक्रम	Programme for Development Backward Areas	1048
1475.	मैक्सिको-अमरीका अणु-शक्ति परियोजना	Mexico-USA Atomic Energy Project	1048—1049
1477.	राष्ट्र ध्वज को सलामी	Slaute to National Flag	1049
1478	पूर्वी पाकिस्तान में पृथकतावादियों का आन्दोलन	Secessoinsts' Move in East Pakistan	1049
1479.	तिब्बती शरणार्थी	Tibetan Refugees	1050
1480.	लेह के साथ सम्पर्क के लिये सड़क का निर्माण	Road Link with Leh	1050
1481.	गणतंत्र दिवस परेड (1968) को बैठने की व्यवस्था	Seating arrangements on Republic Day Parade (1968)	1050—1051
1482.	मारिशस के साथ औद्योगिक सहयोग	Industrial Collaboration with Mauritius	1051
1483.	प्रतिरक्षा तैयारी	Defence preparadness	1051—1052
1484.	पालम के हवाई अड्डे से टायरों और ट्यूबों की चोरी	Theft of tyres and tubes from Palam Airport	1052
1485.	चीन जाने वाले नागा	Nagas going to China	1052
1486.	भारतीय साम्यवादी नेताओं के साथ रूस के प्रधान मंत्री की बैठक	Soviet Prime Minister's meeting with Indian Communist Leaders	1052—1053

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1487.	जेट विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना	Jet Plane mishap	1053
1488.	आकाशवाणी, इम्फाल के कर्मचारियों से अभ्यावेदन	Representations from employees of All India Radio, Imphal	1053—1054
1489.	जंजीबार में भारतीय	Indians in Zanzibar	1054
1490.	काश्मीर पर रूसी इतिहासकार द्वारा टिप्पणी	Commentries by a Soviet Historian on Kashmir	1054—1055
1491.	हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi	1055
1492.	सैगोन में भारतीय	Indian in Saigon	1055—1056
1493.	रेडियो लाइसेंस शुल्क में कमी	Reduction in Radio Licence fee	1056
1494.	हिन्डन हवाई अड्डे पर असैनिक कर्मचारी	Civilian employees working at Hindon Airport	1056
1495.	दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति	Aparthied policy of South Africa	1056—1057
1496.	रोडेशिया	Rhodesia	1057
1497.	आकाशवाणी के श्रेणी तीन के तकनीकी कर्मचारी	Class III Technical Staff of All India Radio	1051—1058
1498.	आकाशवाणी के श्रेणी दो के ड्राफ्टमैनों को स्थायी करना	Confirmation of Draughtsmen Grade II of All India Radio	1058
1499.	पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गए सैनिक अधिकारी तथा जवान	Army Officers and Jawans Arresed by the Police	1058
1500.	गणतंत्र दिवस परेड (1968) पर व्यय	Expenditure on Repubic day Parade (1968)	1059
1501.	समापन समारोह (1968) सम्बन्धी व्यय	Expenditure on Beating Retreat (1968)	1059
1502.	फिल्म डिवीजन के तकनीकी तथा गैर तकनीकी कर्मचारियों की सेवा काल में वृद्धि संबंधी शर्तें	Condititons for Extension of Service to Technical and Non-Technical Employees of Films Division	1059—1060

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1503.	राजनैतिक शरण संबंधी नियम	Rules Regarding Political Asylum	1061
1504.	रूसी नौसेना के कमांडर-इन चीफ की यात्रा	Visit by Commander-in-Chief of Soviet Navy	1061
1505.	पिछड़े वर्गों के लिये अध्ययन दल	Study Group for Backward Classes	1062
1506.	मंत्रियों द्वारा विदेशों का दौरा	Foreign Tours by Ministers	1062
1507.	उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र	Backward areas of Uttar Pradesh	1062—1063
1508.	परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के बारे में संधि	Non-Proliferation of Nuclear Weapons Treaty	1063
1509.	थुम्बा राकेट लांचिंग केन्द्र	Thumba Rocket Launching Base	1063—1064
1510.	संयुक्त अरब गणराज्य के सहयोग से जेट इंजनों का निर्माण	Manufacture of Jet Engines in Collaboration with UAR	1064
1511.	अहमदाबाद से टाइम्स आफ इण्डिया का तृतीय संस्करण	Third Edition of Times of India from Ahmedabad	1064—1065
1512.	त्रिपुरा में पाकिस्तान द्वारा अधिकृत क्षेत्र	Pak. occupied Area in Tripura	1065
1513.	हिमाचल प्रदेश में सड़कें और पुल	Roads and Bridges in Himachal Pradesh	1065
1514.	फरक्का बांध	Farakka Barrage	1066
1515.	पाकिस्तान द्वारा फरक्का बांध के बारे में प्रचार	Propaganda on Farrakka Barrage by Pakistan	1066
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	1067—1068
	मद्रास में हिन्दी विरोधी आन्दोलन	Anti-Hindi agitation in Madras	
	श्री न० कु० साल्वे	Shri N. K. Salve	
	श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri V. C. Shukla	
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1068—1069

अता० प्रश्न संख्या

U S.Q. Nos.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Member's Bills and Resolutions	1069
बीसवां प्रतिवेदन	Twentieth Report	
लोक-लेखा समिति	Public Accounts Committee	1069
अट्ठारहवां प्रतिवेदन	Eighteenth Report	
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	1069
उन्नीसवां प्रतिवेदन	Nineteenth Report	
तारांकित प्रश्न संख्या 572 के सम्बन्ध में पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to a Supplementary Question arising out of S. Q. no. 572	1069—1070
खुदाबक्श ओरियन्टल पब्लिक लाईब्रेरी विधेयक—पुरःस्थापित	Khuda Bakhsh Oriental Public Library Bill Introduced	1070—1071
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of Thanks on President's Address	1071—
श्री जी० बी० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	
श्री च० च० देसाई	Shri C. C. Desai	
श्री राजशेखरन	Shri Rajashekharan	
श्री यज्ञदत्त शर्मा	Shri Yajna Datt Sharma	
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा	Shri mati Jyotsna Chanda	
श्रीमती सुशीला गोपालन	Shri mati Suseela Gopalan	
श्री पी० एम० सैय्यद	Shri P. M. Sayeed	
श्री महन्त दिग्विजय नाथ	Shri Mahant Digvijai Nath	
श्री दामानी	Shri S. R. Damani	
श्री धीरेश्वर कलिता	Shri Dhireswar Kalita	
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	
श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी	Shri Ghulam Mohammad Baskhi	
कार्य-मंत्रालय समिति	Business Advisory Committee	1088
चौदहवां प्रतिवेदन	Fourteenth Report	
भाषा सम्बन्धी आन्दोलन के दौरान	Half-an-hour Discussion Re. Loss to Rail-	1088—1091

विषय	SUBJECT
रेलवे को हानि के बारे में आधे घंटे की चर्चा	ways during language agitation
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goel
श्री कंवरलाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta
श्री विश्वनाथन	Sri G. Viswanathan
श्री चे० मु० पुनाचा	Shri C. M. Poonacha

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 21, फरवरी 1968/ 2 फाल्गुन, 1889 (शक)
Wednesday, February 21, 1968/ Phalguna 2, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ ।

श्री हेम बरुआ : प्रश्न संख्या 181 ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 192 का उत्तर भी इसके साथ ही दिया जाये ।

कोहिमा में नागा नेताओं का सम्मेलन

*181. **श्री हेम बरुआ** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि 1967 के क्रिसमस से पहले नागालैंड बैपटिस्ट मिशन चर्च के तत्वावधान में चुने हुए नागा नेताओं का एक सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्मेलन में छिपे नागा नेताओं ने भाग लिया था और इस सम्मेलन में यदि कोई निर्णय किये गये थे तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां । भारत सरकार के पास सुलभ सूचना के अनुसार, 'नागालैंड बैपटिस्ट चर्च कौंसिल' के नेताओं ने, उन्हीं

के शब्दों में, "सभी नागाओं में स्थायी शांति और एकता स्थापित करने के उद्देश्य से" खास-खास नागा नेताओं की एक बैठक बुलाई। यह बैठक 5 और 6 दिसम्बर, 1967 को हुई थी।

(ख) बताया जाता है कि इसमें दो प्रमुख छिपे नागाओं ने हिस्सा लिया था। इस बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किये गये थे :—

(क) कार्यवाही स्थगन करार अनिश्चित काल तक के लिये जारी रखा जाए और दोनों पक्ष इसकी शर्तों का सख्ती से पालन करें।

(ख) संलग्न इलाकों को, जिनमें नागा बसे हुए हैं, मिला दिया जाये; और

(ग) जल्दी ही एक और बैठक बुलाई जाये जिसमें छिपे नागा हिस्सा लें।

नागाओं द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग की मांग

*192. **श्री श्रीनिवास मिश्र :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमिगत नागा नेशनल कांउसिल ने नागा प्रभुसत्ता के प्रश्न को हल करने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग स्थापित किये जाने की सर्वसम्मत मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :

(क) भारत सरकार के पास सुलभ सूचना के अनुसार 17 और 18 जनवरी, 1968 को जोतसोमा में हुई मीटिंग में छिपे नागाओं ने कथित नागा-भारत संघर्ष में "अंतर्राष्ट्रीय कमीशन" के विधान के लिये एक प्रस्ताव पास किया जिससे कि "नागा प्रभुसत्ता" के प्रश्न का शांतिपूर्ण समाधान किया जा सके।

(ख) इस सम्बन्ध में हमारा रुख कई मौकों पर इस सदन में और छिपे नागाओं को भी स्पष्ट किया जा चुका है। हमने छिपे नागाओं को बार-बार बताया है कि नागा प्रश्न का समाधान भारतीय संघ के ढांचे के अंतर्गत किया जायेगा। नागा प्रश्न भारत सरकार का आंतरिक मामला है जिस पर वही निर्णय करेगी और सरकार का दृढ़ निश्चय है कि वह नागालैंड में कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं होने देगी क्यों कि वह भारतीय संघ का अभिन्न अंग है।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि तथाकथित छिपे नागाओं की सरकार के नये नेताओं ने प्रधान मंत्री को यह जानकारी दी है कि वे बातचीत जारी रखने के लिये तैयार है यद्यपि श्री फिजो की सुरक्षापूर्वक वापसी का आश्वासन दिया जाए, बातचीत पर कोई शर्तें न लगाई जायें और प्रभुसत्ता के लिये नागा मांग के दायरे में ही बातचीत हो; यदि हां, तो इस मांग पर प्रधान मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : मेरे पास ऐसी कोई मांगें नहीं आई हैं।

श्री हेम बरुआ : अब चूंकि तथाकथित छिपे नागाओं का नेतृत्व उग्रवादी तत्वों के हाथों में चला गया है जो श्री फिजो के अनुयायी हैं और उन्होंने अपनी हिंसक कार्यवाहियां

चीन से शस्त्रास्त्र प्राप्त करने के बाद तीव्र कर दी हैं और संसदीय ढांचे के स्थान पर अध्यक्षीय ढांचा स्थापित कर दिया गया है, क्या प्रधान मंत्री छिपे नागा नेताओं से बातचीत करना चाहती हैं, और यदि हां, तो किसके साथ ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : किसी भी बातचीत के लिये इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। यह सच है कि एक वर्ग अधिक उग्रवादी प्रतीत होता है, किन्तु इसके साथ-साथ दूसरा वर्ग भी अधिक बड़ी संख्या में है और कोई यह नहीं कह सकता है कि किसका पलड़ा भारी रहेगा।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न यह था कि यदि प्रधान मंत्री नागा नेताओं से बातचीत करना चाहती हैं तो क्या यह बातचीत उग्रवादी नागाओं के नेताओं से होगी या दूसरे वर्ग के नेताओं से ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने यह कहा कि इस समय किसी के साथ बातचीत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु जब मेरी उनके साथ बातचीत हुई थी तो दोनों वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

श्री शङ्कर सुयाकर : एक ताजा समाचार के अनुसार छिपे नागाओं ने लगभग 1000 व्यक्तियों को चीन में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये चीन में भेजा है। यह समाचार कहां तक सच है तथा इन लोगों के चीन जाने को रोकने के लिए कोई तरीका है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस प्रश्न का उत्तर इस सभा में कई बार दिया गया है। हमने यह स्वीकार किया है कि कुछ छिपे हुये नागा सहायता आदि प्राप्त करने के लिये चीन चले गये हैं। यह बताना सम्भव नहीं है कि कितने नागा गये तथा कितने वापस लौटे।

श्री रंगा : यह तो पुरानी बात है। इस समय क्या स्थिति है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जहां तक हमारी जानकारी है, हाल ही में वहां कोई नहीं गया है। गत जुलाई में हमने कहा था कि उनमें से कुछ गये थे और उनमें से कुछ 2 और 3 के छोटे-छोटे जत्थों में आ गये थे। जहां तक इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का सम्बन्ध है, जैसा कि पहले बताया गया था, प्रत्येक संभव कार्यवाही की जाती है। घने जंगलों के कारण उनका पूरी तरह से जाना रोकना संभव नहीं है। उसे रोकने के लिये हम अपना भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री स्वैल : ऐसे समाचार मिले हैं कि नागाओं की सेना के काटो ग्रुप और अंगामी ग्रुप में फूट पड़ गई है। नागालैंड में हुई बैठक में भाग लेने वाले ये दो व्यक्ति किस ग्रुप से सम्बन्ध रखते हैं ? यदि यह समाचार सच है, तो क्या सरकार ने गतिविधियों का कोई मूल्यांकन किया है और नागालैंड में शांति स्थापित करने में इससे किस हद तक सहायता मिल रही है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जैसा कि प्रधान मंत्री ने अभी बताया, छिपे नागाओं के दो वर्गों में फूट पड़ गई है। 5 और 6 दिसम्बर, 1967 को नागलैंड बैप्टिस्ट मिशन चर्च के तत्वाधान में हुई बैठक में श्री काटो और श्री सेमा दोनों नेता उपस्थित थे। ये व्यक्ति उदारवादी दल

से सम्बन्ध रखते हैं । उग्रवादी नागा समस्या का शांतिप्रिय हल नहीं चाहते । परन्तु हमारा दावा है कि शांतिप्रिय हल चाहने वाले बहुसंख्यक हैं और वे हमारी ओर आ रहे हैं । हमें आशा है कि अन्त में हम उग्रवादी तत्व को पृथक करने में सफल होंगे और सारी समस्या का शांतिपूर्ण हल निकाल पायेंगे ।

श्री रा० बरुआ : क्या सरकार का ध्यान श्री जमीर के हाल के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि वहां पर नागा विद्रोहियों की कार्यवाहियां जोर पकड़ती जा रही हैं और वहां पर सरकार को केन्द्रीय सरकार की सहायता की आवश्यकता है तथा सुरक्षा सेना को नागालैंड सरकार की नियंत्रण में रखी जाये । इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : हिन्दुस्तान टाइम्स में एक समाचार था । एक पत्रकार, चीन में नागा विद्रोहियों के जाने के सम्बन्ध में, मेरे पास स्पष्टीकरण के लिये आया था । अतः मैंने उसे बताया कि लगभग 151 नागा चीन से वापस आ गये हैं । मुझे केवल इतना ही कहना है ।

Shri A.B. Vajpayee : Sir, the Government's stand on this issue is that Naga problem will be solved within the framework of Indian Constitution while Nagas are bent upon the demand for soverignty. May I know where these two stands converge ? After having so many rounds of battles, have Government perceived any change in their attitude and if not, what aim does the Government want to fulfil in prolonging the negotiations ?

Shri Surendra Pal Singh : There is a perceptible change in their mode of thinking in the sense that a number of followers of the extremist group have been weaned away to our side. Many of their followers are joining us. We believe that those who are demanding freedom, if they get an opportunity, would arrive at a conclusion that it would be better for them to remain in India.

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या मैं जान सकती हूँ कि ये नागा, जो कि गोरिला-युद्ध के प्रशिक्षण के लिये चीन जा रहे हैं, किसी नये नागा-नेता के नेतृत्व में जा रहे हैं अथवा उसी पुराने नेता, श्री फिजो, के नेतृत्व, में जा रहे हैं ? मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है तथा सरकार ने इसकी रोक-थाम के लिये कोई कदम उठाये हैं ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह सत्य है कि जो छिपे नागा सीमा पार कर चीन जा रहे हैं तथा वहां से शस्त्र प्राप्त कर रहे हैं, वे श्री फिजो के उग्रवादी दल से सम्बन्धित हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार को इस तथ्य का ज्ञान है कि अभी हाल में ही अमरीकी गुप्तचर विभाग द्वारा आयोजित मॉरल रिआर्मामेंट एसोसिएशन ने कोहिमा में अपना एक प्रतिनिधि भेजा था ? यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि उस प्रतिनिधि की इस यात्रा का क्या अभिप्राय था और वहां पर क्या विचार-विमर्श हुआ ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : एक सदस्य गया था । वह मॉरल रिआर्मामेंट एसोसियेशन की ओर से गया था अथवा किसी अन्य कारण से, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है ; परन्तु जहां तक हमें विदित है, वह किसी छिपे-नागा से नहीं मिला ।

श्री बेदव्रत बरुआ : क्या मैं जान सकता हूँ कि छिपे नागाओं के मुख्य-सेनापति मोव अंगामी पिछले जनवरी मास में नई दिल्ली आए थे । क्या यह भी सत्य है कि उन्होंने यहां

चीनी दूतावास से सम्पर्क स्थापित किया और क्या यह भी सत्य है कि नागालैंड सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सूचित किया है कि श्री मोव अंगामी चीन जाने की योजना बना रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : कोई निश्चित सूचना नहीं है। इस सारे प्रश्न को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने का छिपे नागाओं का प्रयत्न है ; वह चीन से सहायता चाहते हैं, उन्होंने श्री फिजो द्वारा अमेरिका से सहायता पाने के प्रयत्न किये हैं ।

श्री बेदब्रत बरुआ : मैं यह जानना चाहता था कि क्या मोव अंगामी गत जनवरी नई दिल्ली आये थे ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मुझे पता नहीं है ।

Shri Rabi Ray: There are two groups amongst the underground Nagas—those who want to remain satisfied while remaining with India, and those who want to have talks while remaining out of India. May I know which of these two groups has more following ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उसका उत्तर पहले ही दे दिया है । भारत-पक्षी नागा अधिक संख्या में हैं ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह देखते हुए कि पार्थक्य-प्रवृति एक भयंकर प्रवृति है तथा यह देश के दूसरे भागों में फैलती जा रही है, क्या सरकार ने नागाओं को यह स्पष्ट कर दिया है वह पृथक होने की उनकी मांग पर कभी विचार नहीं करेगी ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : ऐसा हर सम्भव अवसर पर किया गया है। हम उन्हें अपना निश्चय बता चुके हैं ।

श्री म० ला० सोंधी : क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार ने ब्रिटिश पत्रों के लेखों के हाल के झुकाव पर विचार किया है जिनसे नागालैंड सहित, भारत के विभिन्न स्थानों पर भारत की प्रादेशिक अखण्डता को चुनौती देने की ब्रिटिश सरकार की राजनैतिक मनोवृत्ति स्पष्ट प्रतिबिम्बित होती है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मैं नहीं जानता कि इसका क्या उत्तर दे सकता हूँ ?

Shri Chandrajit Yadav : It has been repeated by the Government several times that the underground Nagas crossed over to China several times, got their training there and accelerated their activities after coming back to India. It is also said that as the situation here is difficult due to hills, forests etc., it is very difficult to have a complete check on it. It is also correct that with reference to border security, we had to face such situations in Ladakh and other places also ; but the nation will not be satisfied with such an excuse that as we have a difficult situation here we are unable to make arrangement accordingly. If our countrymen go to foreign countries for a rebellion against India, get training there, thereafter return and enhance their rebellious activities, then, I would like to secure a clear assurance in this regard that on these borders of the country where such a difficult situation prevails, no rebellion against India will be allowed to prosper in future and people will not be able to get training in other countries to launch rebellious activities in the country.

Shri Surendra Pal Singh : It has already been said that we try our level best that people do not get opportunity to go outside the country and secure aid ; but it is a very difficult job as there are many terrains and forests, and it is not possible to check all the persons at all the places. They do not go in groups from the places they live. Had they been going in groups, it would have been possible for our security forces to check them; and whenever they tried to cross over in groups, they have been checked. But those people go in the batches of two or three. They collect

at a place already fixed and leave from there ; and our borders are very vast. Still I want to assure the Hon'ble Member that as far as our security force is concerned, it is trying to check them.

Shri Chandrajit Yadav : Mr. Speaker, I want to clarify my question once again.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काफी लम्बा था तथा उत्तर भी बहुत लम्बा ।

Mrs. Indira Gandhi : All have heard the question of Hon'ble Member and its answer too has been given a number of times that it is not a fact that we are helpless in this matter. The situation is improving but has not improved fully.

राजकोट और कलकत्ता के लिए ट्रांसमीटर

*182. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी केन्द्रों से देश के आंतरिक प्रसारणों को बढ़ाने की दृष्टि से राजकोट और कलकत्ता में लगाये जाने वाले सुपर पावर ट्रांसमीटरों जैसे ट्रांसमीटर देश के अन्य क्षेत्रों में लगाने का कोई कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : देश के आंतरिक प्रसारण में सुधार करने के लिये चन्दा समिति ने बी० बी० सी० की भांति एक एक निगम बनाने की सिफारिश की थी । उस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ? क्या छोटे पैमाने के उद्योग द्वारा 51 रु० के ट्रांसिस्टर सेट उपलब्ध करने के बारे में योजना में कुछ प्रगति हुई है ? यदि हां, तो यह ट्रांसिस्टर कब तक उपलब्ध हो जायेंगे ?

श्री के० के० शाह : पहले प्रश्न का उत्तर एक सप्ताह पहले दिया गया था । फिर भी मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर विचार हो रहा है । हम उस पर शीघ्र निर्णय करेंगे । दूसरे प्रश्न के बारे में स्थिति ऐसी है कि नमूने के तौर पर मुझे एक ट्रांसिस्टर प्राप्त हुआ है । उसकी कीमत 51 रुपये है । एक और ट्रांसिस्टर का मूल्य 65 रुपये है । मुझे आशा है कि दो महीनों के दौरान ये बाजार में बिक्री के लिये मिल सकेंगे ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि हमारे देश के उत्तरी भागों में हमारी प्रसारण व्यवस्था ठीक नहीं है । बाड़मेर जैसे क्षेत्रों में जहां पाकिस्तान रेडियो तो ठीक प्रकार सुनाई पड़ता है परन्तु आकाशवाणी के प्रसारण सुनाई नहीं देते । देश के उत्तरी भागों में प्रसारण व्यवस्था को ठीक करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री के० के० शाह : 100 किलोवाट के चार ट्रांसमीटर कानपुर, जालंधर, कलकत्ता और डिब्रूगढ़ में 1968 के पूर्वार्ध में स्थापित किये जा रहे हैं । राजस्थान के बारे में मैंने पहले ही कह दिया है कि वहां एक रेडियो स्टेशन स्थापित किया जायेगा ।

Shri Sheo Narain : Certain foreigners have been appointed in A. I. R. It should be checked.

श्री के० के० शाह : यह कार्यवाही करने के लिये एक सुझाव है ।

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

हमें विदेशी तत्वों के बारे में जागरूक रहना चाहिये । परन्तु मैं चाहती हूँ कि माननीय सदस्यों को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये क्यों कि इससे वहाँ पर कार्य कर रहे लोगों को परेशानी होती है ।

Shri Prem Chand Verma : May I know the action taken in regard to setting up of a high-powered Radio station in Himachal Pradesh and the time by which this transmitter is likely to be set up ?

श्री के० के० शाह : स्थान का चयन कर लिया गया है । निर्माण-कार्य हो रहा है । ट्रांसमीटर उपलब्ध है। जैसे ही निर्माण-कार्य पूरा होगा, ट्रांसमीटर स्थापित कर दिया जायेगा ।

Shri O. P. Tyagi : Our transmitters are not very powerful. The Indians living in other countries are very anxious to listen to our broadcasts but they cannot. The transmitters of Pakistan are comparatively more powerful. May I know what steps are proposed to be taken in this regard ?

श्री के० के० शाह : इसी कारण दो सुपर पावर ट्रांसमीटरों की स्थापना की जा रही है । इनमें से एक मध्य-पूर्व क्षेत्र के लिये और दूसरा दक्षिण-पूर्वी एशिया के लिये होगा । इसके अलावा दो अधिक शक्ति वाले सूक्ष्म तरंग वाले ट्रांसमीटरों की स्थापना भी की जा रही है ।

श्री नारायण राव : राज्यों के भाषाओं के आधार पर पुनर्गठन के बाद आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में प्रसारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है । पहले मद्रास से यह सुविधा प्राप्त थी । क्या सरकार भाषाओं के आधार पर प्रसारण की व्यवस्था करने पर विचार करेगी ?

श्री के० के शाह : वर्तमान व्यवस्था सभी क्षेत्रों के लिये काफी है ।

Shri Gulam Mohammad Bakshi : The transmitter at Srinagar, perhaps, is the weakest. What are the proposals in this regard ?

श्री के० के० शाह : श्रीनगर का ट्रांसमीटर मध्यम तरंग का है । पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहां शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाना ठीक नहीं । यदि आवश्यक हुआ, तो वहाँ एक और स्टेशन स्थापित किया जा सकता है ।

श्री मनुभाई पटेल : रियासतों के विलय से पहले बड़ोदा में एक ट्रांसमीटर होता था परन्तु बाद में किसी और स्थान पर ले जाया गया था । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वह पुनः लगा दिया जायेगा ?

श्री के० के० शाह : बड़ोदा में अब भी एक ट्रांसमीटर है ।

Anti-Indian Propaganda by Pakistan

+

*183. **Dr. Surya Prakash Puri:** **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Prakash Vir Shastri: **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state ;

(a) whether Pakistan is constantly indulging in virulent anti-Indian propaganda in foreign countries even after it has repeatedly professed adherence to the Tashkent Agreement ;

(b) whether it is also a fact that Pakistan's Press and Radio are also indulging in such propaganda ;

(c) if so, whether the Government of India have lodged any protest with the Pakistan Government (or any friendly countries) in this connection ; and

(d) if so, their reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendrapal Singh) : (a) and (b) No Sir.

(c) and (d) Yes Sir. We have lodged protest from time to time but the reaction thereto has been negative.

Dr. Surya Prakash Puri: I want to know whether Government's attention has been drawn to Pakistani broadcasts in which foul language is used against Indian leaders and the Prime Minister ? This programme is broadcast between 7-30 and 8.00 p.m. Anti-Indian propaganda is broadcast in this programme. Have we sent any protest in this regard ?

Shri Surendra Pal Singh: When ever we come across such propaganda, we lodge a protest.

Dr. Surya Prakash Puri : The evening broadcasts of B.B.C. are generally anti-Indian. Almost all discussions are like that. Have the Government sent any protest to British Government in this matter ?

Shri Surencdra Pal Singh : This question pertains to propaganda from Pakistan.

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : Whenever B.B.C. broadcasts something agaist us, we do protest.

Shri Raghuvir Singh Shastri : Our Government has celebrated the second anniversary of signing Tashkent Declaration and our President has declared that inspite of Pakistan's hostile attitude, we will adhere to a policy of friendship towards Pakistan. We would make every effort for normalising relations with Pakistan. I want to know whether Pakistan's attitude continues to be as bad as it was and India's confiscated property has not been released by it so far ?

अध्यक्ष महोदय : आपने तो भाषण आरंभ कर दिया है ।

Shri Surendra Pal Singh : The information given by the hon. Member is factual.

Shri Atal Bihari Vajpayee : A conference of Muslim countries was held in Rawalpindi recently. It has been reported that in that conference not only the Pakistan delegate but other delegates also spoke against India. I want to know whether a report on this conference has been called for and whether Government have any information in this regard; if not, whether Government will give an assurance to get this information ?

Shri Surendra Pal Singh:We have not got the information but I assure that we will look into this. I may add in this regard that as and when foreigners visit and something like that is said, we do lodge protest.

Shri A. B . Vajpayee : When the hon.Minister is not aware of this fact, what will he say to those Governments ?

Shri Surendra Pal Singh : As I have stated that I am unware of it, but we act in this very way in other matters of this kind.

अध्यक्ष महोदय : आपके पीछे बैठे हुए सदस्य बोलने के लिये बार-बार उठ रहे हैं लेकिन जब मैं उन्हें बोलने के लिए कहता हूँ तब वह बैठे रहते हैं। बाद में वह आपत्ति उठाएंगे।

श्री हेम बरुआ : अध्यक्ष महोदय, जब दूसरी ओर के सदस्य प्रश्न करना नहीं चाहते फिर भी आप उन्हें प्रश्न करने के लिए प्रेरित करते हैं।

एक माननीय सदस्य : यह समता का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : यह समता का प्रश्न नहीं है। एक या दो बार वे प्रश्न करने को उठते हैं ; और जब मैं उनकी ओर देखता हूँ वे नहीं उठते लेकिन बाद में वे शिकायत करते हैं कि मैं उन्हें बोलने का अवसर नहीं दे रहा हूँ । यही मेरे लिए समस्या बनी हुई है। जब वे प्रश्न करने को उठते हैं तो उन्हें सचेत होना चाहिए ।

Shri Y. S. Kushwah : Inspite of India's opposition, Pakistan has continued anti-Indian propaganda. May I know what India has done to cope with the situation ?

Shrimati Indira Gandhi : Many actions of Pakistan are not proper. I do not agree that we should also act in that very way. We oppose vigourously such actions and steps on the part of Pakistan which we consider improper.

श्री रा० ढो० भण्डारे : क्या भारत सरकार इस बात से अवगत है कि पाकिस्तान द्वारा भारत-विरोधी प्रचार का किसी भी देश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : यह सत्य है कि पाकिस्तान द्वारा लगातार भारत-विरोधी प्रचार किया जा रहा है और मेरे विचार में इसका प्रभाव अन्य देशों पर कम होता जा रहा है लेकिन मैं यह नहीं कह सकती कि पाकिस्तान के भारत-विरोधी प्रचार का दूसरे देशों पर प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है ।

श्री बलराज मधोक : प्रधान मंत्री महोदय ने अभी-अभी कहा कि हम पाकिस्तान की नकल नहीं कर सकते । यह सत्य है । लेकिन पाकिस्तान रात और दिन रेडियो और समाचार-पत्रों द्वारा भारत-विरोधी प्रचार कर रहा है तथा जनमत तैयार कर रहा है और युद्ध का वातावरण पैदा कर रहा है । अगर आप पाकिस्तान रेडियो सुनें तो आपको विदित हो जायेगा कि वे वैसे ही गीत और अपीलें प्रसारित कर रहे हैं जैसे कि युद्ध के समय किया करते थे । इतना ही नहीं, पाकिस्तानी दूतावास ने यहां संसद्-सदस्यों में ऐसे पर्चे बांटे हैं जिनमें भारत-विरोधी सारी मिथ्या बातें दर्ज हैं । क्या मैं यह जान सकता हूँ कि भारत सरकार पाकिस्तान के इस

भारत-विरोधी प्रचार को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है और किसी भी आकस्मिकता का सामना करने के लिए क्या कर रही है, जो मेरे विचार से बहुत ही निकट है?

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं माननीय सदस्य से इस बात में सहमत नहीं हूं कि कोई ऐसी आकस्मिकता निकट है लेकिन मेरे विचार से किसी भी दूतावास का इस प्रकार माननीय सदस्यों में भारत-विरोधी पर्चे बांटना अनुचित कार्य है, मैं बहुत कृतज्ञता प्रकट करूंगी यदि माननीय सदस्य.....(व्यवधान)

श्री बलराज मधोक : एक प्रति प्रधान मंत्री महोदय को भी मिल गयी होगी।

श्रीमती इंदिरा गांधी : कुछ भी हो, मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं किया गया और मुझे प्रसन्नता होगी यदि माननीय सदस्य, जिनके पास ऐसी पर्चियां हैं, मुझे भी ला कर दें।

Shri Madhu Limaye : What does the intelligence bureau do ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : जहां तक सारे देश को तैयार करने का सम्बन्ध है, यह एक बड़ा भारी प्रश्न है। यह केवल प्रचार करने मात्र तक सीमित नहीं है बल्कि यह प्रश्न है एक बड़े सुदृढ़ औद्योगिक आधार का और अन्य प्रकार की तैयारियों का और इसके लिए सरकार ने समुचित कदम उठाए हैं तथा उठाती रहेगी।

श्री दी० च० शर्मा : जब कि हम पाकिस्तानी समाचार-पत्रों द्वारा भारत-विरोधी प्रचार की चर्चा कर रहे हैं। क्या मैं उपमंत्री महोदय से प्रश्न कर सकता हूं कि यदि सरकार इस तथ्य से अवगत है कि ढाका से प्रकाशित होने वाले 'नवाए मिलत' जैसे समाचार-पत्र और पाकिस्तान से प्रकाशित होने वाले कुछ समाचार-पत्र काश्मीर और अन्य मामलों में भारत का समर्थन करते हैं तो भारत सरकार का वैदेशिक-कार्य मंत्रालय इस तथ्य को लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाता अथवा कम से कम संसद्-सदस्यों तक क्यों नहीं पहुंचाता ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह सुझाव कार्यवाही के लिए है।

श्री रंगा : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सोवियत रूस ताशकन्द भावना और ताशकन्द समझौते को सफल बनाने में इतनी अधिक रुचि प्रकट कर रहा है, क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान में हो रहे भारत विरोधी प्रचार की ओर रूस सरकार का ध्यान आकर्षित किया जिससे उन्हें दोनों देशों में हो रहे कार्यों की जानकारी हो सके ? पाकिस्तान तो भारत-विरोधी प्रचार में संलग्न है जब कि भारत ताशकन्द समझौते की भावना का पूर्णरूपेण सम्मान कर रहा है और पाकिस्तान के विरुद्ध कोई प्रचार नहीं कर रहा है।

श्रीमती इंदिरा गांधी : केवल सोवियत यूनियन ही ताशकन्द भावना बनाये रखने की इच्छुक नहीं बल्कि अमेरिका भी इसका इच्छुक है।

श्री रंगा : परन्तु श्री कोसिगिन आपको उस दिन एक धर्मोपदेश दे चुके हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं समझती हूं कि इस विषय में तुलनायें देना सम्भव नहीं है। फिर भी, दोनों देशों को सूचना दी गई हैं।

श्री नायनार : कच्छ पंचाट के पश्चात् दोनों राष्ट्र, सीमा-सुरक्षा सम्बन्धी प्रबन्ध दृढ़ कर रहे हैं। पाकिस्तान ने गत वर्ष की अपनी सूचना-विज्ञप्तियों में से एक में दोष लगाया

है कि भारत ने 600 बार ताशकान्द समझौते का उल्लंघन किया है । अब तक उस दोषारोपण का खण्डन नहीं किया गया है ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : यह सत्य है कि जब भी हम विरोध भेजते हैं वे हम पर दोषारोपण भी करते हैं, और वे हमारे विरुद्ध दोष धरते हैं कि हम स्वयं ही ताशकन्द समझौते का उल्लंघन करते हैं । परन्तु हम समझते हैं कि वे दोष अनुचित और निराधार हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ ।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या यह सत्य है.....।

Shri Bhogendra Jha : Mr. Speaker, on a point of order. You have said that an Hon'ble Member will get only one chance to put question. You may give two-three chances if you like, but you should change the procedure. We do not want to take exercise by standing fifty times. When you have laid down a procedure that an Hon'ble Member will get only one chance to put question, then why are you going to give the chance again ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मेरे विचार से ऐसा कोई नियम नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई नियम नहीं है । यदि वह प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं उन्हें अवसर दूँगा ।

Shri Sheo Narain : I agree with Mr. Jha. You do not call the Member who stands up but you call the one who is sitting. We have an experience of State Assembly and Council that that Member is called first in whose name the question stands; and then an opportunity is given to those who later rise.

अध्यक्ष महोदय : हर अवसर पर माननीय सदस्य खड़े होते हैं। वह सदैव ही खड़े हो जाते हैं । मैं मानता हूँ कि वह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। परन्तु वे इतने कठिन होते हैं कि मंत्रीगण भी उनका उत्तर नहीं दे सकते ।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं निवेदन कर सकता हूँ कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक सदस्य को एक से अधिक पूरक प्रश्न करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ? आपने तो यह एक परिपाटी स्थापित करने का प्रयत्न किया है कि एक सदस्य को दो से अधिक प्रश्न करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर अब विवाद न करें ।

श्री हेम बरुआ : परन्तु इस पर आपत्ति की गई है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका उत्तर दूँगा । उन्हें यह प्रश्न करने दें ।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या यह सत्य है कि जब श्री कोसिगिन से भारत यात्रा की तब पाकिस्तान के भारत-विरोधी प्रचार के बारे में उनको बताया गया था क्योंकि वह ताशकन्द समझौता कराने वाले व्यक्ति थे ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : जी हां ।

श्री हेम बरुआ : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

एक माननीय सदस्य : वह बड़ी भावक हैं ।

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं अधिक भावुक नहीं हूँ । मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुकी हूँ जब प्रो० रंगा ने इसे पूछा था ?

श्री हेम बरुआ : प्रोफेसर रंगा ने सोवियत संघ के बारे में पूछा था । मैंने तो विशिष्ट प्रश्न पूछा था कि क्या पाकिस्तान के भारत-विरोधी प्रचार के बारे में श्री कोसिगिन को बताया गया था, जब वे भारत आये थे ।

श्रीमती इंदिरा गांधी : "जी हां" ।

Shri Kunwar Lal Gupta : Mr. Speaker, It is a plain question.Pakistan propagates against our country and builds up arms and ammunition. I want to ask the Hon'ble Minister whether our Government considers Pakistan as a friendly country or hostile one ? If it considers her as friendly then why do you take up these measures to face her, and if it considers her hostile then why do you follow Tashkent Agreement ?

Shrimati Indira Gandhi : It is not a plain question, Mr. Speaker.

Shri Kanwar Lal Gupta : You consider Pakistan friendly or hostile ?

Shrimati Indira Gandhi : Mr. Speaker, this question is difficult owing to the reasons that the word 'hostile' has got certain specific meaings in the diplomatic field. That is why we cannot give a plain answer to it.

Shri Sheo Narain : Mr. Speaker, I want to know the action the Government propose to take against the citizens of our own country who propogate against India ?

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि मैंने कहा, यह एक कठिन प्रश्न है तथा इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता । इसमें अध्यक्ष क्या कर सकता है ?

Shri Sheo Narain : Is the Government aware that you received complaints against the Ceylonese Ambassador ....(Interruptions).

अध्यक्ष महोदय : हमें सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहिये । यदाकदा यह उचित हो सकता है परन्तु हर प्रश्न पर मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

Shri Bhogendra Jha : In the context of the partition of country which divided the people of one language, one culture and and even of some villages into two parts, there is no alternative in the long run left for us and Pakistan but to live friendly. Keeping this in view is the Government reluctant—as our Hon'ble Prime Minister was hesitating in answering the question —to tell that we want to keep friendly relations with Pakistan ? In the prevalent circumstances, we want to encourage those powers in Pakistan itself, which want to live with us in peace, and weaken those which adopt an attitude of enemity. Form this point of view, has the Government instructed the country's newspapers or A. I. R. to exercise such attitude that the uniting powers are strengthened and violent powers weakned ?

Shrimati Indira Gandhi : It is a good proposal by the Hon'ble Member. But our newspapers are not controlled by the Government. It is correct that such proposal can be put to them but it is for them to agree to it or not. In so far as Radio is concerned, the Hon'ble Minister is here and he might have noted it.

Shri Sitaram Kesri : I want to ask the Prime Minister that since Pakistan is continuously propagating against us, did she ever discuss it with the Pakistani Authorities to avoid such propaganda ?

Shrimati Indira Gandhi : It is our continuous effort that such a propaganda should not be made. This question was disscused with such Pakistanis who came to India, whether they belonged to Government or not. But I never had a regular discussion with anyone on this matter.

श्री म० ला० सोंधी : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार को ज्ञात है कि पाकिस्तान के पास दो भागों में विभाजित एक परिचालन अनीकिनी है, ताकि एक तो भारतीय राजनैतिक ढांचे तथा भारतीय राजनीतिक दलों को बदनाम किया जा सके तथा दूसरे, देश के भीतर और बाहर, स्वातंत्र्य को बढ़ावा देने की भावना के भारत के स्वाधिकार का दमन किया जा सके ? क्या मैं विशिष्ट रूप से जान सकता हूँ कि क्या हमारी प्रचार और प्रसार व्यवस्था समस्त भारतीय राजनैतिक दलों की पाकिस्तानी प्रचार से रक्षा करना चाहती है और क्या हमारी प्रचार और प्रसार व्यवस्था में पख्तूनिस्तान तथा पूर्वीय पाकिस्तान की स्वतंत्रता के प्रश्नों पर प्रक्षेपण करने के भी प्रयास सम्मिलित हैं ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : विदेशों में भारत का सही चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास हम अवश्य करते हैं परन्तु हम दूसरे राष्ट्रों के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते ।

श्री म० ला० सोंधी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। उदाहरणार्थ, यदि जन संघ अथवा संयुक्त समाजवादी दल पर अपवचनात्मक आक्रमण किया जाता है तो क्या हमारे प्रेस सहचारी अथवा कोई अन्य, इसका मुकाबला करते हैं या ऐसा केवल तभी किया जाता है जब कि केवल कांग्रेस पार्टी पर ही आक्रमण किया गया हो ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : राजनैतिक दलों के विषय में हम ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करते ।

Shri K. N. Tiwary : Are the Government aware that Pakistan and China both collectively propagate against India; Pakistan propagating through Radio Peking and China through Radio Pakistan ? If so, what steps are being taken in this regard ? Has Pakistan been told in this respect that she should not undertake Chinese propaganda against India through her own Radio ?

Shri Surendra Pal Singh : Mr. Speaker, Sir, it is correct that both the countries have been making propaganda against us, and we have always told Pakistan about it.

Shri Ram Charan : Will the Prime Minister say that our propaganda tactics are defective ? It has been the tactics of Pakistan to engage a person of the other country and propagate through him. But our ambassadors are totally a failure to create such an atmosphere. Pakistan has proved sucessful in this direction. Will the Government set up some effective machinery for this purpose ?

Shri Surendra Pal Singh : Mr. Speaker, we do not know what sort of propaganda machinery does Pakistan have and how does it function. But our embassies do whatever is necessary to dispel this propaganda.

बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच

+

*185. श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० गोपालन :
श्री उमानाथ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री का ध्यान 14 जनवरी, 1968 के 'हिन्दुस्तान' में बिहार के भूतपूर्व राज्यपाल द्वारा प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है कि प्रधान मंत्री ने आदेश दिये थे कि बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री के० बी० सहाय के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच तत्कालीन विधि मंत्री श्री जी० एस० पाठक द्वारा गैर-सरकारी तौर पर की जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या श्री सहाय ने श्री पाठक को फाइलें दिखाने से इन्कार कर दिया था ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Mohammad Ismail : May I know the charges levelled by the Bihar Government against the former Chief Minister Shri K. B. Sahai and whether the Central Government have referred this matter to C. B. I. , if not, the reasons therefor ?

Shrimati Indira Gandhi : When some complaints were received they were referred to the Law Minister for comments. Later, the matter had been taken up with the Chief Minister.

Shri Madhu Limaye : What was his opinion ?

Shrimati Indira Gandhi : He was holding an enquiry. In the meantime the elections came. Afterwards, the next Government of Bihar filed a suit against him.

Shri Mohammad Ismail : What were the charges and will they be laid on the Table of the House.

Shrimati Indira Gandhi: All those things were published at that time and it is not proper to place them on the Table now. Later, when this matter was taken before the court, the Supreme Court gave stay order on Shri K. B. Sahay's writ petition.

श्री प० गोपालन : अब बिहार का मण्डल मंत्रिमण्डल इन मामलों की जांच को छोड़ देना चाहता है । अत: मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या श्री के० बी० सहाय और उनके साथियों के विरुद्ध लगाये आरोपों की जांच जारी रखी जायेगी और इस सम्बन्ध में क्या

गारन्टी दे सकती हैं कि जिन सरकारी दस्तावेजों में आरोप हैं उन्हें बिहार का मण्डल मंत्रिमण्डल नष्ट नहीं करेगा ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं नहीं समझती कि मण्डल मंत्रिमण्डल इस मामले में हस्तक्षेप कर रहा है । किन्तु निश्चय ही हमारा यह प्रयत्न होगा कि ऐसे किसी भी प्रमाण को नष्ट न किया जाये ।

Shri Sita Ram Kesri: Do Government propose to hold an enquiry into the allegations of misappropriation levelled against Shri Mahamaya Prasad and his Colleagues ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं इसकी जांच करूंगी । मुझे इसका पता नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : I presume the Prime Minister has read the Santanam Commission report. Despite the recommendation in that report to the effect that if more than ten legilsators, whether M.Ps. or M.L.As. level charges of corruption against a Minister, enquiry should be instituted into those allegations, enquiry into the allegations made against K. B. Sahay and Orissa ministers has not been instituted even when the requisite condition has been complied with. 192 charges were levelled against Shri K.B. Sahay. Has the Central Government or the Central Bureau of Investigation conducted an enquiry into these charges, if not what are the reasons for that ?

Shrimati Indira Gandhi : As stated already that matter has been taken over by the State Government and prior to this taking over no C. B. I. investigation was held into it.

Shri Madhu Limaye : Why it was not held ? Afterall 192 charges do constitute some basis.

Shrimati Indira Gandhi : The 192 charges were received later. The facts which had come to light earlier were being enquired into, but not by C. B. I. I had asked the Law Minister to conduct an enquiry.

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न का सम्बन्ध उस अभ्यावेदन से है जो संविधान सभा के सदस्यों द्वारा और जिस पर संसद्-सदस्यों के भी हस्ताक्षर थे, प्रधान मंत्री को दिया गया था । श्री के० बी० के विरुद्ध दिये गये उस अभ्यावेदन पर प्रधान मंत्री द्वारा क्या कार्यवाही की गई थी ? क्या उस अभ्यावेदन को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास भेजा गया था और यदि हां, तो क्या उस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जैसा कि पहले बताया गया इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास नहीं भेजा गया था । परन्तु उन आरोपों को मैंने विधि मंत्री के पास भेजा था और कोई अग्रेतर कार्यवाही करने से पूर्व हम उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे थे । अब चूंकि बिहार सरकार ने मुकदमा दायर कर दिया है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं ।

श्री प्र० के० देव : क्या महामाया प्रसाद मंत्रिमण्डल के गिरने और मण्डल मंत्रिमण्डल के बनने से पूर्व श्री सहाय ने बैंक में से काफी धन निकाल लिया था ताकि जांच आयोग के प्रयत्न सफल न हों ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ब्रिटेन से सुपरसानिक लड़ाकू बाम्बर विमानों की खरीद

*184. श्री बाबूराव पटेल : श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने हाल में ब्रिटेन से कई हाकर-हंटर सुपरसानिक लड़ाकू विमान खरीदे हैं जो न तो अधिक गति से चलते हैं, न ही ठीक तरह से काम करते हैं और जो न ही आधुनिक ढंग के बने हुये हैं जिन विशेषताओं का होना आधुनिक युद्ध में नितान्त आवश्यक समझा जाता है ;

(ख) किन कारणों से सरकार को ब्रिटेन के इन पुराने लड़ाकू बाम्बर विमानों को खरीदना पड़ा है ; और

(ग) इन विमानों को खरीदने के लिए कितना धन व्यय करना पड़ा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) और (ख) यू० के० से कुछ हण्टर विमानों के क्रय का प्रबंध किया गया है, क्यों कि वह लाभदायक हैं और उनकी कुछ संख्या आई० ए० एफ० की सेवा में है । हण्टर विमानों के यू० के० की आर० ए० एफ० की सेवा में होने की भी सूचना है ।

(ग) सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के सम्बन्ध

*186. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन और पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिए मित्र राष्ट्रों की ओर से हाल के महीनों में कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रेस परिषद्

*187. श्री सीताराम केसरी : डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री योगेन्द्र शर्मा : श्री यशवन्त सिंह कछवाह :
श्री रवि राय : श्री सेझियान :
श्री जुगल मण्डल : श्री शिवचन्द्र झा :
श्री बलराज मधोक :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रमजीवी पत्रकार संघ ने सरकार द्वारा गठित प्रेस परिषद् का बहिष्कार कर दिया है और इसके गठन के बारे में विवाद उठ जाने के कारण परिषद् कार्य नहीं कर सकी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस परिषद् के सभापति तथा कुछ सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस बारे में व्यक्त विभिन्न विचारों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस परिषद् का पुनर्गठन करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) से (घ) एक विवरण (अंग्रेजी में) सदन की मेज पर रखा जाता है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 169/68]

वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिए टेलीविजन कार्यक्रम

* 188. श्री हिम्मतसिंहका : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन कार्यक्रमों का वाणिज्यिक प्रसारणों के लिये उपयोग करने का विचार है, जैसा की आकाशवाणी से किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) जी, हाँ । परन्तु यथा समय पर, जब आय अच्छी हो जायगी।

(ख) इस समय सवाल नहीं उठता ।

आयुध कारखानों में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की छंटनी

*189. श्री स० मो० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967 में विभिन्न आयुध कारखानों में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं को नौकरी से निकाल दिया गया है ;

(ख) वर्ष 1965-67 की अवधि में सरकार ने इन प्रशिक्षुओं पर कुल कितनी राशि खर्च की ; और

(ग) यदि हां, तो उनके लिये रोजगार की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल०ना० मिश्र) :

(क) सुपरवाइज़री एप्रेन्टिस विशिष्ट आवश्यकताओं के विरुद्ध भर्ती किए जाते हैं, और सफलतापूर्वक प्रशिक्षण की समाप्ति पर सभी पर्यवेक्षक नियुक्तियों में खपा लिये जाते हैं । एप्रेन्टिसों को एप्रेन्टिस ऐक्ट 1961 के अनुबंधों के अन्तर्गत आयुध कारखानों में प्रशिक्षण दिया जाता है । प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक सम्पूर्ति पर ऐसे एप्रेन्टिसों को रोजगार

प्राप्य करने का उत्तरदायित्व सरकार पर नहीं है। प्राप्य रिक्त स्थानों के आधार पर उन्हें आयुध कारखानों की नियमित सेवा में खपा लिया जाता है।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) क्योंकि प्रशिक्षित कार्मिकों की आवश्यकता प्रशिक्षण-प्राप्त कार्मिकों से कम है, सभी सफल प्रशिक्षार्थियों को आयुध कारखानों में खपा पाना सम्भव नहीं है।

पाकिस्तान के साथ बातचीत

*190. श्री योगेन्द्र शर्मा : श्री चेंगलराया नायडू।
श्री गाडिलिंगन गौड : श्री वेदव्रत वरुआ :
श्री य० अ० प्रसाद : श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच अनिर्णीत मामलों को निपटाने के लिये भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत पुनः आरम्भ करने के लिये कोई नवीन प्रयास किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में भारत के प्रस्ताव पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :

(क) और (ख) पिछले कुछ महीनों में भारत सरकार ने असैनिक विमानों का आना-जाना फिर शुरू करना, व्यापार पुनः आरम्भ करना, सभी सीमा-पड़ताल चौकियों को फिर से खोलना, जब्त की हुई संपत्ति की वापसी, संचार व्यवस्था पुनः आरम्भ करना, यात्रा सुविधाओं में ढील देना आदि, जैसे कुछ विषयों पर तकनीकी अथवा सरकारी मीटिंगों में बातचीत करने का प्रस्ताव किया है। भारत के प्रस्तावों पर पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया अभी तक उत्साह-वर्धक नहीं रही है।

रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस और रेडियो मास्को से प्रसारण

*193. श्री कामेश्वर सिंह : श्री ओथरन :
श्री शिवचन्द्र झा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में जब रूस के प्रधान मंत्री भारत आये थे तो उनके साथ रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस और रेडियो मास्को से प्रसारणों के बारे में बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ क्या-क्या बातचीत हुई और उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) जी

नहीं । मास्को-स्थित भारत के राजदूतावास ने सोवियत विदेश कार्यालय के साथ इस मामले को पहले उठाया था । सोवियत सरकार ने इस प्रकार के प्रसारणों पर हमारी प्रतिक्रिया पर सम्यक तौर से विचार करने का वादा किया है ।

Exchange of Enclaves

*195. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the progress made in respect of exchanging Indian and Pakistani enclaves situated in East Pakistan and West Bengal ;

(b) the action taken for the security of the residents of Indian enclaves in Pakistan ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Sri B. R. Bhagat) :

(a) In reply to supplementary questions arising from Starred Questions No. 421 answered in the Lok Sabha on the 4th December, 1967, it has already been stated that the position taken by the Government of Pakistan was that they would not agree to the exchange of enclaves unless the Berubari question was settled. As the House is ware, the demarcation of the Berubari Union was contested by means of a writ petition filed in the Calcutta High Court. By a judgment pronounced on the 3rd January, 1968, the High Court passed an order restraining the respondents, including the Government of India, from announcing the "appointed day" and from constructing any pillars to demarcate Berubari Union No. 12 for the purpose of effecting the transfer of the portion of that Union to Pakistan until a law is passed by the appropriate legislature providing for payment of compensation to the petitioners in respect of their disputed properties.

(b) The Government of India have been in correspondence with the Government of Pakistan in regard to the sending of police parties to the enclaves, on a reciprocal basis.

आकाशवाणी से प्रसारणों के लिये संहिता

*196. श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री रवि राय :
श्री प्र० ना० सोलंकी : श्री नायनार :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी से प्रसारणों के लिये हाल में प्रकाशित "संहिता" किस उद्देश्य से तथा किसके द्वारा बनाई गई है ;

(ख) इस संहिता को लागू करने के बारे में इसका निर्वाचन करने के लिये आकाशवाणी के अधिकारियों द्वारा क्या अर्हताएं अपेक्षित हैं ; और

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि जनता ने सामान्यतः इस संहिता के विरुद्ध राय व्यक्त की है क्योंकि यह प्रतिगामी हैं तथा नागरिकों के विचार स्वातन्त्र्य के अधिकार का उल्लंघन करती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) इस का उद्देश्य कुछ मूल्यवान और वांछनीय परम्पराओं और प्रथाओं को संहिता-

बद्ध करना था ताकि इनका आदर करते हुए भाषण की स्वतंत्रता और खुले विवाद का पूरा लाभ उठाया जा सके ।

(ख) समूचे राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए और जिम्मेवारी के साथ स्वतन्त्रता देते हुए, लेकिन लापरवाही को रोकते हुए इस संहिता का निर्वचन करने की क्षमता। जरूरत पड़ने पर उन्हें आकाशवाणी महानिदेशालय के महानिदेशक और सूचना तथा प्रसारण मन्त्री की सलाह हर समय उपलब्ध है ।

(ग) सामान्यतः जनता ने इस संहिता का स्वागत किया है परन्तु जैसा कि स्वाभाविक है, कहीं-कहीं इसके विरुद्ध भी विचार प्रकट किये गये हैं ।

Political Talks on All India Radio

*197. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether all the political parties in the country and their leaders are entitled to give talks on the All India Radio ;

(b) if so, the time given to each of the political parties for giving talks on the All India Radio since the last General Elections to date; and

(c) the reasons for the difference, if any, between the time given to different parties and the basis on which time is given for such talks ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) :

(a) and (b) In the absence of agreement on allocation of time amongst different political parties at the time of general elections no time is allotted to any political party as such. In these circumstances no political party or its leader is as such entitled to give talk as a matter of course on AIR, but talkers are booked by AIR on the basis of their knowledge and competence over the subject of talks and this is done irrespective of the party to which the talker belongs. On topics of national interest occasionally round table talks are arranged in which the leaders of the political parties are invited to participate.

(c) Does not arise.

आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट

*198. **श्री जार्ज फारनेन्डीज** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी और उसमें काम करने वाले स्टाफ आर्टिस्टों के बीच कोई विवाद है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विवाद के निपटारे के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) से (घ) आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की संस्था कुछ सालों से चल रही है

और स्टाफ आर्टिस्टों की ओर से यह एसोसियेशन इस बात पर जोर देती रही है कि स्टाफ आर्टिस्टों को स्थायी सरकारी कर्मचारी बना दिया जाए । इसका निर्णय होने तक कि इनकी इस मांग को मन्जूर किया जाता, यह निर्णय किया गया कि वर्तमान करार के बदले उन्हें 55 वर्ष तक की आयु तक काम करने का नियुक्ति-पत्र दिया जाये । इस नियुक्त-पत्र में बीस वर्ष के सेवाकाल के करार की शर्त भी थी। ये शर्तें स्टाफ आर्टिस्टों को मन्जूर नहीं थी, इसलिये इसे नियुक्ति-पत्र में से हटा दिया गया । इसी बीच, एसोसियेशन दो भागों में बंट गई । इसलिये, इन दोनों में से किसी एक से भी बतचीत करना कठिन हो गया क्योंकि मान्यता देने का प्रश्न इस बात पर निर्भर करता है कि सबसे अधिक सदस्यता किस की है, जिसका पता उनके पंजीकृत होने के 6 माह बाद ही लग सकता है । तो भी, बीस वर्ष वाली शर्त के हटा देने के पश्चात् भी नियुक्तिपत्र की कई अन्य शर्तों पर आपत्ति की गई जिसके कारण इस नियुक्तिपत्र को जारी होने से रोक दिया गया । इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, सरकार सक्रिया रूप से यह विचार कर रही है कि क्या मूल एसोसियेशन के साथ तबतक बातचीत जारी रखी जाए जब तक यह बात स्पष्ट न हो जाए कि किस यूनियन को बहुमत प्राप्त है ।

Establishment of Aircraft Factory with U. A. R. Collaboration

*199. **Sri Atal Bihari Vijpayee** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the aircraft factory set up at Cairo with Indian collaboration is functioning satisfactorily ; and

(b) if so, whether it is proposed to set up a similar factory in India in collaboration with U.A.R. ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) :

(a) No aircraft factory has been set up in the U. A. R. with Indian collaboration.

(b) There is no proposal to set up an aircraft factory in India in collaboration with U.A.R.

Sale of Cars by an Officer of Indian Embassy in Chile

*200. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Officer of the Indian Embassy, Chile (South America) earned a large amount by selling one Impala and one Fiat 1100 before his return to India ;

(b) whether it is also a fact that when the price of a new Impala is about 3,200 dollars in America, it was sold for 10,000 dollars in Chile by this Officer; and

(c) whether this Officer had purchased cars and disposed them on very large profit in this very fasion in Australia also, before leaving that country ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat) : (a) to (c) : This matter is under investigation and on its completion the facts of the case, which are being collected from the concerned Mission abroad, will be placed before the House.

पखतूनिस्तान

*201. श्री गु० सि० ढिल्लों : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई / अगस्त 1967 में किसी भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने तथा युनाइटेड पखतूनिस्तान फ्रंट के सचिव ने उप-प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया था जिसमें पखतूनिस्तान के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने तथा पखतूनिस्तान सम्बन्धी विचार का स्पष्टीकरण करने के लिए उनके प्रतिनिधिमण्डल के विदेश जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) यूनाइटेड पखतूनिस्तान फ्रंट का एक प्रतिनिधिमंडल 6 अगस्त, 1967 को उप-प्रधान मंत्री से मिला था और फ्रंट द्वारा पास किए गए प्रस्ताव की प्रति दी थी । उप-प्रधान मंत्री के साथ इस प्रतिनिधिमंडल ने जो बातचीत की थी, उसमें और न प्रस्ताव में ही संयुक्त राष्ट्र में पखतूनिस्तान के मसले को उठाने का अथवा पखतूनिस्तान के पक्ष को समझाने के लिए विदेशों में प्रतिनिधिमंडल के जाने की अनुमति देने का कोई उल्लेख किया गया था ।

मद्रास में राष्ट्रीय छात्र सेना दल के प्रशिक्षण का बन्द किया जाना

*202. श्रीमती तरकेश्वरी सिन्हा :
श्री रवि राय :
श्री जुगल मंडल :
श्री बलराज मधोक :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री सेझियान :
श्री अटल बिहारी वाजपेई :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास वे सरकार ने 25 जनवरी, 1968 से राज की सभी शिक्षा संस्थाओं में तब तक के लिये राष्ट्रीय छात्र सेना दल तथा सहायक छात्र सेना दल का प्रशिक्षण बन्द कर दिया है जब तक केन्द्र राज्य सरकार की इस मांग को स्वीकार नहीं कर लेता है कि कमान से हिन्दी के शब्द निकाल दिये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) :

(क) ए० सी० सी० की योजना 1965-66 में बन्द कर दी गई थी। जहां तक एन० सी० सी० का सम्बन्ध है, मद्रास सरकार ने डायरेक्टर एन० सी० सी० मद्रास से प्रार्थना की थी, कि जब तक उनकी केन्द्रीय सरकार की इस प्रार्थना पर निर्णय न लिया जाए कि एन० सी० सी० में प्रचलित कमान के शब्द अंग्रेजी में होने चाहिए या प्रादेशिक भाषा में, वह इस सम्बन्ध में और प्रशिक्षण, ड्रिल, कक्षाएं या शिविर आयोजित न करें । तदनुसार डायरेक्टर एन० सी० सी० वे ऐसा समस्त प्रशिक्षण, बन्द कर दिया है ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

नैपाल को सहायता

*203. श्री क० प्र० सिंह देव : श्री दीवीकन :
श्री दी० चं० शर्मा : श्री जुगल मंडल

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नैपाल सरकार ने अपनी कुछ परियोजनाओं का विकास करने के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार नेपाल सरकार द्वारा मांगी गई सहायता देने के लिए सहमत हो गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न परियोजनाओं के विकासार्थ अब तक नैपाल सरकार को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) भारत सरकार छोटी सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि बागवानी तथा ग्राम एवं उद्योग के क्षेत्रों में खास खास विकास योजनाओं के लिए 4 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सहायता देगी। यह धन राशि अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक अर्थात् 31 मार्च, 1969 तक उपयोग में लाई जानी है। यह अतिरिक्त सहायता नैपाल के महामहिम की सरकार के विशेष अनुरोध पर दी जा रही है और यह उन योजनाओं के अलावा होगी जो कि मार्च, 1971 में समाप्त होने वाली पांच वर्ष की अवधि के भारतीय सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले ही स्वीकृत हो चुकी है।

(घ) यह सूचना श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 379 के उत्तर में 25 मई, 1967 को उप–प्रधान मंत्री ने सदन को दे दी है।

Hindus in East Pakistan

*204. **Shri Ram Avtar Sharma:** **Dr. Surya Prakash Puri :**
Shri Prakash Vir Shastri : **Shri Attal Bihari Vajpayee :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Hindus in East Pakistan are being continuously harassed deliberately resulting in their increased migration to India ;

(b) whether it is also a fact that certain prominent Hindu nationals had been arrested recently in that connection ; and

(c) if so the reaction of the Government of India thereto ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The Government of India have repeatedly represented to the Government of Pakistan regarding the plight of the minorities there, and have reminded them of their obligations

under the Nehru-Liaquat Pact of 1950. The question of providing security to the minorities is a duty which the Government of Paskitan owes to its own nationals.

भारत की सैनिक आवश्यकताओं के बारे में अमरीका की प्रतिक्रिया

*208. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 'टाइम्स आफ इंडिया' के वाशिंगटन स्थित संवाददाता के 5 जनवरी, 1968 के इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीका अब भारत की सैनिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिये राजी है क्योंकि उसको "एक साम्यवादी पड़ोसी" से खतरा बना हुआ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त समाचार ठीक है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) यू० एस० सरकार द्वारा 12 अप्रैल 1967 को घोषित भारत और पाकिस्तान को सैनिक साजसामान की सप्लाई के सम्बन्ध में संशोधित नीति के अन्तर्गत घातक सैनिक सामान की सप्लाई फिर से शुरू करदी गई है । तदपि घातक सामान की सप्लाई अभी तक पुनः शुरू नहीं की गई, सिवाए सीमित हद तक, मामले दर मामले के आधार पर फालतू पुरजों की नकद सप्लाई के जो भूतकाल यू० एस० ए० द्वारा पहले से सप्लाई किये गये घातक साज सामान के लिए हों । यू० एस० सरकार की उपरोक्त नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।

छोटे समाचारापत्रों से अभ्यावेदन

*209. **श्री जार्ज फरनेंडीज** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छोटे समाचार-पत्रों से अभ्यावेदन मिला है कि बड़े समाचार-पत्रों का अनियंत्रित विस्तार होता जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार का विचार भारत में समाचारपत्रों के एकाधिकार को समाप्त करने तथा छोटे समाचारपत्रों को प्रोत्साहन देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सरकार की कोई निश्चित योजना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) जी, हां । केवल एक समाचार–पत्र ने अभ्यावेदन दिया था ।

(ख) और (ग) अपने एक मूल उद्देश्य के अनुसार, प्रेस परिषद् ने समाचार-पत्रों में एकाधिकार या एक मालिक के साथ में कई समाचार–पत्रों के आने की प्रवृति बढ़ने का अध्ययन करना पहले ही शुरू कर दिया है । अगस्त, 1967 में विभिन्न लोगों को जारी की गई प्रश्नावली के उत्तर मिलने पर वह अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देगी । परिषद् द्वारा दी गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार आगे कार्यवाही करने पर विचार करेगी । सरकार छोटे और मध्यम समाचार-पत्रों को उचित विज्ञापन, अखबारी कागज के बटवारे में तरजीह तथा प्रेस रिलीज फीचर

लेख, फोटे, एबानाइड ब्लाक आदि नियमित रूप से देकर उनको पहले ही क्रमबद्ध प्रोत्साहन और सहायता दे रही है।

आण्विक 'टिप' लगी हुई चीनी पनडुब्बियां

*210. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 दिसम्बर, 1967 के "पैट्रियट" में प्रकाशित इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि चीनी पनडुब्बियों में आण्विक टिप लगे हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) चीन की नौसेना द्वारा संकट का सरकार समय पर आंकन करती है, और भारतीय नौसेना को शक्तिशाली बनाने और उसके आधुनिकीकरण के लिए उपयुक्त उपाय किए जा रहे हैं।

Newspapers and Magazines for Military Clubs

1397. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether any lists of approved and disapproved or proscribed Newspapers, Weeklies and Monthly Magazines have been prepared for Military Clubs, Reading Rooms and Libraries ;

(b) if so, the details thereof and the names and number of copies of the Newspapers and Magazines of different languages which are purchased by Government for the army ; and

(c) the measures adopted by Government to prevent circulation and propagation of disapproved or proscribed newspapers and magazines in the army ;

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :

(a) to (c) : Military units are allotted funds to purchase reading material according to their needs. Lists of suitable reading material, revised from time to time, selected from the large number of publications available are also circulated for information and guidance of the units who make purchases according to availability of funds and the suitability of material for their particular needs. There is no system of approved or disapproved newspapers, weeklies or monthly magazines, though publications considered inappropriate for read ing by troops are not included in the guidance lists.

आकाशवाणी साप्ताहिक

1398. श्री बाबूराव पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक पत्रिका "आकाशवाणी" की कितनी प्रतियां प्रतिमास भाषा-वार, छापी जाती हैं, और उन पर कितनी लागत आती है और प्रत्येक भाषा की पत्रिका की बिक्री तथा उनमें छपने वाले विज्ञापनों से कितनी शुद्ध आय होती है और वर्षिक हानि अथवा लाभ कितना होता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : एक विवरण अंग्रेजी में संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है [पुस्कालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 170/68]

आकाशवाणी साप्ताहिक पत्रिका की छपाई

1399. श्री बाबूराव पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक भाषा संस्करण की साप्ताहिक पत्रिका "आकाशवाणी" के मुद्रकों के नाम क्या हैं और उन्हें प्रति वर्ष छपाई के लिये कितनी राशि दी जाती है और क्या इस प्रयोजन के लिये टेंडर मांगे गये थे और यदि हां, तो कब ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 171/68]

"आकाशवाणी" साप्ताहिक पत्रिका के लिए खर्च हुआ कागज

1400. श्री बाबूराव पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक भाषा की "आकाशवाणी" साप्ताहिक पत्रिका में प्रति वर्ष कितने मूल्य का कागज लगता है और उस देश तथा व्यापारियों के नाम क्या हैं, जिनसे यह कागज प्राप्त किया जाता है और प्रत्येक व्यापारी को प्रतिवर्ष कितनी राशि का भुगतान किया जाता है ;

(ख) इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि "आकाशवाणी" अंग्रेजी प्रति का मूल्य 30 पैसे है, क्या "आकाशवाणी" पत्रिका के अंग्रेजी प्रकाशन को अच्छा बनाने तथा उसमें अच्छा कागज लगाना सरकार के लिये संभव है ; और

(ग) इन प्रकाशनों को सरकारी मुद्रणालय में न छपवाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) से (ग) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 172/68]

Development of Backward Areas in Maharashtra

1401. **Shri Deorao Patil**: Will the **Prime Minister** be pleased to state the steps taken so far or proposed to be taken in the coming years for the development of backward areas in Maharashtra ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : Attention is invited to the reply given to Unstarred Question No. 3698 on December 11, 1967. It is hoped that the State Government will draw up specific programmes for the accelerated development of its backward areas, so that they can be included in their Fourth Five Year Plan.

टेलीविजन सेटों का निर्माण

1402. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयातित टेलिविजन सेटों के मूल्यों की तुलना में भारत में निर्मित टेलीविजन सेटों के मूल्य कितने कम या अधिक हैं ;

(ख) क्या हमारे देश में वाणिज्यिक पैमाने पर टेलीविजन सेट बनाये जाते हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इस स्थिति में पहुँचने में कितना समय लगने की संभावना है ; और

(घ) 1970 तक वाणिज्यिक पैमाने पर कितने टेलीविजन सेट बनाये जाने का अनुमान है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) देशीय ज्ञान के आधार पर 10000 टी० वी ० सेटों के निर्माण के लिए दो फर्मों को लाईसेंस दिए गए हैं । आशा है कि वह इस वर्ष के मध्य में उत्पादन आरंभ कर देंगे । आशा है कि देशीय निर्मित सेट मूल्य में आयात सेट के मूल्य का लगा अच्छी तरह खा सकेगा ।

(घ) लगभग 50000 की संख्या में ।

एक्स-रे ट्यूबों का निर्माण

1403. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में एक्स-रे ट्यूबों की खरीदारी पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ;

(ख) क्या देश में सरकारी क्षेत्र में एक्स-रे ट्यूबों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) क्या इसके लिये विदेशी सहयोग प्राप्त किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र):

(क) सूचना इकट्ठी की जा रही है, और बाद में सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) जी हां । राजकीय क्षेत्र की एक कम्पनी भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटिड बंगलौर को एक्स-रे ट्यूबों और ट्यूब हाऊसिंग्स के निर्माण के लिए लाइसेंस दिया गया है ।

(ग) भारत इलेट्रानिक्स लिमिटेड दो प्रकार की स्टेशनरी एनोड ट्यूबें और एक रोटेटिंग एनोड ट्यूब और उनके लिये हाऊसिंग के निर्माण का विचार रखते हैं, जो आशा है एक्स-रे की वृहत् आवश्यकताओं को आवृत्त कर लेंगे। आशा है उत्पादन लगभग 1969 के आरंभ में शुरू हो जाएगा।

(घ) जी हां, इस उद्देश्य के लिये सर्वश्री सीमेंज एक्टेन्जेसलशैफ्ट पश्चिमी जर्मनी के साथ एक करारनामा तय पाया है ।

राष्ट्रपति विकास परिषद् की बैठक

1404. श्री जार्ज फरनेंडीज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) दिसम्बर, 1967 में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक आयोजित करने के लिये कब निर्णय किया गया था ; और

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक जानबूझकर आयोजित की गई थी ताकि कांग्रेस के सभी मुख्य मंत्री दिल्ली में होने से कांग्रेस अध्यक्ष चुनने में सहायता मिल सके ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) योजना आयोग की 10 नवम्बर 1967 को हुई बैठक में यह निश्चय किया गया था कि दिसम्बर, 1967 में राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक बुलाई जाय।

(ख) जी, नहीं ।

Aircraft Industry

1405. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) the production capacity of aircraft building industry in the country at present ;

(b) the percentage of Indian and foreign components of machinery being used in the industry ;

(c) the percentage of raw material and spare parts available indigenously and those imported for aircraft-building ; and

(d) the names of the countries from which these materials and spare parts are imported and the amount of foreign exchange involved annually ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra (a) to (d) : It will not be in public interest to give these informations.

खान अब्दुल गफार खां

1406. श्री सु० कु० तापड़िया ।
श्री० जी० विश्वनाथन :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जनवरी, 1968 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि यदि भारत सरकार निमंत्रण दे, तो खान अब्दुल गफार खां भारत में बसने को तैयार हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) इसका सवाल ही नहीं उठता क्योंकि यह रिपोर्ट ही ऐसी थी ।

जम्मू-श्रीगर राजपथ

1407. श्री अंबचेजियान :
श्री यशपाल सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के इन्जीनियरों ने जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजपथ में सुधार करने और उसका विकास करने के लिये आरम्भ किया गया नया सर्वेक्षण पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) नये सम्पर्क मार्ग का निर्माण-कार्य कब आरम्भ होने की सम्भावना है;

(घ) उस पर कितना व्यय होगा ; और

(ङ) इस नई योजना से पूरा वर्ष सड़क चालू रखने में कहां तक सहायता मिलेगी ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) एक नया सर्वेक्षण हस्तगत किया गया है । (डायरेक्टर जनरल सड़क विकास) रोड्ज विंग ; इंजीनियर इन चीफ, सेना मुख्यालय, और डायरेक्टर जनरल सीमा सड़क पर सम्मिलित इंजीनियरों की एक समिति ने 1966 में आवश्यक सुधार कार्यों के विस्तार का निरीक्षण किया था । प्रगतिशील सुधार कार्यों की योजनाओं को उपरोक्त समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् अन्तिम रूपरेखा दी गई थी । हस्तगत कार्यों में शामिल है विचरना को चौड़ा करना, सड़कों की पपड़ी को चौड़ा करना और उसका सुधार, मोड़ों, सुपर एलीवेशन, दृश्यता दूरी इत्यादि में सुधार, और विभिन्न रक्षात्मक और सर्पी दढ़ीकरण निर्याण कार्य ।

(ग) किसी नई लिंक का निर्माण प्रस्तावित नहीं है । एक सर्पी क्षेत्र के पास से जाने के लिए एक सड़क 1966–67 में बनाई गई थी ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

नेताजी की कथित मृत्यु के बारे में नये सिरे से जांच

1408. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन में अनेक संसद् सदस्यों ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की कथित मृत्यु के बारे में नये सिरे से जांच कराने की मांग की है ;

(ख) क्या इस मांग पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) 1956 में जो सरकारी जांच समिति बनाई गई थी, सरकार ने उसके इस निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया है कि 1945 में एक विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई थी । चूंकि इस बारे में कोई नये तथ्य सामने नहीं आए हैं, इसलिए सरकार के विचार से नये सिरे से जांच की जरूरत नहीं है ।

Indian Consulate in G. D. R.

1409. **Shri Shashibhushan Bajpai** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the details of the special scheme proposed to be drawn up for the development of Indian Consulate in German Democratic Republic ?

The Prime Miniter, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi : We are not aware of any special scheme for this purpose.

Manufacturing of T. V. Sets by a Haryana Firm

1410. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Telefunken India, Limited, Ballabgarh (Haryana), have sent an application to the Central Government for manufacturing Television sets; and

(b) if so, the action taken thereon ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) :

(a) and (b) The application received from M/s Telefunken India Limited was not approved as it envisaged foreign collaboration.

गणतंत्र दिवस की परेड के निमंत्रण पत्र

1411. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा :** **श्री क० लक्कप्पा :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गणतंत्र दिवस समारोह, 1968 के लिये बी–1 अहाते के लिये मंत्रियों तथा संसद् सदस्यों के नामों में कितने निमंत्रण-पत्र जारी किये गये थे और वस्तुतः उन्हें कितने पास दिये गये थे ;

(ख) इस अहाते में कितने स्थान उपलब्ध थे ;

(ग) इस अहाते के लिये संसद् सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को कितने निमंत्रण-पत्र जारी किये गये थे ;

(घ) क्या यह सच है कि इस अहाते में कई मंत्रियों तथा बहुत से संसद् सदस्यों को स्थान नहीं मिल सका; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

	(क) जारी किए गए नियंत्रण पत्रों की संख्या	वास्तव में वितरित किए गए नियंत्रण पत्रों की संख्या
(1) मंत्री अध्यक्ष/उपाध्यक्ष लोक सभा और उप-सभापति राज्य सभा	58	58
(2) संसद् सदस्य	612	*606

*शेष निमन्त्रण-पत्र इसलिए वितरित नहीं किए जा सके कि 4 हालतों में परेड देखने का अभिप्राय बहुत विलम्ब से प्राप्त हुआ था, एक हालत में रिहाईश पर ताला लगा था, और एक और हालत में उन महान व्यक्ति ने अपनी रिहाईश बदल ली थी।

(ख) 1120।

(ग) मन्त्रियों/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष लोक सभा/उपसभापति राज्य सभा समेत लगभग 235 महान व्यक्तियों को निमन्त्रण-पत्र जारी किए गए थे ।

(घ) और (ङ) प्रायः सभी निमन्त्रित व्यक्ति समारोह में शामिल नहीं होते । इसलिए वी–1 अहाते में प्राप्य किए गए स्थान काफी होने चाहिए थे । तदपि भीड़ अधिक हो गई थी और प्रबंध विस्थापित, क्योंकि कई महान व्यक्ति दूसरों के लिए अलाट किए गए स्थानों पर बैठ गए, और कई व्यक्तियों की ऐसी संख्या को भी साथ ले आए, कि जिनके लिए वी–1 अहाते के निमन्त्रणपत्र जारी न किए गए थे । यथा संभव अतिरिक्त स्थान प्राप्य किए गए थे ।

नोवोस्ती के साथ करार

1412. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि "नोवोस्ती", जिसके साथ प्रेस सूचना विभाग ने हाल ही में एक करार किया है, एक ऐसा संगठन है, जो विश्व में अनेक स्थानों में जासूसी तथा तोड़फोड़ की अनेक गतिविधियों में सुनियोजित ढंग से संलग्न है ; और

(ख) क्या "नोवोस्ती" के स्वरूप तथा पूर्ववृत्त के बारे में इन समाचारों की सचाई का सरकार ने पता लगाया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) और (ख) समाचार पत्रों में छपी इस प्रकार की कुछ रिपोर्टें देखने में आई हैं, परन्तु सरकार के पास इन आरोपों की सत्यता या असत्यता के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

नोवोस्ती के साथ करार

1413. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) नोवोस्ती के साथ प्रेस सूचना विभाग द्वारा किये गये करार के पश्चात् प्रेस सूचना विभाग ने "नोवोस्ती" के रूसी समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं में प्रकाशन हेतु जो समाचार तथा प्रचार समाग्री दी है उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) प्रकाशन के लिये भारत से भेजी गई विविध सामग्री में से रूसी समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं ने वस्तुतः किस अनुपात में तथा कितना प्रकाशित किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) प्रेस सूचना कार्यालय–नोवोस्ती करार के अन्तर्गत कार्यालय, सूचना पत्र समाचार नहीं भेजता, वह केवल भारत से सम्बन्धित पृष्टभूमि सूचना, फीचर लेख और फोटो भेजता है । 29 फीचर लेख (जिनमें 14 लेख फोटो सहित थे), जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण (अंग्रेजी में) दिया हुआ है, नोवोस्ती को भेजे गये । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 173/68] ये लेख भारत के समाचारपत्रों को भी भेजे गये ।

(ख) "नोवोस्ती" ने पत्र सूचना कार्यालय को सूचित किया है कि उन्होंने पत्र सूचना कार्यालय द्वारा भेजी गई सामग्री को वितरित करना प्रारम्भ कर दिया है। पत्र सूचना कर्यालय की सामग्री के प्रयोग के बारे में ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

Peaceful Uses of Atomic Energy

1415. **Shri Ram Avtar Sharma:** **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Y. S. Kushwah : **Shri Prakash Vir Shastri :**

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether any scheme has been formulated in regard to the peaceful uses of atomic energy for the coming year ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Prime Minister, Miniser of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs : (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) and (b) The attention of the Honourable Members is invited to the statement laid on the Table of the House in reply to Starred Question No. 735 dated December 18, 1967 in the Lok Sabha which gives full information about the work done by the Atomic Energy Commission in the peaceful uses of atomic energy.

Research and development work in the application of atomic energy to power generation, agriculture, industry and medicine are proposed to be continued and expanded. The Tarapur Atomic Power Project is expected to be commissioned during the year, while work on atomic power projectsat Pratap Sagar and at Kalapakkam near Madras will proceed further. A beginning is expected to be made in the construction of a Heavy Water Plant, a Fast Breeder Reactor and the Variable Energy Cyclotron.

भारत की नौसेना

1416. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रियर एडमिरल श्री एस० एन० कोहली ने समाचार-पत्र संवाददाताओं को बताया है कि भारतीय नौ सेना शीघ्र ही दो पनडुब्बियां प्राप्त कर रही है ;

(ख) क्या नौ सेना के किसी प्रमुख अधिकारी के लिये एक खुले सम्वाददाता सम्मेलन में नौ सेना सम्बन्धी गुप्त रहस्यों को बताया जाना उचित है ;

(ग) क्या इस प्रकार के आचारण के सम्बन्ध में हमारी प्रतिरक्षा सेनाओं के लिये कोई विशेष अनुशासन संहिता है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) प्रेस से एक अनौपचारिक भेंट में रीयर एडमिरल एस० एन० कोहली ने बताया कि भारतीय नौसेना शीघ्र ही पनडुब्बिएं प्राप्त कर लेगी, परन्तु उन्होंने कोई संख्या नहीं बताई थी ।

(ख) जी नहीं; परन्तु यह बात, कि भारत शीघ्र ही पनडुब्बिएं प्राप्त करेगा गुप्त रहस्य

नहीं है, क्योंकि यह सूचना कई प्रश्नों के उत्तर में संसद् को दी जा चुकी है। 13 नवम्बर 1967 को ही सब से पहले सभा को सूचित किया गया था, कि पनडुब्बिएं प्राप्त करने के लिए पग उठाए गए हैं।

(ग) और (घ) जब तक कि ऐसा करने के लिए अधिकृत न किया जाए वर्गीकृत किस्म की सूचना प्रकट करने के लिए, रक्षा सेना के किसी अफसर पर अभियोग चलाया जा सकता है, और उसे संगत सेवा अधिनियम के अधीन कोर्ट मार्शल द्वारा दंड दिया जा सकता है।

दूतावास के कर्मचारियों द्वारा शराब की बिक्री

1417. **श्री नम्बियार :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री प० गोपालन :
श्री उमानाथ :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विदेशी दूतावासों के कुछ कर्मचारी बाहर के लोगों को प्रति दिन शराब बेच रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

धारवाड़ और गुलबर्ग रेडियो स्टेशनों से उर्दू कार्यक्रम रिले किये जाना

1418. **श्री मोहसिन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व बम्बई-कर्नाटक और हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्रों में उर्दू बोलने वाले लोगों की काफी प्रतिशतता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि धारवाड़ और गुलबर्ग रेडियो स्टेशनों से इस समय उर्दू के कोई भी कार्यक्रम रिले नहीं किये जाते; और

(ग) गुलबर्ग और धारवाड़ रेडियो स्टेशनों से उर्दू के कार्यक्रय रिले करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं ; अधिक प्रतिशतता नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) विविध-भारती के उर्दू के सभी कार्यक्रमों को रिले करने के अतिरिक्त धारवाड़ और गुलबर्ग केन्द्र उर्दू के कुछ अपने कार्यक्रम भी प्रसारित करते हैं। इन प्रसारणों और कार्यक्रमों के रिले करने के अलावा मैसूर राज्य के श्रोता दिल्ली के शक्तिशाली ट्रांसमीटरों से प्रतिदिन प्रसारित होने वाले उर्दू मजलिस के कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं।

Linguistic Knowledge of India's Trade Representatives

1419. **Shri Maharaj Singh Bharati : Shri Ram Sewak Yadav : Shri Inder J . Malhotra :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that our trade representatives in other countries do not know any other language except English, as a result of which our trade in all the countries whose language is not English is not increasing ;

(b) if so, the remedial measures being taken by Government in this respect; and

(c) the number of the said representatives knowing the language of the respective non-English speaking countries and the number of those who do not know such languages ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) No, Sir. Some of our Trade Representatives though not all, do know the language of the country in which they are functioning.Besides English, ourTrade Representatives are required to know one or more foreign languages. In any case, it is wrong to think that the country's trade depends only on the linguistic proficiency of her Trade Representatives.

(b) Does not arise.

(c) Out of 34 Indian Trade Representatives in non-English speaking countries, 7 know the local language while of the rest some know one or two other foreign languages besides English.

Manufacture of Defence Articles

1420. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the number of defence articles out of 20,000 articles, the samples of which have been diplayed in the sample room set up at Delhi, for the manufacture of which the manufacturing enterprises have given an undertaking ;

(b) whether Government have started utilising the services of such enterprises ;

(c) if so, the progress made in this regard so far ; and

(d) whether the industrialists have manufactured any articles according to the samples so far and supplied them to Goverment on small profits ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) :

(a) Out of about 18,000 items, 4272 have been taken up for manufacture by private firms, public sector undertakings and EME workshops.

(b) and(c) Yes, supplies in respect of over 1300 items of the value of approximately s. 1 crore have so far materialised.

(d) The items manufactured conform to the drawings/specifications as per the Defence requirements. The prices at which most of the orders have been executed compare favourably with the imported prices.

Circulation Figures of Newspapers

1421. **Shri Maharaj Singh Bharati**: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of newspapers in whose case the circulation figures were found fabricated during Newspapers Circulation Enquiry Drive in 1966 and the extent to which the figures were exaggerated in each case ; and

(b) the number of newspapers published from Meerut showing fabricated figures of circulation and the action taken by Government against them ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) :

(a) During 1966, circulation was found to be exaggerated in respect of 234 newspapers. The details of these cases are given in Statements I and II appended to Chapter XII of "Press in India", 1967, Part I, a copy of which was laid on the Table of the Lok Sabha on 7-8-1967.

(b) Discrepancies in circulation were noticed in the case of 13 newspapers published from Meerut. Where an excess quota of newsprint had been allocated, it was adjusted.

Of the 13 papers, only one, a Hindi daily, was being used by the Directorate of Advertising and Visual Publicity for Central Government advertisements. After the scrutiny by the Registrar of Newspapers, its use was suspended since its circulation was below 1,000 copies, the minimum required for inclusion in the Directorate's media list.

गोपालपुर क्षेत्र (उड़ीसा) में परमाणु सामग्री का सर्वेक्षण

1422. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उड़ीसा में गोपालपुर क्षेत्र में परमाणु सामग्री का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) क्या उड़ीसा में पाई गई परमाणु सामग्री को काम में लाने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) और (ख) 1962-63 में किये गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की समुद्र तटीय रेत में मोनाजाइट, इल्मेनाइट, रयुटाइल तथा जिरकान पाये गए ।

(ग) उड़ीसा के समुद्र तट का सुनियोजित सर्वेक्षण जारी है तथा वहां प्राप्त परमाणु धातुओं को काम में लाने की कार्यवाही सर्वेक्षण के परिणामों का मूल्यांकन पूरा होने पर की जायेगी ।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीविजन का विस्तार

1423. **श्री सीताराम केसरी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीणों को खेती के अधुनिक तरीकों की जानकारी देने तथा शिक्षा का प्रसार करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीविजन सेटों के विस्तार की कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस समय देश में सामुदायिक टेलीविजन सेटों की संख्या कितनी है और इससे कितनी जनता लाभान्वित होती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) और (ख) जी, हां । विस्तार के पहले चरण में दिल्ली के टेलीविजन केन्द्र का विस्तार करने के अतिरिक्त, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था है । ये केन्द्र नगरों में कार्यक्रम देने के अतिरिक्त, अपने इर्द गिर्द के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्यक्रम देंगे ।

(ग) 217 सामुदायिक टेलीविजन सेट टेली-क्लबों में लगे हुए हैं तथा 80 और टेलीविजन दिल्ली में ग्रामीण दर्शकों के लिए लगे हुए हैं । हाल के सर्वेक्षण से पता चलता है कि टेली-क्लबों के दर्शकों की संख्या 20,000 से 25,000 प्रति कार्यक्रम थी । कृषकों के लिए कार्यक्रम को लगभग 16,000 व्यक्ति देखते हैं । इसके अतिरिक्त 548 सेट स्कूलों में लगे हुए हैं जिनसे भौतिक और रसायन विज्ञान के 36,000 विद्यार्थियों को और सामान्य विज्ञान और अंग्रेजी के 96,000 विद्यार्थियों को लाभ हो रहा है ।

दिल्ली क्षेत्र में 5212 घरेलू टेलीविजन लाइसेंस हैं । अन्य क्षेत्रों में सामुदायिक टेलीविजन सेट नहीं है । इन सेटों पर दर्शकों की संख्या, प्रति सेट 10 दर्शकों के अनुमान से, 52,120 होगी ।

टलीविजन सेट लगना

1424. श्री सीताराम केसरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीविजन कार्यक्रम से सीमित संख्या में ही लोग लाभ उठाते हैं, जिनमें अधिकतर वे लोग होते हैं जो अच्छे खाते पीते लोग हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आगामी वर्ष में टेलीविजन सेटों के संधारण व्यय में कमी करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं । दिल्ली में टेलीविजन के कार्यक्रम मुख्यतः सामाजिक शिक्षा, कृषि के उन्नत तरीकों की शिक्षा, परिवार नियोजन आदि तथा स्कूलों में शिक्षण में, विशेष रूप से विज्ञान के क्षेत्र में, सहायता करने के लिये होते हैं । मनोरंजन सम्बन्धी कार्यक्रम उसी सीमा तक सम्मिलित किये जाते हैं जिससे श्रोताओं की दिलचस्पी बनी रहे और उनके द्वारा वे शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकें । आकाशवाणी श्रोता अनुसन्धान के अनुसार भी दर्शकों में अधिकांश संख्या विद्यार्थियों, किसानों और मध्य आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की होती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Setting up of a Radio Station in Kotah Divison, Rajasthan

1425. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a Rdaio Station in Kotah Division of Rajasthan; and

(b) if so, when ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) :

(a) No, Sir. There is no proposal at the moment.This area is being served by the Radio Stations at Indore and Ajmer.

(b) Does not arise.

हिन्दी फिल्में

1426. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत अक्तूबर में उनके मंत्रालय ने फिल्म निर्माताओं के संगठन को सुझाव दिया था कि हिन्दी फिल्मों के नाम देवनागरी और केवल देवनागरी में होने चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो किन प्रयोजन से यह सुझाव दिया गया था ; और

(ग) इसी बारे में फिल्म निर्माताओं की क्या प्रतिक्रिया थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) जी, हां । भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार का यह सुझाव कि हिन्दी फिल्मों के नाम देवनागरी में दिये जायें, फिल्म उद्योग के ध्यान में लाया गया था । यह फिल्म उद्योग पर निर्भर था कि वह जैसा उचित समझे वैसा निर्णय ले ।

(ग) कुछ फिल्म लेखकों ने इसका स्वागत नहीं किया ।

ईरान में भारतीय फिल्में

1427. **श्री राम चरन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में बनाई गई भारतीय फिल्में ईरान, अफगानिस्तान और अरब देशों में बिल्कुल पसन्द नहीं की जाती हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विदेशों में बनाई गई फिल्मों की तुलना में भारत में बनाई गई फिल्मों से विदेशी मुद्रा अधिक प्राप्त होती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विदेशों में भारतीय फिल्मों की शूटिंग करने पर प्रतिबन्ध लगाने तथा इस कार्य के लिये विदेशी मुद्रा न देने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह)

(क) जी, नहीं ।

(ख) नियम के तौर पर नहीं ।

(ग) अभी वर्तमान नीति में परिर्वतन करने का कोई विचार नहीं है ।

पाकिस्तान से प्रतिनिधिमंडल

1428. श्री राम चरन : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान से कितने सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रतिनिधिमंडल दिसम्बर, 1967 से लेकर जनवरी, 1968 तक की अवधि में भारत आये ; और

(ख) इन प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य कौन-कौन थे और उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था ?

प्रधान मंत्री, अणु–शक्ति मंत्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक–कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 174/68]

गणतंत्र दिवस समारोह के लिये नियंत्रण-पत्र

1429. श्री राम चरन : श्री लखमण लाल कपूर :
श्री हरदयाल देवगुण : श्री विक्रम चंद महाजन :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के लिये गणतंत्र दिवस समारोह के लिये निमंत्रण पत्र भेजने की कसौटी क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रत्येक संसद् सदस्य को केवल पांच सीटें ही दी जाती हैं, जब कि वरिष्ठ अधिकारियों के घरेलू नौकरों तक को आपस में बांटने के लिये काफी कार्ड मिल जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या निमंत्रण-पत्रों को जारी करने की समूची प्रक्रिया का पुन–विलोकन करने का सरकार का विचार है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) और (ख) इस वर्ष, गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिये केन्द्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों, राज्यमंत्रियों, उपमंत्रियों, संसद् के सदस्यों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, योजना आयोग के सदस्यों, राजनयिकों, दिल्ली महानगर परिषद् के सदस्यों तथा दिल्ली नगर निगम के सदस्यों आदि–आदि को निमंत्रण पत्र दिए गये । जहां तक भारत सरकार के असैनिक अधिकारियों का सम्बन्ध है निमंत्रण पत्र उनको दिए गये थे जिनका अधिकतम वेतन मान 1250 रुपये से कम नहीं था और वास्तविक वेतन 26 जनवरी, 1968 को 900 रुपये मासिक से कम नहीं था, सैन्य बलों में से मेजर और इसके समकक्ष से नीचे के सभी अधि–कारियों तथा कैप्टन और इसके नीचे के तथा इसके समकक्ष के अधिकारियों में से 50% को आमंत्रित किया गया, जहाँ तक दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों का सम्बन्ध है निमंत्रण-पत्र उन सब अधिकारियों को दिए गये थे जिनका अधिकतम वेतन मान 850 रुपये से कम नहीं

था और वास्तविक वेतन 600 रुपये मासिक से कम नहीं था। सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों में से केवल उनको निमंत्रण-पत्र दिए गये थे जिनका अधिकतम वेतन मान 1400 रुपये से कम नहीं था और वास्तविक वेतन 1100 रुपये मासिक से न्यून न था। कर्मचारी परिषदों और मान्यता प्राप्त कर्मचारी संस्थाओं के पदधारियों को भी निमंत्रण-पत्र दिए गये थे।

जहां तक गैर-सरकारी व्यक्तियों का सम्बन्ध है, उपलब्ध स्थानों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न श्रेणियों के अधिक से अधिक व्यक्तियों को निमंत्रण-पत्र देने का उद्देश्य था। प्राथमिकता उन लोगों को दी गयी जो विदेशों से या दिल्ली के बाहर से आने वाले थे। दिल्ली में स्थायी रूप से रहने वाले व्यक्तियों को दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गयी सूची के आधार पर निमंत्रण-पत्र दिए गये। मंत्रियों, संसद् सदस्यों तथा अधिकारियों आदि द्वारा अपने सम्बन्धियों तथा अतिथियों के लिए निमन्त्रण पत्रों के लिए की गयी निवेदनों पर योग्यता के आधार पर जांच की गयी और उपलब्ध स्थानों के आधार पर निमन्त्रण-पत्र दिए गये। संसद सदस्यों को चार-चार स्थान दिए गये। फिर भी, संसद् सदस्यों को मुख्यतः अनुरोध करने पर उनके सम्बन्धियों तथा विधान-सभा-सदस्य जैसे अन्य व्यक्तियों के लिए अधिक निमन्त्रण पत्र दे दिए गये। सामान्यतः अधिकारियों के घरेलू नौकरों के लिए निमन्त्रण पत्र नहीं दिये जाते हैं।

(ग) गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आमन्त्रित व्यक्तियों को निमन्त्रण पत्र देने की जो व्यवस्था है उस पर प्रति वर्ष विचार किया जाता है और जहां आवश्यकता होती है उसमें परिवर्तन भी कर दिए जाते हैं।

भारत-पूर्व पाकिस्तान सीमा का सीमांकन

1430. **श्री राम चरण :** **श्री लखन लाल कपूर :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 75 मील लम्बी मुर्शिदाबाद- राजशाही सीमा के साथ मौसमी सीमांकन के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच कलकत्ता में 14 जनवरी, 1968 को एक औपचारिक करार हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो करार का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) और (ख) मुर्शिदाबाद-राजशाही सेक्टर में भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा करीब 78 मील की लम्बाई तक नदीतट की है। हर वर्ष बरसात के मौसम के बाद जगह-जगह कुछ चर-भूमि निकल आती है जिसकी वजह से कभी-कभी सीमा पर वारदातें भी हो गई हैं क्योंकि उनकी मिल्कयत के बारे में शक पैदा हो जाता है। इन वारदातों को रोकने

के लिए मौसमी सीमांकन का तरीका निकाला गया था और हर साल इस प्रकार सीमांकन किया जाता है।

तदनुसार, ढाका में 25 और 26 सितंबर, 1967 को पश्चिमी-बंगाल और पूर्व पाकिस्तान के भू-अभिलेख और सर्वेक्षण निदेशकों का जो सम्मेलन हुआ था, उसके निर्णयों के अनुरूप मुर्शिदाबाद-राजशाही सेक्टर के मौसमी सीमांकन का क्षेत्र-कार्य 16 नवम्बर, 1967 को शुरू किया गया था। क्षेत्रकार्य पूरा होने पर दोनों ओर के अधिकारियों ने 15/17 जनवरी, 1968 को स्थालाकृति कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए।

Projects in Uttar Pradesh, West Bengal and Madras

1431. **Shri Ram Charan** : Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7070 on the 27th July, 1967 and state:

(a) the reasons for which more projects have been set up in West Bengal and Madras irrespective of the fact that Uttar Pradesh has larger population and is industrially backward ;

(b) the total outlay involved in six projects in West Bengal and Madras ;

(c) whether Government propose to give additional assistance to UttarPradesh during 1967-68 with a view to make up this deficiency ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs : (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) The location of industrial projects is decided primarily on the basis of techno-economic considerations. Within this limitation the special needs of comparatively backward regions are kept in view.

(b) The investment on the 6 industrial projects in West Bengal and 5 industrial projects in Madras is approximately estimated at Rs.138 crores and Rs.94 crores respectively during the Third Plan period.

(c) and (d) : As the annual provision is related to the requirement of each project, the question of providing additional assistance to any particular State does not arise.

Pak Balloon in Ferozepur

1432. **Shri Shiv Kumar Shastri:** **Shri Y. S. Kushwah:**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a gas balloon of Pakistan came down in Pandit Colony in Ferozepur on the 22nd January, 1968 ;

(b) whether it is a fact that slogans like Pakistan Zindabad etc. were marked on this balloon ;

(c) whether the Government have made any enquiries in this connection ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Prime Miniser, Minister of Atomic Engery, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) and (b) A balloon filled with gas and bearing the inscription of "Pakistan Zindabad" etc., landed in the Post and Telegraph Colony in Ferozepur on the evening of January 21, 1968.

(c) an (d): Enquiries made by the Government of India reveal that the balloon had drifted into our territory due to the direction of the wind.

बिहार योजना

1433. श्री दीवीकन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार सरकार को सूचित किया था कि वह राज्य की 1968-69 की वार्षिक योजना को 75 करोड़ रुपये की राशि से घटाकर 52 करोड़ रुपये की कर दे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि केन्द्र ने कहा है कि वह केवल 48 करोड़ रुपये अथवा राज्य की योजना में अपना अंश ही दे सकेगा ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि बिहार सरकार ने योजना के आकार में परिवर्तन न किये जाने की मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या बिहार सरकार ने संख्या के आधार पर केन्द्रीय सहायता की राशि में वृद्धि की जाने के लिये सरकार से प्रार्थना की है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) राज्य की 1968-69 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप देने के बारे में अभी योजना आयोग तथा राज्य के मुख्य मंत्री के मध्य विचार-विनिमय नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) वर्तमान स्थिति में ये प्रश्न नहीं उठते।

The 'Untold Story' by Lt. Gen. Kaul

1434. **Shri R. S. Vidyarthi :** **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Kanwar Lal Gupta: **Shri Gadilingan Gowd:**

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to reply given to Unstarred Question No. 31on the13th November,1967and state the reasons for which Government did not take any action against General Kaul for writing the book "Untold Story",although the Ministry of Law had made a recommendation to that effect?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh):

The examination of the book, carried out in consultation with Ministry of Law, indicated that some information of a classified nature has been disclosed in the book.However, because of the considerable changes made sine1962 in our operational planning, methods of warfare, logistical and other administrative arrangements, the disclosures not unoften in-accurate and imcomplete, do not have the same importance or security value today. Government have, therefore, taken the view that on the whole no advantage is to be gained by proceeding against the author and in fact some harm may be done to public interest.

राष्ट्रपति टीटो के आगमन पर आकाशवाणी से "आंखों देखा हाल" का प्रसारण

1435. श्री विश्वनाथन : श्री यशपाल सिंह :
श्री सेझियान :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी ने पालम हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति टीटो और प्रधान मंत्री श्री कोसीगिन के आगमन पर "आंखों देखा हाल" का प्रसारण केवल हिन्दी में किया था ; और

(ख) यदि हां, तो "आंखों देखा हाल" का प्रसारण अंग्रेजी में न किये जाने के क्या कारण हैं, जैसा कि सामान्यतया पहले किया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) राष्ट्रपति टीटो और प्रधान मंत्री कोसीगिन के पालम हवाई अड्डे पर आगमन का आंखों देखा हाल स्थानीय प्रसारणों के रूप में आकाशवाणी दिल्ली से हिन्दी में प्रसारित किया गया था । बाद में उनके आगमन सम्बन्धी विशेष समाचार-चित्र अंग्रेजी में सायंकाल को, जब सारे देश में कार्यक्रम देने के लिए अतिरिक्त ट्रांसमीटर उपलब्ध थे, प्रसारित किए गए थे ।

(ख) ऐसी कोई निश्चित प्रथा नहीं है कि विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के आगमन का आंखों देखा हाल अंग्रेजी में प्रसारित किया जाए । पालम हवाई अड्डे पर विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के आगमन का आंखों देखा हाल प्रसारित करना अनेक बातों पर निर्भर करता है जैसे आगमन का समय, उन चैनलों और ट्रांसमीटरों का उपलब्ध होना जिन पर प्रसारण किया जा सकता है। क्योंकि प्रधान मंत्री कोसीगिन के आगमन के समय अंग्रेजी में अन्य चैनल उपलब्ध नहीं थे, अतः उनके आगमन पर आंखों देखा हाल स्थानीय प्रसारण के रूप में हिन्दी में प्रसारित किया गया ।

वी० ई० एल० कम्पनी में रेडियो के पुर्जों का निर्माण

1436. श्री वेदव्रत बरुआ : श्री य० अ० प्रसाद :
श्री रा० रा० सिंह देव : श्री धीरेन्द्रनाथ देव ।

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वी० ई० एल० कम्पनी इस उद्देश्य से रेडियों के सस्ते पुर्जे बना रही है कि देश में अधिक संख्या में रेडियो बनाये जा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो 1968-69 के लिये कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):

(क) भारत एलेक्ट्रानिक्स लिमिटिड वेल्वों और ट्रांजिस्टरों तथा डायोड्ज का निर्माण कर रहे हैं, जो रेडियो रिसीवरों के निर्माण में इस्तेमाल होते हैं । जनवरी, 1968 से उन्होंने ट्रांजिस्टरों और डायोड्ज के मूल्य लगभग 10 प्रतिशत कम कर दिए हैं । रिसीवरों के निर्माताओं ने ऐसा वचन दिया है कि कीमतों में इस कमी का लाभ ग्राहक को दिया जाएगा । इसलिए इससे रेडियों सेटों के मूल्य में कमी करने में सहायता मिलेगी ।

(ख) 1968-69 वर्ष के लिए इन संघटकों के लिए भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटिड के उत्पादन लक्ष्य हैं :—

(1) वेल्व 50 लाख की संख्या में ।

(2) ट्रांजिस्टर और
डायोड्ज 120 लाख की संख्या में ।

मसानी समिति

1437. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के आर्टिस्टों से सम्बन्धित मसानी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) क्या कर्मचारियों के कुछ प्रतिनिधियों को विचार-विमर्श तथा साक्ष्य के लिये बुलाया गया था ;

(ग) क्या कुछ प्रतिनिधियों ने अपनाई गई प्रक्रिया पर आपत्ति की थी; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों द्वारा बनाई गई दो यूनियनों को अभी सरकारी मान्यता नहीं दी गई है और उनके प्रतिनिधियों को निमन्त्रित करने का प्रश्न नहीं उठता । कुछ स्टाफ आर्टिस्टों को अध्ययन दल से व्यक्तिगत आधार पर मिलने के लिये निमंत्रित किया गया था । सभी बैठक में आये थे परन्तु उनमें से तीन, जो एक यूनियन से सम्बन्ध रखते थे, इस आधार पर कि अध्ययन दल को स्टाफ आर्टिस्टों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत न करके, ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों से बात-चीत करनी चाहिए, उठकर चले गये । उनका सुझाव स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि दोनों में से कोई भी यूनियन अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं है ।

चीनियों द्वारा नेपाल में सड़क का निर्माण

1438. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : **श्री लीलाधर कटकी** :
श्री श्रीगोपालन साबू :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि ल्हासा-काठमांडू सड़क (कोडारी राजमार्ग) के बन जाने के बाद नेपाल में चीनियों द्वारा एक अन्य सड़क कोडारी से जनकपुरी तक, जो कि भारतीय सीमा से केवल 14 मील पर है, बनाई जा रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि चीन की सीमा से भारत की सीमा तक इस सड़क की दूरी केवल 64 मील के लगभग है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) चीन की सहायता से नेपाल में जो सड़क बनाई गई है वह काठमांडू को नेपाली सीमावर्ती गांव कोडारी से मिलाती है जो कि तिब्बत के साथ लगने वाली सीमा पर स्थित है ।

(ख) और (ग) भारत सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि चीनी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत जनकपुर को जाने वाली या उसके पास कोई सड़क बनाने की योजना है जोकि दक्षिणवर्ती नगर है। जनकपुर होकर जाने वाली एक पूर्व-पश्चिम सड़क भारतीय सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाई जा रही है।

बिहार में नये रेडियो स्टेशन

1439. **श्री बेणीशंकर शर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेडियो स्टेशनों की राज्य-वार संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं और उनमें प्रत्येक पर प्रतिवर्ष कितना व्यय होता है ;

(ख) गत दो सूखों के दौरान बिहार में कितने नये रेडियो स्टेशन चालू किये गये, उन पर कितनी पूंजी लगाई गई और उनका वार्षिक आवर्त्तक व्यय कितना होता है ; और

(ग) बिहार में रेडियो स्टेशनों में नियुक्त आर्टिस्टों तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उनको वेतन अथवा उपलब्धियों के रूप में कितनी राशि दी जाती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) एक विवरण (अंग्रेजी में) सदन की मेज पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 175/68]

(ख) बिहार में भागलपुर में मार्च, 1967 में 15 लाख रूपए के पूंजीगत व्यय से एक प्रसारण-केन्द्र चालू किया गया था। 1967–68 के दौरान इस केन्द्र पर लगभग 2.17 लाख रुपए आवर्त्ती-व्यय होने का अनुमान है।

(ग) बिहार के तीन प्रसारण-केन्द्रों अर्थात पटना, रांची और भागलपुर में 331 स्टाफ आर्टिस्ट और नियमित कर्मचारी काम कर रहे हैं। 1967–68 में उनके वेतनों और भत्तों पर कुल 13.7 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

अजीज ओलोग जेड का रक्षात्मक अभिरक्षण

1440. **श्री कु० मा० कौशिक :** श्री नायनार।

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा रूसी युवक अजीज ओलोग जेड को दिये गये रक्षात्मक अभिरक्षण का अभिप्राय क्या है ;

(ख) उसे इस प्रकार का संरक्षण देने की क्या आवश्यकता थी ; और

(ग) क्या पहले भी किसी व्यक्ति को ऐसा अभिरक्षण दिया गया था और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)

(क) और (ख) 'रक्षात्मक अभिरक्षण' कोई पारिभाषिक शब्द नहीं है। जहां तक रूसी

नौजवान अजीज ओलोग जेड का संबंध है, फारेनर्स एक्ट 1946 की धारा 3 के अन्तर्गत एक आदेश जारी किया गया था जिसमें उससे कहा गया था कि वह नामांकित जगह पर रहे, उसके आने-जाने और अन्य लोगों से मिलने-जुलने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया और उससे कह दिया गया कि वह भारत सरकार द्वारा नामांकित अधिकारियों की अनुमति के बगैर भारत छोड़कर न जाए । ये प्रतिबन्ध उसकी अपनी सुरक्षा के हित में लगाए गए थे । उसे न तो गिरफ्तार किया गया था और न नजरबन्दी निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत उसे नजरबन्द किया गया ।

(ग) विगत समय में ऐसा कोई और मामला हुआ मालूम नहीं होता ।

परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना

1441. **श्री समर गुह** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के बारे में अमरीका-रूस के बीच हुए समझौते में सम्मिलित इस उपबन्ध की ओर ध्यान दिया है, जिसमें गैर-परमाणु शक्तियों को परमाणु इंजीनियरिंग के लिए खंडनीय सामग्री सप्लाई करना स्वीकार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारत में परमाणु इंजीनियरिंग तथा अन्य प्रयोजनों के लिये आयातित अथवा स्वदेशी खण्डनीय सामग्री का प्रयोग करने का है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री; योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) अट्ठारह राष्ट्रों की निरस्त्रीकरण समिति में अमरीका और सोवियत संघ ने 18 जनवरी, 1968 को एटमी हथियारों का विस्तार न करने के विषय पर संधि का जो संशोधित मसौदा पेश किया था, उसमें यह कहा गया है कि आणविक विस्फोटों के शांतिपूर्ण उपयोगों से उत्पन्न होने वाले ठोस लाभ समुचित अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं के द्वारा अथवा विशेष करारों के परिणामस्वरूप द्विपक्षीय आधार पर ऐसे गैर-एटमी हथियार वाले राज्यों को सुलभ कराए जाएंगे जो संधि के पक्षधर हैं ।

(ख) एटमी विस्फोटक हथियारों के शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए सरकार के पास आजकल कोई योजनाएं नही हैं लेकिन बिजली उत्पादन और अनुसंधान के लिए विस्फोटक सामग्री का उपयोग किया जाता है ।

भारत तथा श्रीलंका के प्रधान मंत्रियों की बैठक

1442. **श्री सम्बन्धन** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या राज्यहीन व्यक्तियों के सम्बन्ध में भारत तथा श्रीलंका के बीच हुए समझौते में परिवर्तन करने तथा श्रीलंका के बागानों में मजदूरों की वर्तमान स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिये भारत तथा श्रीलंका के प्रधान मंत्रियों की एक बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चंडीगढ़ में डिफेंस कालोनी

1443. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ में कोई डिफेंस कालोनी बनाई गई है और यदि हां, तो भूतपूर्व सैनिकों के कितने परिवारों को वहां बसाये जाने की संभावना है ;

(ख) क्या देश के अन्य स्थानों में भी इसी तरह की डिफेंस कालोनियां बनाई गई हैं ; और

(ग) भूतपूर्व सैनिकों को भारत सरकार ने और क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की हैं?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी हां, लगभग 2400 कुटुम्ब ।

(ख) जी हां । ऐसी कालोनिएं देहरादून और गोवा में भी स्थापित की गई हैं । जभी सरकार द्वारा अलाट भूमि भवन निर्माण समिति दिल्ली को प्राप्त हुई, दो और कालोनिएं पीतमपुर और नरेला में भी स्थापित की जाएंगी ।

(ग) राज्य सरकारों की मार्फत प्राप्त की गई विकसित भूमि रक्षा सेविवर्ग को, अकेले-अकेले या इस उद्देश्य के लिए बनाई गई सहकारी समितियों के सदस्यों के तौर पर बिना हानि या लाभ के आधार पर अलाट की जाती है। उसके पश्चात् भवनों का निर्माण अलाटियों द्वारा किया जाएगा । इस संबंध में और कोई सुविधाएं देना इस समय प्रस्तावित नहीं है ।

रूसी समाचार एजेंसी 'नोवोस्ती' के प्रेस प्रतिनिधि

1444. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** । **श्री काशीनाथ पाण्डेय**।

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि श्री सिमोनोव को रूसी समाचार एजेंसी 'नोवोस्ती' के प्रेस संवाददाता के रूप में भारत सरकार द्वारा अधिकृत रूप से मान्यता दी गई है ;

(ख) क्या श्री सिमोनोव को अपनी गाड़ी के लिये डिप्लोमैटिक नम्बर प्लेट प्राप्त करने की अनुमति दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने 'नोवोस्ती' को रूसी सरकार का अधिकृत अधिकारी स्वीकार कर लिया है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसे डिप्लोमैटिक प्लेट दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या अन्य विदेशी पत्रकारों को भी ऐसी डिप्लोमैटिक मोटर लाइसेंस प्लेटें दी गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

(ङ) जी, नहीं ।

भारतीय वायुसेना के विमान

1445. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारी वायु सेना के 90 प्रतिशत से अधिक विमान विदेशों में बने हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय वायु सेना के लिये अपेक्षित विमानों की हमारी आवश्यकता के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) आई० ए० एफ० में विदेशी विमानों को देशीय विमानों द्वारा बदलने का काम एक लम्बे अर्से की प्रक्रिया है । देश में विमानों का विकास और उत्पादन प्राप्य संसाधनों के अन्तर्गत प्रगतिशील है ।

उत्तर प्रदेश के लिए योजना सम्बन्धी नियतन

1446. श्री चेंगलराया नायडू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने चौथी योजना के चालू वित्तीय वर्ष के लिये केन्द्रीय नियतन के मामले में केन्द्र द्वारा किये गये भेदभाव के विरुद्ध एक कड़ा विरोध-पत्र भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहा है कि इस कटौती के कारण उसे कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को छोड़ना पड़ेगा ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार कुछ और धनराशि नियत करने के बारे में सोच रही है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री, तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी, : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

मध्य प्रदेश को सस्ते रेडियो सेटों की सप्लाई

1447. श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968 में सस्ते रेडियो सेट सप्लाई करके मध्य प्रदेश के ग्रामों तथा नगरों में आकाशवाणी के कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने की कोई योजना विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) और (ख) सारे भारत के लिए अधिक उपज के कार्यक्रमों के अन्तर्गत, रायपुर के सहायक केन्द्र में स्थित आकाशवाणी की सघन फार्म और गृह प्रसारण यूनिट द्वारा जिन जिलों अर्थात् रायपुर और दुर्ग में कार्यक्रम दिए जाते हैं, उनके ग्राम सेवकों को 700 सस्ते रेडियो सेट देने का एक प्रस्ताव है। ग्राम सेवक इन सेटों का उपयोग छोटे-छोटे समूहों को कृषि कार्यक्रम सुनाने के लिए करेंगे।

सिक्किम में भारत का राजनैतिक कार्यालय

1448. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जनवरी, 1968 को 'इण्डियन एक्सप्रेस' समाचारपत्र में "सिक्किम के साथ अधिक निकट का सम्पर्क" (क्लोजर कांटेक्ट विद् सिक्किम) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : भारत सरकार ने 29 जनवरी, 1968 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित श्री रंजन गुप्ता द्वारा गंगतोक से 28 जनवरी, 1968 को प्रेषित रिपोर्ट देखी है।

(ख) इस रिपोर्ट में अत्यंत साधारण तरीके से यह मत व्यक्त किया गया है कि सिक्किम-स्थित भारत के राजनीतिक कार्यालय और सिक्किम के लोगों के बीच कोई निकट संपर्क नहीं है। मत तथ्यों पर आधारित नहीं है।

राजस्थान में प्रेषण (ट्रांसमिशन) प्रणाली

1449. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में प्रेषण प्रणाली बहुत कमजोर है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके कब तक ठीक हो जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) और (ख) प्रसारण के विकास में प्रथमिकता सामान्यतः घनी जन संख्या वाले क्षेत्रों को दी जाती है ताकि अधिक से अधिक लोग कार्यक्रम सुन सकें। राजस्थान एक बिखरी हुई जन संख्या वाला प्रदेश है, अतः घनी जन संख्या वाले प्रदेशों की अपेक्षा इसका प्रसारण-क्षेत्र कुछ कम हैं। पहले से ही चालू योजनाओं के पूरा हो जाने पर राजस्थान के 50 प्रतिशत से कुछ अधिक क्षेत्र में कार्यक्रम सुने जा सकेंगे जबकि तृतीय पंचवार्षीय योजना के अंत तक अखिल भारतीय औसत 52 प्रतिशत थी।

नाथूला में चीनियों का प्रचार

1450. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाथूला में चीनियों द्वारा लाउड स्पीकरों के द्वारा किये जाने वाला प्रचार हिन्दी भाषा में किया जा रहा है ;

(ख) क्या हमारी ओर से प्रतिरोधी प्रसारण चीनी भाषा में किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो हमारी प्रसारण संबंधी सामग्री का चयन किस प्रकार होता है और ये प्रसारण किस प्रकार तैयार किये जाते हैं और किसके द्वारा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) प्रतिरोधी-प्रसारणों की सामग्री केन्द्रीय रूप से तैयार की जाती है ।

भारतीय राजदूतों के रिक्त पद

1451. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने तथा किन-किन देशों में भारतीय राजदूतों के पद इस समय रिक्त हैं ;

(ख) प्रत्येक पद कितनी अवधि से रिक्त पड़ा हैं और उसके क्या कारण है ; और

(ग) इन पर कब तक और किनकी नियुक्तियां करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) से (ग) विदेशों में भारतीय मिशन प्रमुखों के 7 पद हैं जो आजकल खाली हैं। इनमें से तीन शीघ्र ही भर दिए जाएंगे। बाकी चार पर नियुक्तियां करने पर विचार हो रहा है। ये सभी रिक्तियां सामान्य स्थानांतरण और सेवानिवृत्तियों के कारण हुई हैं। शेष विवरण ब्यौर में दे दिया गया है जो नीचे रखा है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 176/68]

सैनिक भूमि तथा छावनी सेवा

1452. श्री निहाल सिंह : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनका पिछले 6–7 वर्षों से सैनिक भूमि तथा छावनी सेवा में नियुक्ति के बाद अभी तक पुलिस सत्यापन तथा डाक्टरी परीक्षा नहीं की गई है जिसके कारण उन्हें न तो अर्ध स्थायी/स्थायी ही घोषित किया जा सका है और न ही पदोन्नति के अवसर मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

Purchase of Tungsten Metal

1453. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 136 on the 20th November, 1967 and state :

(a) whether the information regarding the purchase of Tungsten metal has since been collected ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is attached. [**Placed in Library. See No. LT—177/68**

Indians Under Detention in Foreign Countries

1454. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1056 on the 20th November, 1967 and state :

(a) whether the information about the Indians under detention in Burma and other countries has since been collected; and

(b) if so, the details thereof ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) Statistics of Indians under detention in Iraq, U. S. A. and U. K. are awaited.

(b) The number of Indians in foreign countries other than those mentioned above who are under detention and the reasons for detention are shown in the Statement attached. [**Placed in Library. See No. LT—178/68**) The position regarding Indians under detention in Pakistan is as stated in answer to Lok Sabha Unstarrted Question No. 64 on 13-11-1967.

सुरक्षा दल टुकड़ियों के बीच गलतफहमी के कारण गोलीबारी

1455. **श्री समर गुह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिजोलैंड में तैनात पंजाब रेजीमेंट तथा आसाम राइफल्स ने गलतफहमी में एक दूसरे पर गोलियां चलाई थीं जिसके परिणामस्वरूप दोनों ओर बहुत से व्यक्ति हताहत हो गये थे ;

(ख) क्या इसी प्रकार कुछ समय पहले मिजोलैंड में व्याप्त स्थिति पर काबू पाने के लिये तैनात सैनिकों अथवा पुलिसमैनों की अपनी ही टुकड़ियों के बीच गोलियां चलाने की घटना भी घटी थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौर क्या है और ऐसी दुर्घटनाओं की जांच करने तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) :

(क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तारापुर परमाणु बिजलीघर

1456. श्री जार्ज फरनेंडीज : श्री चन्द्रशेखर सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) तारापुर परमाणु बिजलीघर कब चालू हो जायेगा ;

(ख) इसके चालू हो जाने पर इसमें कितनी बिजली पैदा होगी ;

(ग) बिजली किस दर पर बेचने का विचार है ;

(घ) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है ; और

(ङ) इस परियोजना पर कितनी लागत आयेगी ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) यह बिजलीघर सन् 1968 की अन्तिम तिमाही में चालू होगा।

(ख) 390 मैगावाट (शुद्ध)।

(ग) महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य बिजली बोर्डों को बिजली किस दर पर बेची जाये यह अभी विचाराधीन है।

(घ) ईंधन की कीमत के अलावा परियोजना पर जनवरी, 1968 के अन्त तक खर्च होने वाली धनराशि 56·85 करोड़ रुपये थी।

(ङ) ईंधन की कीमत के अलावा बिजलीघर पर 65.03 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

कोचीन नौसैनिक अड्डे के असैनिक कर्मचारी

1457. श्री विश्वनाथ मेनन : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कोचीन नौसैनिक अड्डे के असैनिक कर्मचारियों को जिनकी सेवाएं 1965 और 1966 में समाप्त कर दी गई थीं अभी तक कोई सेवा निवृत्ति लाभ जैसे उपदान, पेंशन या भविष्य निधि नहीं मिली है ; और

(ख) उन कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख) नौसेना अड्डे कोचीन के (4 स्थायी और 5 अस्थायी) 9 असैनिक कर्मचारियों की सेवाएं 1965 और 1966 के दौरान समाप्त की गई थीं। जिन स्थायी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई थीं, वह किसी पेन्शन के अधिकारी न थे। अस्थायी कर्मचारी पेन्शन, उपदान या करुणामूलक भत्ते के अधिकारी नहीं, होते उन में से एक को, उसे देय प्राविडेंट फंड की राशि अदा कर दी गई

है, दूसरे को नौसेना डॉकयार्ड कार्मिकों के प्राविडेंट फंड की देय राशिएं प्रदान कर दी गई हैं अन्य । तीन अस्थायी कर्मचारियों के मामले निरीक्षण अधीन हैं।

बर्मा तथा श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले भारतीय

1458. **श्री विश्वनाथ मेनन** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बर्मा तथा श्रीलंका से स्वदेश लौटने वालों से इस आशय का कोई अभ्यावेदन मिला है कि सरकार इसके लिए कोई उपयुक्त कार्यवाही करे कि वे लोग उन देशों के बैंकों में अपनी जमा राशि जिसे उन देशों की सरकारों ने निरुद्ध कर रखा है निकाल सकें ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान–मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना-मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) सरकार को बर्मा के प्रत्यावर्तियों से इस प्रकार के शिकायत-पत्र मिले हैं। जहां तक श्रीलंका का प्रश्न है, जो लोग भारत-श्रीलंका करार (1964) के अन्तर्गत अब तक भारत आ गये हैं, उन्हें करार की व्यवस्था के अनुसार अपनी परिसंपत्ति ले जाने की अनुमति है । हमारे हाई कमीशन से कहा गया है कि वह हमें ताजी स्थिति बताए ।

(ख) भारतीय प्रत्यावर्तियों (रिपेट्रिएट्स) ने बर्मा के बैंकों में जो आस्तियां छोड़ी हैं, उनके विषय में भी दोनों सरकारों के बीच भारतीयों की आस्तियों के मुआविजे पर बात-चीत हुई है ।

एर्णाकुलम में प्रतिरक्षा सम्बन्धी मंडप

1459. **श्री विश्वनाथ मेनन** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को कोचीन निगम की प्रदर्शन समिति से कोई प्रार्थना मिली है कि एर्णाकुलम में होने वाली प्रदर्शनी में इस वर्ष प्रतिरक्षा सम्बन्धी मंडप होना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या पिछले वर्ष हुई प्रदर्शनी में प्रतिरक्षा सम्बन्धी मंडप लगाया गया था ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) से (ग) एर्णाकुलम में 1966-67 में आयोजित की गई अखिल भारतीय कृषि तथा औद्योगिक प्रदर्शनी में एक रक्षा मंडप संगठित किया गया था । एर्णाकुलम में 1967-68 की अखिल भारत कृषि तथा औद्योगिक प्रदर्शनी में भी एक रक्षा मंडप स्थापित करने के लिये एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था । तदपि, इस तथ्य को समक्ष रखते हुये कि एर्णाकुलम और केरल के अन्य स्थानों समेत समस्त देश के विभिन्न स्थानों के भ्रमण के लिये रक्षा प्रदर्शनी रेलगाड़ियां संगठित की गई हैं, और प्राप्य संसाधनों के पहले से वचन बद्ध हो जाने के कारण, प्रार्थना-को स्वीकार करना सम्भव न हो पाया ।

रेयर अर्थ्स एल्लूर, केरल

1460. **श्री विश्वनाथ मेनन** : क्या प्रधान–मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेयर अर्थ्स एल्लूर (केरल) के विस्तार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस विस्तार कार्यक्रम के लिये कितना धन नियत करने का विचार है ; और

(ग) यह कार्य कब आरम्भ होगा और कब तक इसे पूरा करने का समय निर्धारित किया गया है ?

प्रधान मंत्री अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) से (ग) एल्लूर स्थित संयंत्र का आगे विस्तार विचाराधीन है । अनुमान है कि विस्तार योजना को पूरा करने में 60 लाख रुपये व्यय होंगे । तथापि, अब तक इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

केरल के त्रावनकोर देवास्वम बोर्ड से ज्ञापन

1461. श्री विश्वनाथ मेनन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के त्रावनकोर देवास्वम बोर्ड के अध्यक्ष से साबरीमाला तीर्थयात्रा का समाचार दर्शन (न्यूज रील) तैयार करने के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी प्रार्थना के अनुसार काम कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) :

(क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । साबरी माला तीर्थ यात्रा 2 फरवरी, 1968 को रिलीज किये गये इन्डियन न्यूज रिव्यू संख्या 1008 में दी गई थी, इसका शीर्षक था "साबरी माला की तीर्थ यात्रा" ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के लिये प्रतिनिधि मंडल

1462. श्री क० लकप्पा : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रतिनिधि मंडल भेजते समय वहां विचार-विमर्श के मार्गदर्शन के बारे में सरकार ने सभी राजनैतिक दलों के विचार प्राप्त किये हैं ।

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) जी नहीं । इस उद्देश्य के लिये सभी राजनीतिक दलों की आम

राय जानने अथवा उनसे सलाह-मशविरा करने की आवश्यकता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में हमारा प्रतिनिधिमंडल सरकार का प्रतिनिधित्व करता है।

दक्षिण कोरिया की समस्यायें

1463. श्री क० लक्कप्पा : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरिया के महावाणिज्य दूतावास द्वारा भारत सरकार को दक्षिण कोरिया की समस्याओं के बारे में बताया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो दक्षिण कोरिया की वैदेशिक तथा आन्तरिक समस्याओं के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) नई दिल्ली में कोरिया का कोई राजदूतावास नहीं है क्योंकि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के साथ सिर्फ कोंसली सम्बन्ध है। दक्षिण और उत्तर कोरिया प्रधान कोंसल समय-समय पर विभिन्न मामलों पर, खासतौर से कोरिया के पुनः एकीकरण पर, अपनी-अपनी सरकारों के विचारों से हमारी सरकार को अवगत कराते हैं।

(ख) सरकार ने उत्तर और दक्षिण कोरिया, दोनों के साथ व्यापारिक और वाणिज्यिक सम्बन्ध बढ़ाने की कोशिश की है। कोरिया के पुनः एकीकरण के प्रश्न पर सरकार का यह ख्याल है कि मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीकों से दूर करने की कोशिश की जानी चाहिये ताकि कोरिया स्वाधीन हो सके और एक हो जाये।

Films on Scientific Methods of Agriculture

1464. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether there is some proposal to prepare films for demonstration to the farmers the scientific methods of increasing production of foodgrains in the required languages so that they can understand them in their own language through films ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) and (b) The Films Division has been producing, among others instructional films demonstrating scientific methods of increasing production of foodgrains. These films are released in several language versions to suit specific areas of the Country. A statement of such films already produced and those under production is laid on the Table of the House. **(Placed in Library. See No. LT-179/68).**

दार्जिलिंग में अर्जित की गई जुर्मानों के लिये मुआवजा

1465. श्री चपलाकान्त भाट्टाचार्य : क्या प्रतिरक्षा मंत्री 20 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1085 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग के सिलीगुड़ी सबडिवीजन में सैनिक कार्यों के लिये अधिगृहीत भूमि के बारे में मुआवजे के निर्धारण का शेष कार्य अपेक्षित वित्तीय मंजूरी का देना और मुआवजे की बकाया राशि और किराये की अदायगी का काम पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दी गई राशि का ब्यौरा देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : (क) से (ग) 35 में से 28 प्रायोजनाओं के सम्बन्ध में निर्धारण वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का कार्य सम्पूर्ण हो चुका है । 6 प्रायोजनाओं का निर्धारण वित्तीय स्वीकृति के लिये निरीक्षण अधीन है, और निरीक्षण सम्पूर्ण हो जाने के पश्चात् उनकी शीघ्र ही स्वीकृति दे दी जाएगी। 640 एकड़ों को आवृत्त करने वाली शेष एक योजना के लिए निर्धारण अभी कलेक्टर द्वारा सम्पन्न नहीं किया गया ।

स्थानीय राजस्व अधिकरणों द्वारा अब तक की गई अदायगिएं लगभग 16.60 लाख रुपये की है । इसमें लगभग 13.99 लाख रुपये शेष निलम्बित 7 प्रायोजनाओं के सम्बन्ध में निर्धारण और वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने तक "उन के हिसाब में" अदा किए गए हैं ।

अदायगी के लिये अधिकारी व्यक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लेने और अदायगी करने का उत्तरदायित्व स्थानीय कलेक्टर का है । तदनुसार राज्य सरकार से प्रार्थना की गई है कि वह कलेक्टर को कहें कि जहां वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है वह शीघ्र अदायगी करे, और जहां निर्धारण नहीं हो पाया शीघ्र निर्धारण करे ।

भारत में बनी फिल्में

1466. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलयेशिया सरकार ने भारत में बनी कुछ फिल्मों के वहां दिखाये जाने पर हाल ही में रोक लगा दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मंत्रीमंडल की नई प्रतिरक्षा समिति

1467 **श्री शिवचन्द्र झा :** **श्री रामावतार :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रिमंडल की एक नई प्रतिरक्षा समिति बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं और यह क्या विशिष्ट कार्य करेगी ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में जानकारी देना लोकहित की दृष्टि से उचित नहीं है ।

सेना में वामपंथी साम्यवादियों का आ जाना

1468. श्री सु० कु० तापडिया : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सेना में वामपंथी साम्यवादी तत्वों के आ जाने का पता है ; और

(ख) क्या सरकार ने उनके सेना में बड़े पैमाने पर आ जाने और सेना में तोड़फोड़ की गतिविधियों को रोकने के लिये आवश्यक पूर्वोपाय कर लिये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) सरकार विध्वंस के सम्भावित साधनों और विध्वंस के प्रयासों पर सतर्कता से नजर से रखती है, और उन से उपयुक्त तौर पर निपटती है ।

नये प्रसारण केन्द्र

1469. श्री गाडिलिंगन गौड : श्री रा० बरुआ :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968-69 में देश में नये प्रसारण केन्द्रों की स्थापना के कोई प्रस्ताव हैं ; और

(क) यदि हां, तो ये नये केन्द्र किन शहरों में खोले जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) :

(क) और (ख) 1968-69 के दौरान निम्नलिखित प्रसारण केन्द्रों या ट्रांसमीटरों के स्थापित हो जाने की संभावना है :—

1. डिबरूगढ़ ..... नया प्रसारण केन्द्र ।
2. कलकत्ता ..... एक अति ऊंची शक्ति का मीडियम वेव ट्रांसमीटर और एक ऊंची शक्ति का ट्रांसमीटर
3. जलंधर ऊँची शक्ति का मीडियम वेव ट्रांसमीटर
4. पणजी (गोआ) मध्यम शक्ति का मीडियम वेव ट्रांसमीटर ।

व्यापारिक प्रसारण

1470. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में व्यापारिक प्रसारणों के लिये क्या दर नियत की गई है ; और

(ख) 31 दिसम्बर, 1967 तक इससे कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) :

(क) वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिए आकाशवाणी द्वारा निश्चित की गई दरें इस प्रकार हैं :—

		रविवार			सप्ताह के दिन		
	अवधि	क	ख	ग	क	ख	ग
		रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
15	सैकंड	80	50	20	50	20	15
30	सैकंड	140	90	30	90	40	30
1	मिनट	230	150	60	150	70	40
	निश्चित स्पोट				25 प्रतिशत अधिक		
	विशेष स्थिति				25 प्रतिशत अधिक		
	शनिवार (2.30 अपरान्ह से 3·30 अपरान्ह तक)				10 प्रतिशत अधिक		

अकेली स्थिति के लिए 2 मिनट प्रभार जमा 25 प्रतिशत होगा ।

क. (वह समय जब कार्यक्रमों का जोर होता है)	प्रातः 8·30 बजे से 9·30 बजे तक, 11·00 बजे से अपरान्ह 12·30 बजे तक, अपरान्ह 2·30 बजे से 3·30 तक, सायंकाल 6·45 बजे से 8·30 बजे तक, रात्रि में 9·15 बजे से 10. 35 बजे तक ।
ख. (वह समय जब कार्यक्रमों का कुछ जोर हो)	रात्रि में 8.45 बजे से 9·15 बजे तक ।
ग. (वह समय जब कार्यक्रमों का जोर न हो ।)	प्रातः 7·40 बजे से 8·15 बजे तक, 10.15 बजे से 10·55 बजे तक, अपरान्ह 2·00 बजे, से 2.30 बजे तक, 3.30 बजे से 3.45 बजे तक ।

(ख) नवम्बर और दिसम्बर, 1967 के दोनों मास में हुई कुल शुद्ध आय 6,43,849/- रुपए थी ।

बड़ौदा में रेडियो स्टेशन

1472. श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ौदा में आकाशवाणी का केन्द्र कब शुरू हुआ था ;

(ख) जब यह केन्द्र शुरू किया गया था उस समय इसका आकार क्या था ; और

(ग) केन्द्र के भवन का प्रतिमास कितना किराया दिया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) बड़ौदा का मूल रेडियो केन्द्र महाराजा बड़ौदा द्वारा जनवरी, 1947 में चालू किया गया था और वह आकाशवाणी द्वारा दिसम्बर, 1948 में लिया गया था। उस समय वार्षिक किराया 6,511 रुपये था। आकाशवाणी ने जब उसे लिया था तब उसमें 5 किलोवाट का एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर और 4 स्टूडियो का एक स्टूडियो केन्द्र था।

(ग) वर्तमान जगह का मासिक किराया 3,545 रुपए (करों सहित) है।

Atrocities Committed on Rajputs in West Pakistan

1473. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it a fact that atrocities are being perpetrated on the Saudha Rajputs in the Thaiparkar District of West Pakistan ; and

(b) if so, the action taken by Government in regard thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) Government has no such information.

(b) Does not arise.

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये कार्यक्रम

1474. श्री गु० सि० ढिल्लों : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या 16 जनवरी, 1968 को भुवनेश्वर में एक सार्वजनिक भाषण में उन्होंने घोषणा की थी कि समूचे देश तथा प्रगतिशील क्षेत्रों के हित में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक विशेष कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस कार्यक्रम में 1965 के भारत-पाक युद्ध से क्षतिग्रस्त हुए क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) प्रधान मन्त्री ने पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह नहीं कहा कि विशेष कार्यक्रम के बारे में विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

मैक्सिको-अमरीका अणु-शक्ति परियोजना

1475. श्री गु० सि० ढिल्लों : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'गैस बग एक्सपैरिमैंट्स' कहे जाने वाली मैक्सिको-अमरीका अणु-शक्ति परियोजना के तकनीकी ब्यौरे का पता लगाने के लिये कोई प्रयास किया है ;

(ख) क्या प्राकृतिक गैस के उत्पादन हेतु सफलतापूर्वक किये गये विश्व के प्रथम शान्ति-पूर्ण अणु विस्फोट के बारे में हमारे वैज्ञानिकों के लिये कोई लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मंत्री अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) गैस बग्गी प्रायोजना के अन्तिम परिणाम लगभग एक वर्ष तक प्राप्त होने की सम्भावना है।

राष्ट्र ध्वजा को सलामी

1477. **श्री वे० कु० दासचौधरी :**
श्री मोहन स्वरूप :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री चपलाकांत भट्टाचार्य :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में राष्ट्रीय छात्रसेना दल के केडिटों ने 26 जनवरी, 1968 को गणतन्त्र-दिवस की परेड के समय राष्ट्र ध्वज को सलामी नहीं दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) गवर्नमेंट कालेज, मेरकारा के एन० सी० सी० छात्रों ने 26 जनवरी, 1968 के गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रध्वज को सल्यूट नहीं दिया था।

(ख) एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी आदिष्ट की गई है, और उसकी कार्यवाही प्रतीक्षित है।

पूर्वी पाकिस्तान में पृथकतावादियों का आन्दोलन

1478. **श्री जुगल मंडल :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में पृथकतावादियों की कार्यवाही के लिये भारत पर आरोप लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) 6 जनवरी, 1968 को पाकिस्तान सरकार ने आरोप लगाया कि अगरतला में एक भारतीय राजनयिक और कुछ भारतीय सैनिक अधिकारियों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ षड़यंत्र में कई पाकिस्तानियों की सहायता की ।

(ख) भारत सरकार ने आरोपों को निश्चित रूप से अस्वीकार किया है और इस पर खेद प्रकट दिया है कि पाकिस्तान सरकार ने भारतीय अधिकारियों को ऐसे मामले में झूठे ही फसाने की कोशिश की है जो कि अनिवार्य रूप से पूर्व पाकिस्तान की आंतरिक घटना है ।

तिब्बती शरणार्थी

1479. श्री जु० कि० मंडल : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बती शरणार्थी अभी भारत आ रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में छानबीन करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां, 126 तिब्बती शरणार्थियों का आखिरी दल 18/19-11-67 को भारत में पहुंचा था ।

(ख) पूछताछ करने वालों के एक दल द्वारा तिब्बतीय शरणार्थियों से अच्छी तरह पूछताछ की जाती है ताकि विध्वंसक तत्वों को पकड़ा जा सके और उन्हें घुसने न दिया जाए । जब कभी किसी की असलियत पर शक होता है तो उसे निवारक नजरबन्दी कानून के अंतर्गत रोक लिया जाता है ।

24 जुलाई, 1967 को लोक-सभा तारांकित प्रश्न संख्या 1348 के उत्तर में और 18 दिसम्बर, 1967 को लोक-सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 722 के उत्तर में यह सूचना दी जा चुकी है ।

लेह के साथ सम्पर्क के लिये सड़क का निर्माण

1480. श्री हिम्मतसिंहका : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नुवरा घाटी को लेह के साथ जोड़ने वाली सड़क का निर्माण-कार्य चालू हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) लेह और देश के शेष भाग के बीच सम्पर्क के लिये इस सड़क के निर्माण में केन्द्र का अंशदान कितना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) नुवरा घाटी को लेह से मिलाने के लिए सड़क का निर्माण, सीमा सड़क विकास बोर्ड के कार्यक्रम में शामिल नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

गणतंत्र-दिवस परेड (1968) को बैठने की व्यवस्था

1481. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गणतन्त्र-दिवस परेड (1968) के समय शेख अब्दुल्ला के बैठने के लिए पांचवीं पंक्ति में तथा दिल्ली के मेयर के बैठने के लिए सांतवीं पंक्ति में व्यवस्था की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) शेख मुहम्मद अब्दुल्ला और दिल्ली के मेयर दोनों के लिए स्थानों का प्रबन्ध,

मन्त्रियों, संसद् सदस्यों और अन्य महान् विभूतियों के लिए उद्दिष्ट वी–1 अहाते में किया गया था ।

(ख) उन महान् विभूतियों को बिठाने का प्रबन्ध कि जो गणतन्त्र-दिवस परेड देखने के लिए आमन्त्रित किए गए थे अग्रता क्रम की सारणी में उनके अपने-अपने स्थान के अनुसार किया गया था । किसी महान व्यक्ति को जिसने अपने पद प्रभार का त्याग किया हो, प्रायः उस पद प्रभार को धारण करने वाले के बाद बिठाया जाता है । राज्यों के मुख्य मंत्री धारा 15 में आते हैं, जब कि दिल्ली के मेयर को अग्रताक्रम की सारणी में धारा 28 के पश्चात् और धारा 29 से पहले स्थान दिया गया है ।

Industrial Collaboration with Mauritius

1482. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn towards a recent statement made by the Prime Minister of Mauritius where in welcoming the investment of foreign capital in the industrial development of his country and offering extension of all possible assistance to foreign industrialists;

(b) if so, the reaction of the Government thereto ; and

(c) whether Indian industrialists have also expressed a desire to establish industries there and the number of those who have sought permission from Government therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) and (b) No, Sir. Government is, however, aware that the Government of Mauritius would welcome investment of foreign capital. Every possible ecouragement and facility will be given by our Government to entrepreneurs and industrialists wishing to establish joint industrial ventures in Mauritius.

(c) Yes, Sir. Three Industrialists have expressed their interest to estabish industries in Mauritius.

प्रतिरक्षा तैयारी

1483. **श्री ओ० प्र० त्यागी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान की प्रतिरक्षा तैयारी को दृष्टि में रखते हुए हमारे सैनिक विशेषज्ञों ने हमारी प्रतिरक्षा तैयारी के बारे में सरकार को एक योजना पेश की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त योजना पर विचार नहीं हुआ क्यों कि वित्त मंत्रालय ने उस पर होने वाले व्यय की स्वीकृति नहीं दी थी ; और

(ग) यदि हां, तो पाकिस्तानी हमले के विरुद्ध भारत की रक्षा के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) 1966–71 के लिए रक्षा आयोजना में जो सेवाओं के मुख्यालयों से सलाह-मशविरे के साथ तैयार की गई थी और सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी वह विभिन्न उपाय

समावेशित किए गए हैं जो देश की रक्षा के लिए आवश्यक समझे गए हैं। सेवाओं के मुख्यालयों द्वारा कोई अन्य योजना या प्रायोजना नहीं भेजी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पालम के हवाई अड्डे से टायरों और ट्यूबों की चोरी

1484. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री 10 जुलाई, 1967 को अतारांकित प्रश्न संख्या 5087 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम हवाई अड्डे से टायरों और ट्यूबों की चोरी के बारे में की जा रही जांच पूरी हो गई है ;

(ख) क्या अपराधियों का पता लग गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) से (ग) इसका कोई सूत्र चिन्ह नहीं मिला, ऐसे घोषित करके मामला पुलिस द्वारा न्यायालय को भेज दिया गया है तदापि, मामले की वायु सेना द्वारा, जांच के लिए नियुक्त की गई कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी ने अपनी कार्यवाही भेज दी है। वायुसेना के 4 सेविवर्ग और दो असैनिक, कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी द्वारा पर्यवेक्षण के अभाव और लापरवाही के दोषी ठहराए गए हैं। वायुसेना के सेविवर्ग के विरुद्ध प्रशासनिक कार्य किया गया है। असैनिकों में से एक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रगतिशील है। दूसरे असैनिक को वायु सेना से निवृत्त कर दिया गया है।

चीन जाने वाले नागा

1485. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमिगत विद्रोही नागाओं के दो दल, जिनमें लगभग 500 नागा हैं, चीन जाने के उद्देश्य से हाल ही में नेफा के तीरप सीमान्त जिले की ओर जाते बताए गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) छिपे नागाओं से और उनकी गतिविधियों से संबद्ध सभी सूचना वर्गीकृत होती है।

(ख) भारत सरकार ने छिपे नागाओं की गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं और उठा रही है।

भारतीय साम्यवादी नेताओं के साथ रूस के प्रधान मन्त्री की बैठक

1486. **श्री यशपाल सिंह** : **श्री यज्ञदत्त शर्मा** :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1968 में अपनी हाल की यात्रा के दौरान रूस के प्रधान मंत्री भारतीय साम्यवादी नेताओं से मिले थे ;

(ख) यदि हां, तो उनके बीच क्या बातचीत हुई हैं ; और

(ग) क्या इस बैठक के बारे में, सरकार को पूर्व जानकारी थी ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्ट देखी है कि सोवियत राजदूतावास में सोवियत प्रधान मंत्री और कुछ भारतीय साम्यवादी नेताओं की प्राइवेट मीटिंग हुई थी । यह नहीं मालुम हुआ है कि किस प्रकार की चातचीत हुई थी ।

(ग) जी नहीं ।

जेट विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

1487. **श्री मेघचन्द्र** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1968 के अन्तिम सप्ताह में हैदराबाद में एक जेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें स्कैवड्रन लीडर मर गया था और डिप्टी लीडर जख्मी हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के लिये कोई मुआवजा अथवा अन्य सहायता मंजूर की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ललित नारायण मिश्र) :

(क) जी हां । घटना में, जो 22 जनवरी, 1968 को हुई, स्क्वैड्रन लीडन सी० वी० सिंह निधनप्राप्त हुए और स्क्वेंड्रन लीडर एम० के० जैन को मामूली चोटें आईं ।

(ख) ऐसा मालूम होता है कि विमान एक मोड़ लेते सम्भल न सका । तदापि, एक कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी आदिष्ट कर दी गई है । पूरे विस्तार उसकी रिपोर्ट की अन्तिम रूपरेखा पर ही ज्ञात हो पाएंगे ।

(ग) और (घ) स्क्वैड्रन लीडर सी० वी० सिंह की विधवा को निम्न लाभों की अदायगी के लिये कार्यवाही की जा रही है, कि जिसकी वह अधिकारिणी हैं—

(1) कुटुम्ब उपदान	4000 रुपये
(2) विशेष कुटुम्ब पेन्शन	180 रुपये
(3) बच्चों के लिए भत्ता	30 रुपये मासिक प्रति बच्चा

इसके सिवाय प्रति बच्चे के लिए 5 वर्ष की आयु से साधारणतः 21 वर्ष की आयु तक अधिकाधिक 40 रुपये मासिक तक शिक्षा-भत्ता देय है । विधवा को 42,000 रुपये तक की एक अनुग्रहपूर्वक अदायगी भी देय है ।

आकाशवाणी, इम्फाल के कर्मचारियों से आवेदन

1488. **श्री मेघचन्द्र** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आकाशवाणी केन्द्र, इम्फाल के स्थानीय कर्मचारियों की ओर से एक

अभ्यावेदन मिला है जिसमें कहा गया है कि उनकी पदोन्नति की जाये और असिस्टेंट प्रोड्यूसर की श्रेणी बढ़ाई जाये, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उसके बारे में क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) प्रार्थना को इस लिये स्वीकार न किया जा सका क्यों कि असिस्टेन्ट प्रोड्यूसर का कोई पद खाली न था। बचत की सख्त जरूरत के कारण इम्फाल में असिस्टेन्ट प्रोड्यूसर का पद भी न बनाया जा सका।

जंजीबार में भारतीय

1489. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जंजीबार की सरकार ने यह घोषणा की है कि उन सभी विद्यार्थियों, विशेषकर एशियाई, जिन्होंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा देने के बाद इस द्वीप को छोड़ दिया है, के माता पिता 29 जनवरी, 1968 तक द्वीप को छोड़कर चले जायें ;

(ख) यदि हां, तो इस घोषणा से जंजीबार में कितने भारतीयों पर प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) सरकार को ऐसी किसी घोषणा की जानकारी नहीं है। बहरहाल, 28 जनवरी, 1968 को जंजीबार में एक बड़ी रैली के सम्मुख भाषण करते हुए, तन्जानिया के प्रथम उपराष्ट्रपति और जंजीबार के राष्ट्रपति ने यह कहा बताते हैं कि द्वीप (जंजीबार) के विभिन्न जाति वर्गों को पूरी तरह मिलाने के लिए "मिश्रित विवाहों" पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा और इसलिए जो माता-पिता अपने बच्चों को विवाह कराने के लिए जंजीबार से बाहर भेजेंगे , उन्हें निष्कासित कर देना होगा। यह और पता चला है कि जंजीबार के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि जिन मां-बापों के बच्चे उक्त उद्देश्य के लिए पहले ही जंजीबार से बाहर भेजे जा चुके हैं, उन्हें फरवरी, 1968 के अन्त तक जंजीबार छोड़ कर जाना होगा।

(ग) सरकार उक्त घटना की जांच कर रही है।

काश्मीर पर रूसी इतिहासकार द्वारा टिप्पणी

1490. **श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री म० ला० सोंधी :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ताशकन्द घोषणा की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर विभिन्न भाषाओं जिनमें हिन्दी और उर्दू भी शामिल है मास्को रेडियो द्वारा प्रसारित की गई एक रूसी

इतिहासकार आयोना एंड्रोना की टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है जिनमें काश्मीर पर आंग्ल-अमरीकी साम्राज्यवादियों की चाल का उल्लेख है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) जी हां । सरकार ने अखबारों में इस आशय की खबरें देखी हैं ।

(ग) इस बारे में सरकार को कुछ नहीं कहना है ।

Use of Hindi

1491. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the details of those orders regarding the use of Hindi, out of all such orders issued by the Ministry of Home Affairs on this subject, which have not been sent to the subordinate offices so far ; and

(b) the time by which these orders would be sent to all the subordinate offices of the Ministry?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) :

(a) and (b) A large number of orders relating to the use of Hindi have been issued by the Ministry of Home Affairs from 1955 onwards. The Ministry of Defence forwards these orders to the Service Headquarters and Inter-Service Organisations so far as they are applicable to them and it is for the Service Headquarters and the Inter-Service Organisations to transmit these orders to the large number of offices subordinate to them.

The information asked for is being collected and will be placed on the Table of the House as soon as it is collected.

सैगोन में भारतीय

1492. **श्री मेघचन्द्र** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैगोन में लगभग कितने भारतीय हैं ;

(ख) क्या सैगोन में रह रहे भारतीय सुरक्षित हैं और उन पर सैगोन में हाल में हुई गड़बड़ी का प्रभाव नहीं पड़ा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उनकी सुरक्षा के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) दक्षिण वियतनाम में अनुमानतः कोई डेढ़-दो हजार भारतीय राष्ट्रिक हैं जिनमें से एक हजार सैंगोन में रह रहे हैं ।

(ख) सैगोन-स्थित हमारे प्रधान कोंसलावास के पास सुलभ सूचना के अनुसार सैगोन और चोलेन क्षेत्रों के सभी भारतीय राष्ट्रिक सुरक्षित हैं । प्रधान कोंसलावास के पास दूसरे शहरों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों के बारे में पूरा ब्यौरा सुलभ नहीं है । लेकिन किसी दुर्घटना की रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ग) प्रधान कोंसलावास की देख-रेख में स्थानीय भारतीय संगठन भारतीय समुदाय की देखभाल रख रहे हैं। प्रधान कोंसलावास के पास सहायता की कोई विशेष प्रार्थना अभी तक नहीं आई है।

रेडियो लाइसेंस-शुल्क में कमी

1493. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी से व्यापार सम्बन्धी विज्ञापन से होने वाली अतिरिक्त आय को देखते हुए सरकार का विचार रेडियो लाइसेंस-शुल्क कम करने अथवा समाप्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब से कार्य रूप दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Civilian Employees working at Hindon Airport

1494. **Shri Nihal Singh**: Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3775 on the 11th December, 1967 and state :

(a) whether a decision has since been taken in regard to the House Rent Allowance and City Compensatory Allowance of civilian employees working at Hindon Airport, Ghaziabad ;

(b) if so, the details thereof and whether Government propose to grant such special allowances to the civilian employees working at Hindon as have been granted to their counterparts working at Gurgaon ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence : (Shri M. R. Krishna) :

(a) and (b) Yes, Sir. Orders have been issued for the grant of house rent allowance with effect from 1-1 1968 to the civilian employees of Air Force Units at Hindon as a special case at the following rates :

(i) **Staff residing at Delhi**—at the rates applicable for Delhi from time to time.

(ii) **Staff residing at Ghaziabad**—at the rates applicable for Ghaziabad from time to time.

As regards compensatory allowance the position was stated in parts (b) (ii) and (d) of the reply to the earlier question quoted by the Hon'ble Member. The earlier decision not to grant any compensatory allowances to the employees residing at Ghaziabad and working at Hindon remains unchanged. Government do not also propose to consider the grant of allowance to the employees at Hindon at the rates sanctioned for employees working within the premises of Ammunition Depot, Gurgaon.

(c) The allowances at Ammunition Depot, Gurgaon, were sancioned in consideration of its special situation, e.i. greater proximity of the Depot area to the Delhi corporation than to the Gurgaon Municipality. The situation of Hindon Airport is not similar to that of Ammunition Depot Gurgaon.

दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति

1495. श्री हिम्मतसिंहका : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल के संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन द्वारा इस बात के लिए उपलब्ध अवसर का लाभ उठाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है कि दक्षिण अफ्रीका को बाध्य किया जाये कि वह अपनी रंगभेद नीति छोड़ दे ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यवाही का ब्यौरा क्या है तथा इसमें भारत का क्या योगदान है ; और

(ग) इस कार्यवाही के क्या परिणाम रहे ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

रोडेशिया

1496. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन महीनों में सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्रमंडल के माध्यम से अथवा अन्य किसी तरीके से रोडेशिया की अल्प-संख्यक सरकार के स्थान पर एक लोकप्रिय सरकार की स्थापना के लिये क्या कार्यवाही की है तथा इस सम्बन्ध में अब तक कितनी सफलता मिली है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : पिछले तीन महीने में भारत सरकार ने रोडेशियाई समस्या के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र के समक्ष कोई नया प्रस्ताव नहीं नहीं रखा है किन्तु संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्र-मंडल के समान विचारधारा वाले सदस्यों से निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं, यह विचार करने के लिए कि रोडेशिया के विद्रोह को समाप्त कराने के उद्देश्य से सम्मिलित रूप से क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं ।

आकाशवाणी के श्रेणी तीन के तकनीकी कर्मचारी

1497. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के श्रेणी तीन के तकनीकी कर्मचारियों के कार्य तथा कार्य के घंटे निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके कार्य तथा कार्य के घंटे निर्धारित करने में कितना समय लगने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) से (ग) आकाशवाणी के तृतीय श्रेणी के तकनीकी कर्मचारियों के काम निर्धारित किए हुए हैं । एक विवरण संलग्न है जिसमें विभिन्न श्रेणियों के तकनीकी

कर्मचारियों के काम दिए हुए है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 180/68]

आकाशवाणी में दो प्रकार के तकनीकी कर्मचारी हैं; एक वे जो आकाशवाणी ट्रांसमीटरों, श्रवण-केन्द्रों, स्टूडियों आदि में शिफ्ट ड्यूटी पर काम करते हैं और दूसरे वे जिनके काम न्यूनाधिक कार्यालय कर्मचारियों के समान हैं। शिफ्ट ड्यूटी वाले कर्मचारियों के लिए काम करने का आम समय प्रति दिन 8 घंटे रखा गया है (एक साप्ताहिक छुट्टी के साथ) । शिफ्ट ड्यूटी वाले कर्मचारियों के काम के कितने घंटे हों, उसको अंतिम रूप से निश्चित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

शिफ्ट ड्यूटी पर काम न करने वाले कर्मचारियों का कार्यालय समय वही है जो केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के लिए निर्धारित है।

आकाशवाणी के श्रेणी दो के ड्राफ्ट्समैनों को स्थायी करना

1498. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में श्रेणी दो के ऐसे कितने ड्राफ्ट्समैन है जिन्हें अब तक स्थायी नहीं किया गया हैं ; और

(ख) इन्हें स्थायी करने में कितना समय लगने की संभवना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) और (ख) आकाशवाणी में श्रेणी दो के ड्राफ्ट्समैन के 19 स्थायी पदों में से 8 पदों पर व्यक्ति स्थायी हैं जिनमें से 5 उच्चतर पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं । अगले कुछ महीनों में 11 और व्यक्तियों के स्थायी हो जाने का संभावना है परन्तु उच्चतर पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे श्रेणी दो के 5 ड्राफ्टसमैनों की जगह नियुक्त व्यक्तियों को तभी स्थायी किया जाएगा जब वे उच्चतर पदों पर स्थायी हो जाएँगे और रिक्तियों को मूलतः मुक्त कर देंगे।

Army Officers and Jawans Arrested by the Police

1499. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of officers and jawans of the Indian Army arrested by the Police for violating the various Laws of the country from January, 1962 to date ;

(b) the number of persons amongst them who have been prosecuted ?

(c) the number of persons convicted and those acquitted by the courts ; and

(d) the number of cases still pending in the courts ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L.N. Mishra) :

(a) to (d) The information is being collected from the lower formations and will be laid on the Table of the House, as soon as it is received.

गणतंत्र दिवस परेड (1968) पर व्यय

1500. श्री विक्रम चन्द महाजन : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 जनवरी, 1968 को हुई गणतंत्र दिवस परेड पर कुल कितना धन व्यय हुआ ; और

(ख) सभी ब्लाकों में लोगों के बैठने के लिये कुल कितनी सीटें थीं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) गणतंत्र दिवस परेड, 1968 का हिसाब-किताब अभी तक सम्पूर्ण नहीं हो पाया। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किए गए खर्च दर्शाने वाला एक विवरण हिसाब-किताब के सम्पूर्ण हो जाने के पश्चात् सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ख) 49359 ।

समापन समारोह (1968) सम्बन्धी व्यय

1501. श्री विक्रम चन्द महाजन : श्री रवि राय :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 29 जनवरी, 1968 को हुए "समापन समारोह" पर कुल कितना धन व्यय हुआ था और उसमें लोगों के बैठने के लिए कितनी सीटों की व्यवस्था की गई थी ; और

(ख) क्या जनसाधारण को कोई निमन्त्रण-पत्र, जारी किये गये थे और यदि हां, तो कितने और वे किन सिद्धान्तों पर जारी किये गये थे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) :

(क) और (ख) गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट उत्सव के खर्च की कुछ मदें सांझी हैं । इसलिए 29 जनवरी, 1968 के बीटिंग रिट्रीट उत्सव पर अलग किया गया खर्च दर्शा पाना कठिन होगा । तदपि, यथासंभव सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

29 जनवरी,1966 के बीटिंग रिट्रीट उत्सव के लिए 14592 व्यक्तियों के बैठने के लिए स्थान थे। इसमें 1120 स्थान उस अहाते में थे जिस के लिए आमन्त्रण-पत्र/प्रवेश पत्र आवश्यक न थे । इसके अतिरिक्त जिन अहातों में प्रवेश आमन्त्रण-पत्रों द्वारा होना था, उनके लिए, 2200 स्थानों के लिए ऐसे व्यक्तियों को आमन्त्रण-पत्र जारी किए गए थे जो प्राप्य सूचना के अनुसार कोई सरकारी ओहदे धारण न करते थे । ऐसे व्यक्तियों के लिए आमन्त्रण-पत्र जारी किए जाने की प्रार्थनाओं पर उन के गुणरूप के आधार पर विचार किया गया था, और आमन्त्रण-पत्र स्थानों की प्राप्यता के आधार पर जारी किए गए थे । उपयुक्त हालतों में, जहां 29 जनवरी, 1968 के बीटिंग रिट्रीट (के मुख्य) उत्सव के लिए आमन्त्रण-पत्र जारी करना संभव न था, 28 जनवरी, 1968 को आयोजित, विशेष प्रदर्शन के लिए, आमन्त्रण-पत्र जारी किए गए थे ।

फिल्म डिवीजन के तकनीकी तथा गैर-तकनीकी कर्मचारियों के सेवा-काल में वृद्धि सम्बन्धी शर्तें

1502. श्री कन्डप्पन: : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तकनीकी तथा गैर-तकनीकी कर्मचारियों का सरकारी सेवा से अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की आयु क्या है;

(ख) फिल्म डिवीजन, बम्बई के तकनीकी तथा गैर-तकनीकी कर्मचारियों के सेवा-काल में वृद्धि किन शर्तों पर दी जाती है; और

(ग) 1966 और 1967 में 58 वर्ष का आयु प्राप्त करने के बाद फिल्म डिवीजन के कितने तकनीकी तथा गैर-तकनीकी कर्मचारियों का सेवा-काल बढ़ाया गया है और उन कर्मचारियों के पदनाम क्या हैं और उनका सेवा-काल कितनी अवधि के लिये बढ़ाया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के कर्मचारियों के लिए 58 साल परन्तु 1938 से पूर्व के कार्यालीय सरकारी कर्मचारियों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 60 साल है।

(ख) सामान्य सिद्धान्त के अनुसार, सेवा-काल में वृद्धि विशेष अवस्थाओं तथा जन-हित में की जाती है। तथापि, तकनीकी और वैज्ञानिक व्यक्तियों को, उनकी विशिष्ट योग्यता और अनुभव का लाभ उठाने के लिए अधिक अवधि के लिए रखना जनहित में समझा जाता है, बशर्ते कि वे उपयुक्त और योग्य हो। वृद्धि किसी भी हालत में और गैर-तकनीकी और गैर-वैज्ञानिक कर्मचारियों के लिए 60 साल और वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों के लिए 62 साल की आयु से उपर नहीं होती।

(ग) चार, नीचे दिये गये विवरण के अनुसार :—

कर्मचारी का नाम, पदनाम तथा किस पद पर हैं।	सेवा-काल में वृद्धि की अवधि	सेवा-काल में वृद्धि के कारण
गैर-तकनीकी		
1. श्री जी० के० महरेश, प्रोडक्शन मैनेजर	2 फरवरी, 1967 से एक वर्ष के लिये जिसको तब तक के लिए बढ़ाया गया जब तक उसके स्थान पर नियुक्ति नहीं हो जाती।	जन-हित
2. श्री बी० एन० मजूमदार आर्ट डायरेक्टर	15 अप्रैल, 1967 से 6 माह के लिये।	

3. श्री आर० बी० आर्य, सम्पादक	1 जुलाई, 1962 से समय-समय पर सेवा-काल में वृद्धि की गई। अन्तिम वृद्धि 15 अक्टूबर, 1967 को एक वर्ष के लिये, परन्तु 17 नवम्बर, 1967 को उनकी मृत्यु हो गई।	जन-हित (वह गांधी जी पर फिल्म बनाने के काम पर लगे थे)
तकनीकी		
4. श्री डी० आर० मिस्त्री, चीफ कैमरामैन	3 दिसम्बर, 1966 से एक वर्ष के लिये।	जन-हित

Rules Regarding Political Asylum

1503. **Shri Sheopujan Shastri** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are no rules at present under which political asylum could be granted to a defector like Shri Aziz Oulong Zade ; and

(b) if so, whether any rules are beig framed in this regard for the expeditous disposal of such cases ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) There are no rules governing the grant of political asylum in India. Such cases are decided by the Government in the exercise of its sovereign right and discretion and a decision is taken in each case on its merits.

(b) No Sir.

रूसी नौसेना के कमांडर-इन-चीफ की यात्रा

1504. **श्री दी० चं० शर्मा : श्री यशपाल सिंह :**

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी नौसेना के कमांडर-इन-चीफ ने रूसी नौसेना प्रतिनिधि-मंडल के प्रधान के रूप में हाल ही में भारत का दौरा किया था ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था ; और

(ग) उनके साथ हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) जी हां, यू० एस० एस० आर० की नौसेना के अध्यक्ष ने 6 स्टाफ अफसरों समेत हाल ही में भारत का भ्रमण किया है।

(ख) हमारे नौसेना अध्यक्ष के 1967 में य० एस० एस० आर० के भ्रमण के उत्तर में यह एक सद्भावना भ्रमण था।

(ग) सद्भावना भ्रमण होने के नाते यह प्रश्न नहीं उठता।

पिछड़े वर्गों के लिए अध्ययन दल

1505. **श्री द० रा० परमार** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के तत्वावधान में श्री श्रीकान्त सेठ के नेतृत्व में पिछड़े वर्गों सम्बधी एक अध्ययन दल ने अक्तूबर, 1967 में गुजरात राज्य का दौरा किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अध्ययन दल ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि पिछड़े वर्गों के सुधार तथा लाभ के कार्यों की बजाय धनराशि का मुख्य भाग प्रशासन पर खर्च किया जा रहा है ;

(ग) इस अध्ययन दल ने अन्य क्या सुझाव दिये हैं ; और

(घ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) से (ग) योजना आयोग के सुझाव पर योजना कार्य समिति द्वारा आदिम जाति विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित अध्ययन दल नियुक्त किया गया था । दल के अध्यक्ष श्री पी० शिलू आओ हैं और सर्वश्री एल० एम० श्रीकान्त और टी० शिवशंकर इसके सदस्य हैं । अध्ययन दल की ओर से श्री श्रीकान्त ने अक्तूबर, 1967 में कतिपय आदिम जाति क्षेत्रों का दौरा किया और अधिकारियों, गैर-सरकारी व्यक्तियों इत्यादि से विचार-विनिमय किया । अध्ययन दल ने अभी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता, क्यों कि अध्ययन दल का प्रतिवेदन अभी तैयार नहीं हुआ है ।

मंत्रियों द्वारा विदेशों का दौरा

1506. **श्री कृ० मा० कौशिक** :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) मन्त्रियों तथा उप-मन्त्रियों द्वारा किये गए विदेशों के दौरे प्रधान मन्त्री की सलाह से किए गए थे ; और

(ख) उनको सामान्यतः किस आधार पर अनुमति दी जाती है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) जी, हां ।

(ख) मंत्री और उप-मंत्री विदेश-यात्रा उस स्थिति में करते हैं जब कि ऐसा करना उनके लिए कर्त्तव्य निर्वहन की दृष्टि से आवश्यक होता है ।

Backward Areas of Uttar Pradesh

1507. **Shri Nageshwar Dwivedi** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the amount sanctioned item-wise to District Jaunpur under the Patel Commission for backward areas of Uttar Pradesh and the amount paid so far ; and

(b) whether a part of the amount sanctioned to Jaunpur has been provided to Azamgarh and if so, the extent thereof ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) On the basis of the information given by the Government of Uttar Pradesh, a statement indicating the outlays and the expenditure in years 1964-65 to 1966-67 on the development pogrammes in district Jaunpur, Uttar Pradesh is plaeed on the Table of the House. (**Placed in Library. See No. LT-181/68**)

(b) The State Government has reported that no part of the outlay allotted to Jaunpur was dverted to Azamgarh.

Non-Proliferation of Nuclear Weapons Treaty

1508. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the countries to which nuclear science is proposed to be confined according to the present non-proliferation of nuclear weapons treaty ; and

(b) the reasons as to why India has not been included in the list of the countries possessing ability to manufacture atom bomb when the Indian Scientits are able to manufacture and explode the same ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) and (b) The revised draft of the Treaty on non-proliferation of nuclear wepons presented by the USA and the USSR to the Eighteen-Nation Disarmament Committee at Geneva on 18th January, 1968 prohibts non-nuculear weapon States party to the Treaty from developing or acquiring nuclear weapon or nuclear explosive devices even for peaceful purposess such a restrition does not apply to the nulear weapon States party to the Treasy. However all parties to the Treaty will have the right to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes, subject to the prohibition referred to above. The definition of a nuclear weapon State, according to the draft Teaty, is one which has manufacturd and exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive device prior to 1st January 1967. The USA, the USSR, the UK, France and the People's Republic of China would fall in this category.

थुम्बा राकेट लांचिंग केन्द्र

1509. **श्री दी०चं० शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या थुम्बा राकेट लांचिंग केन्द्र अन्तरिक्ष सम्बन्धी अनुसन्धान के हेतु अन्तर्राष्ट्रीय उपयोग के लिये खोल दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों ने इस केन्द्र का उपयोग करने के लिये अनुरोध किया है ;

(ग) क्या चीन ने रेडियो से अपने प्रसारणों में इस केन्द्र के अन्तर्राष्ट्रीय उपयोग के लिये खोले जाने की आलोचना की है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : (क) जी हां । थुम्बा विषुवदीय राकेट प्रक्षेपण स्टेशन को अन्तर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए 2 फरवरी, 1968 को विधिवत खोल दिया गया ।

(ख) इस स्टेशन की स्थापना से ही इसके लिये फ्रांस, अमरीका तथा रूस का सहयोग मिला है। हाल ही में जापान तथा पश्चिमी जर्मनी ने भी आपसी सहयोग से किये जा सकने वाले परीक्षणों के लिये रुचि दिखाई है ।

(ग) और (घ) जी, हां ।

संयुत अरब गणराज्य के सहयोग से जेट इंजनों का निर्माण

1510. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मरुत परियोजना किस अवस्था में है ;

(ख) क्या यह पता लगाने के लिये कोई विस्तृत छानबीन की गई है कि क्या विमान इंजनों के विकास के लिये देश में हाल में किये गये अनुसंधान को दृष्टि में रखते हुये संयुक्त अरब गणराज्य में निर्मित ई-300 इंजन से अभी भी भारत की वर्तमान आवश्यकता पूरी हो सकेगी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) एच० एफ० 24 मेक 1 एच० ए० एल० (बी० डी०) में उत्पादन अधीन है। कुछ विमान भारतीय वायु सेना को वितरित कर दिये गये हैं ।

एच० एफ० 24 मेक आई० आर० का एक संशोधित संस्करण विकास अधीन है ।

(ख) और (ग) एच० एफ० 24 के विमान ढांचे में युक्त किये गये ई-300 इंजन की विकास उड़ानों के परीक्षण अभी यू० ए० आर० में प्रगतिशील हैं। भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उसकी उपयुक्तता का प्रश्न उड़ान परीक्षणों की सफलतापूर्वक सम्पूर्ति के पश्चात् ही उठ सकता है ।

अहमदाबाद से टाइम्स आफ इण्डिया, तृतीय संस्करण

1511. **श्री एस्थोस :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

श्री चक्रपाणि : **श्री प० गोपालन :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाइम्स आफ इण्डिया ने अहमदाबाद से तृतीय संस्करण के प्रकाशन के लिये घोषणा-पत्र दे दिया है ;

(ख) क्या टाइम्स आफ इण्डिया ने इस प्रयोजन के लिये प्रेस रजिस्ट्रार से अनुमति मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या प्रेस रजिस्ट्रार ने आवश्यक अनुमति दे दी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) जी, हां टाइम्स आफ इंडिया का अहमदाबाद संस्करण 5 फरवरी, 1968 से छपना शुरू हुआ था ।

(ख) वर्तमान प्रेस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम 1867 की धारा 6 के अन्तर्गत, समाचार-पत्र के नाम के बारे में प्रेस रजिस्ट्रार की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि प्रस्तावित पत्र उन्हीं मालिकों द्वारा प्रकाशित किया जाता था जो पहले से ही विभिन्न स्थानों से उसी नाम से और उसी भाषा में समाचार-पत्र निकाल रहे थे । अखबारी कागज के लिए भी प्रेस रजिस्ट्रार की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 1967-68 के लिए अखबारी कागज के नियतन सम्बन्धी नीति के अनुसार, नए समाचार-पत्र किसी भी यूनिट के अधिकृत कोटे के अन्दर प्रकाशित हो सकते हैं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

त्रिपुरा में पाकिस्तान द्वारा अधिकृत क्षेत्र

1512. श्री शशि रंजन : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में पाकिस्तान द्वारा अधिकृत क्षेत्र छुड़ाने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) त्रिपुरा-पूर्व पाकिस्तान सीमा पर कुछ भारतीय प्रदेश पाकिस्तान के कब्जे में हैं । ऐसा या तो सीमा का अन्तिम रूप से रेखांकन होने तक अस्थायी कार्यकारी सीमा करारों के अन्तर्गत अथवा वर्तमान करारों की परस्पर विरोधी अर्थ-व्याख्या के कारण हुआ है । सीमा का रेखांकन और विवादों का समाधान होने से पहले इन प्रदेशों के एक दूसरे देश के विपरीत अधिकार से छुड़ाने का प्रश्न नहीं उठता । त्रिपुरा- पूर्व पाकिस्तान सीमा के रेखांकन का काम हाल ही में फिर शुरू हुआ है । आशा है कि इस क्षेत्र की बाकी सीमा समस्याएं रेखांकन का कार्य होते-होते हल हो जायंगी ।

हिमाचल प्रदेश में सड़कें और पुल

1513. श्री हेमराज : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1966-67 में सड़कों तथा पुलों के निर्माण के लिये हिमाचल प्रदेश के लिये कितनी राशि मंजूर की गई थी और वास्तव में कितनी राशि दी गई थी ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : 1966-67 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में सड़कों, पुलों आदि के निर्माण के लिये कुल 518.02 लाख रुपये की धन राशि मंजूर की गई है और पूंजीगत परिव्यय के अधीन उसे दिया गया है ।

Farakka Barrage

1514. **Shri Onkar Lal Berwa :** **Shri Deven Sen :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan Foreign Minister in a recent statement in Dacca stated that Pakistan has a claim on sharing the Ganga waters according to the international law and objected to the construction of the Farakka Barrage and threatened to take this issue to the international area ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandi) :

(a) Yes, Sir.

(b) The Government of India are of the view that the Farakka Barrage Project will not affect the interests of Pakistan. However, with a view to allaying the apprehension of the Pakistau Government, the Government of India agreed to the exchange of data by the technical experts of the two countries. For this purpose, four meetings have so far been held ; and the fifth one may be held in the coming months.

पाकिस्तान द्वारा फरक्का बांध के बारे में प्रचार

1515 श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रचार तेज कर रहा है कि फरक्का बांध का पूरा होना पाकिस्तान के हितों के विरुद्ध है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का खंडन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मत्री, अणु-शक्ति मंत्री ,योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार का ख्याल है कि फरक्का बांध प्रायोजन से पाकिस्तान के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । फिर भी, पाकिस्तान सरकार के भय को दूर करने की दृष्टि से भारत सरकार दोनों देशों के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा सूचना का आदान-प्रदान करने को सहमत हो गई । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अभी तक चार मीटिंगें हुई हैं ; और पांचवी मीटिंग आगामी महीनों में आयोजित की जायेगी ।

सरकार ने भारतीय मिशनों के जरिये भारत की स्थिति को स्पष्ट करने के लिये कदम भी उठाये हैं ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

मद्रास में हिन्दी विरोधी आन्दोलन

श्री न० कु० साल्वे (बतूल): मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इस विषय के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ;

"तामिलनाड को भारत संघ से मुक्त कराने हेतु प्रचार करने के मदुरै के विद्यार्थियों की हिन्दी विरोधी आन्दोलन परिषद् के कथित निश्चय और मद्रास राज्य के कुछ विद्यार्थियों द्वारा भारत के संविधान की हिन्दी प्रतियां जलाने के कथित निश्चय"

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों से सरकार को पता चला है कि मद्रास में कुछ विद्यार्थियों को पृथकतावादी मांगें प्रस्तुत करने के लिये गुमराह किया जा रहा है। हम राज्य सरकार से सम्पूर्ण तथ्यों का पता लगा रहे हैं। सभा को विदित है कि देश के विभिन्न भागों में भाषा विवाद के मामले पर जनता की भावनाएं भड़क उठी हैं । हमने बार-बार इस बात पर बल दिया है कि राष्ट्रीय एकता की सर्वाधिक आवश्यकता को ध्यान में रख कर हमें इन मामलों पर शान्तिपूर्ण ढंग से और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपना कर विचार करना चाहिये ।

Shri N. K. P. Salve (Betul) : The situation has become very serious as a result of the students' decision to propagate for liberation of Tamilad from the Indian Union. If such an agitation is put down rusthlessly and immediately, the country will go to dogs. I want to know whether a round table conference of leaders of all the parties would be conveneed in which a political code of conduct should be evolved in order to determine the causes of students agitations which lead to lawlessness and chaos ?

Shri Vidya Charan Shukla : We have asked for the details of this agitation from Madras Government. On receipt of these details, the course of action would be determined.

Shri Shrichand Goel (Chandigarh) : The representatives of 100 schools took part in the said conference and it was decided that they will neither respect the Indian Flag nor they will honour National Anthem but on the other hand they will propagate for liberation of Madras from the Indian Union. I want to know whether Government has made any enqiury to see if there is any political element working behind this agitation ? Whether Government would also examine such activities of the students and determine the action to be taken against them so that such a mentality could be curbed ?

Shri Vidya Charan Shukla : We have asked for the details. After examining the full facts we s hall be able to decide the eourse of action.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want to know whether eminent leaders of Madras support the resolution of Madurai Students' Council ? Whether Prime Minister and Home Minister are aware of the speeches made by the founder of the Swatantra Party Shri Rajagopalachari to the effect that he was being forced in his old age to think about separation from India ? (**Interruptions**) I want to know whether Rajaji and Shri Kamraj have made such speeches ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : ऐसे कोई वक्तव्य हमारे ध्यान में अभी तक नहीं आये हैं ।

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh): Shri Kamraj has not said any such thing.

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि वे इस समस्या के प्रति यथार्थवादी एवं उचित दृष्टिकोण अपनाने के लिये तैयार हैं और क्या देश के सभी राष्ट्रीय तत्वों में मतैक्य स्थापित करने के लिये तैयार हैं जिससे पृथकतावादी शक्तियों को रोका जा सके ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : यदि विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य परस्पर विचार करके हमे बतायें कि यर्थाथवादी दृष्टिकोण क्या है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि विरोध पक्ष, कांग्रेस या सरकार गोल मेज़ कान्फ्रेंस में किसी मतैक्य पर पहुंच सके, तो अच्छा होगा । इस सम्बन्ध में ध्याव दिलाने वाली सूचना के रूप में नहीं, बल्कि अलग-अलग बात-चीत करके विचार किया जा सकता है । इसलिये वे अलग कमरे में बैठ कर इस विषय पर विचार करें ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

पंजाब सिनेमाघर (विनियमन) हरयाणा संशोधन अधिनियम

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : मैं हरयाणा राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पंजाब सिनेमाघर (विनियमन) हरयाणा संशोधन अधिनियम, 1967 (1967 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 9) की एक प्रति, जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, सभा-पटल पर रखता हूँ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 167/68]

नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें तथा विविध (संशोधन), विनियम

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें तथा विविध (संशोधन) विनियम, 1968 की एक प्रति, जो दिनांक 13 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 1-ई में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखता हूँ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 168/68]

पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल से प्राप्त टेलीप्रिंटर सन्देश

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मैं पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल से 20 फरवरी, 1968 को प्राप्त टेलीप्रिंटर सन्देश की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 168/68]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

बीसवां प्रतिवेदन

श्री र० के० खाडिलकार (खेड) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयको तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 20 वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

लोक लेखा सयिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

अट्ठरहवां प्रतिवेदन

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : मैं परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय (सीमा सड़क संगठन) से संबंधित लेखा परीक्षण प्रतिवेदन (सिविल), 1967, पर लोक लेखा समिति का 18 वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

उन्नीसवां प्रतिवेदन

श्री कन्डप्पन (मैटूर) : मैं शिक्षा मंत्रालय—वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद-नेशनल फिज़ीकल लेबोरेटरी, नई दिल्ली—के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति (तीसरा लोक-सभा) के 103वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्रांक्कलन समिति का 19 वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

तारांकित प्रश्न संख्या 572 के सम्बस्ध में पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION TO THE REPLY GIVEN TO A SUPPLEMENTARY QUESTION ARISING OUT OF STARRED QUESTION NO. 572.

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : चन्दा समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य के कागजात के नष्ट किये जाने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 572 के अनुपूरक प्रश्न में श्री देवकी नन्दन पाटोदिया ने पूछा था कि यह स्पष्ट है की जो कुछ हुआ है, उसके सम्बन्ध में सरकार से सलाह नहीं ली गयी। उन्होंने यह भी पूछा था कि क्या सरकार नियमों

में ऐसे परिवर्तन कर रही है जिससे ऐसी घटनाएं दोबारा न हों और भविष्य में इस प्रकार साक्ष्य का रिकार्ड नष्ट न किया जाये।

इसके उत्तर में मैंने यह उत्तर दिया था कि नियम पहले से बने हुए हैं। नियमों के अनुसार उन्हें यह साक्ष्य का रिकार्ड नष्ट नहीं करना चाहिये था। परन्तु उन्होंने उसे नष्ट कर दिया है।

इस सम्बन्ध में यह भी कहना चाहता हूँ कि इस उत्तर की सही रचना यह है कि जब सरकार कोई समिति बनाती है तो उस समिति को जितने कागजात मिलते हैं वह सरकार की सम्पत्ति होती है और इसलिये बिना सरकार की अनुमति के समिति को उन्हें नष्ट नहीं करना चाहिये। यह सामान्या प्रक्रिया है, परन्तु इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिये और अधिक बन्धनकारी बनाने के लिये गृह-कार्य मंत्रालय ने 25 जनवरी, 1968 को विशिष्ट अनुदेश जारी किये हैं कि सरकार द्वारा नियुक्त समिति/आयोग के समक्ष दिये गये साक्ष्य को बिल्कुल सही रूप में सरकार को सौंप देना चाहिये और उस प्रतिवेदन में निहित शिफारिशों से सम्बन्धित कार्यवाही पूरी हो जाने के पांच वर्ष बाद तक उसे रखा जाना चाहिये।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मंत्री महोदय को स्पष्ट रूप में बताना चाहिये कि पहले कोई ऐसा नियम था या नहीं। यदि पहले कोई ऐसा नियम नहीं था तो उन्हें इस बात को स्वीकार करना चाहिये और कह देना चाहिये कि अब नियम बनाये जा रहे हैं।

श्री के० के० शाह : मैंने बताया है कि उसमें कुछ ग़लतफ़हमी थी।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : इसलिये समिति ने जो कार्यवाही की थी, वह ठीक है।

श्री के० के० शाह : अधिनियम के अनुसार यह कार्यवाही अनुचित थी।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं उस समिति का सदस्य था। किसी साक्ष्य को सुरक्षित रखना समिति के लिये अनिवार्य नहीं था। समिति के समक्ष जो साक्ष्य दिये गये थे, उनके साथ निपटना समिति का काम था। हमारे बहुत से गवाह सरकारी कर्मचारी थे। यदि हम उन्हें यह आश्वासन नहीं देते कि उनके वरिष्ठ अधिकारी उनके साक्ष्य को नहीं दे सकेंगे तो वे निर्भीक हो कर अपना साक्ष्य कभी न देते। उस समिति के अध्यक्ष कई समितियों के अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने हमें कई उदाहरण दिये थे जिनके साक्ष्य नष्ट कर दिये गये थे।

खुदाबक्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी विधेयक

KHUDA BAKSH ORIENTAL PUBLIC LIBRARY BILL

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : I beg to move for leave to introduce a Bill to declare the Khuda Baksh Oriental Public Library at Patna to be an institution of national importance and to provide for its administration and certain other connected matters.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : On a point of order, Sir. I welcome this Bill. There are however, certain objectionable things in this Bill. There is a provision of forming a Board

in Calsuse 5(c) . It is proposed to nominate a member of Khuda Baksh's family in the Board which is not proper as it indicates that we believe in imprealism whereas our ideal is socialism. In view of this I am of the opinion that the Bill should be introduced in the revised form.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ;

"कि पटना स्थित खुदा बख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और उसके प्रशासन तथा कतिपय अन्य संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Sher Singh : I introduce the Bill.

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव–जारी

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—CONTD.

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : मुझे इस बात का खेद है कि जिन बातों को सरकार कई वर्षों से कहती चली आ रही है उन्हीं बातों को राष्ट्रपति के अभिभाषण में दोहराया गया है । इस में समस्याओं की सूची तो दी गयी है परन्तु उनके समाधान के विषय में कुछ नहीं कहा गया है । आज देश में जो आर्थिक संकट है उसका कारण केवल दो वर्ष तक सूखा पड़ना या पाकिस्तान के साथ युद्ध ही नहीं है बल्कि इसके कई अन्य कारण भी हैं । इनमें से एक कारण यह है कि देश में मुद्रास्फीति बहुत अधिक रही है । पिछले पांच वर्षों में ही यह मुद्रास्फीति 3000 से बढ़ कर 5000 करोड़ रुपये हो गयी है । फिर अवमूल्यन हुआ । हमारा विचार था कि अवमूल्यन के पश्चात् हमारे निर्यात में वृद्धि होगी । परन्तु वास्तव में हमारे आयात की लागत गढ़ गयी और इसलिये हमारे निर्यात में कमी हो गयी क्योंकि जिस वस्तु का यहां उत्पादन होता है उसकी लागत पहले से अधिक हो गयी है । इस पर भी काफी औद्योगिक क्षमता बेकार पड़ी है । इससे न केवल बहुत बड़ी हानी होती है बल्कि इसका प्रभाव रोजगार की स्थिति पर भी पड़ता है । दूसरी कठिनाई यह कि हमारे पास धन की भी कमी है ।

पिछले 15 वर्षों में प्रशासनिक व्यय में 8 गुना वृद्धि हुई है । इसमें से कुछ रुपये को औद्योगिक विकास में लगाया जा सकता है । लगभग तीन तिहाई सरकारी को निकाला जा सकता है और इससे कार्य-कुशलता में भी कमी नहीं होगी बल्कि वृद्धि होगी । गैर–सरकारी क्षेत्र में धन ज्यादातर भूमि और भवनों पर खर्च किया जा रहा है । उदाहरण के तौर पर केवल दिल्ली में ही शानदार भवन निर्माण करने पर 1000 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं ।

हमारे देश में उपभोग की दर भी बहुत अधिक है । राष्ट्रपति भवन और राज भवनों

पर बहुत अधिक रुपया खर्च होता है। राष्ट्रपति भवन और राजभवन एक प्रकार से धर्मशालाएँ-सी बनी हुई हैं। जो भी कोई विदेशी आता है वह उसमें ठहरता है। दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता। उन देशों में विदेशियों को होटलों में ठहराया जाता है।

अधिक आयकर और अप्रत्यक्षकरों के कारण क्रमागत ह्रास हो रहा है। इसके कारण मुद्रा स्फीति भी हो रही है। उद्योग और सरकार के बीच कोई सम्पर्क नहीं है।

हमारी लाइसेंस देने की नीति भी दोषपूर्ण रही है। हमने ऐसे वस्तुओं के लिए लाइसेंस दे दिये हैं जिनके बिना हम गुजारा कर सकते हैं। कभी-कभी हम ऐसी वस्तुओं के लिये भी लाइसेंस जारी कर देते है जिनका उत्पादन हम नहीं कर सकते हैं।

उत्पादन में भी वृद्धि नहीं हुई है। पंचवर्षीय योजना के समाप्त किये जाने के परिणाम स्वरूप सरकारी आर्डरों में कमी हो गई है। रेलवे और दूसरे छोटे और मझले दर्जे के उद्योग बन्द हो गये हैं। इंजीनियरों में इसी कारण बेरोजगारी उत्पन्न हुई है।

राष्ट्रपति ने देश की एकता और देश में फैली हिंसा का भी अपने भाषण में उल्लेख किया है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

बुराई को घटाकर बताया जाता है और बुराई को उचित ठहराया जाता है। आसाम के सम्बन्ध में सरकार को पहले मालूम हो गया था कि वहां पर विघटनकारी तत्व सक्रिय हैं, फिर भी यह कहा जाता है कि वहां पर आकस्मिक ही उपद्रव हुए हैं।

मद्रास में जो कुछ हो रहा है उसके लिए हम सब उत्तरदायी हैं।

ब्रिटिश काल में नेतृत्व में एकता थी तथा त्याग की भावना थी, परन्तु आज नेतागण मुख्यतः सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं और हमेशा संकट उत्पन्न करते रहते हैं।

यदि हमारे नेता भाषा के प्रश्न पर दखल न देते तो वह बहुत ही संतोषपूर्ण ढंग से हल हो सकता था। हम इस भाषा विधेयक को प्रस्तुत न करते। अब वह कहते है कि सर्व-सम्मति होनी चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने इस बारे में पहले कांग्रेसी सदस्यों से भी विचार-विमर्श नहीं किया।

मेरे विचार से यह विधेयक उचित नहीं था तथा असंवधानिक था। यदि आपको कोई चीज करनी थी तो आपको संवैधानिक संशोधन लाना था। इस विधेयक को लाने से पहले सरकार ने राजा जी से क्यों विचार-विमर्श नहीं किया।

यदि सरकार विरोधी पक्ष के साथ समझौता करने की इच्छुक है तो उसे दूसरे स्वतन्त्र देशों की तरह विपक्षी दलों को सरकार के साथ काम करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

विपक्षी दल के किसी सदस्य को संयुक्त राष्ट्र संघ व्यापार तथा विकास सम्मेलन में नहीं बुलाया गया।

क्या संसार में कोई भी देश ऐसा है जो विकसित नहीं हो रहा है ? आपने इस सम्मेलन पर न अपना बल्कि दूसरे देशों का भी बहुत अधिक रुपया व्यय किया है। इस सम्मेलन से कोई लाभ होने वाला नहीं मेरी समझ में नहीं आता कि उन देशों का सम्मेलन क्यों बुलाया गया है जो कि विकसित हैं और जो दूसरे देशों की परवाह नहीं करते। इस समय सब देशों में मन्दी है। यह सम्मेलन उपयोगी हो सकता था यदि यह उचित समय पर बुलाया गया होता।

यदि हम देश को समृद्ध बनाना चाहते हैं तो हम अपने देश में सदा विरोध करने वाले विरोधी दल और सदा गलती करने वाली सरकार को सहन नहीं कर सकते। विपक्षी दल सत्ता रूढ़ दल को गुलाम बनाना नहीं चाहते। वे तो केवल उनकी शक्ति में भागीदार होना चाहते है।

आप सहयोग की बात करते हैं। क्या आपने किसानों को सहयोग दिया है ? उनके लिये पानी, खाद तथा बीजों की व्यवस्था की है।

हमें सबको मिलकर कठिनाइयों को हल करना चाहिये।

जो देश अधिक विकसित हो गये हैं उनमें भाषा और हिंसा की कोई समस्या नहीं है। वे पूर्व परम्पराओं के अनुसार कार्य करते हैं।

क्या इस समय की अपेक्षा भी ज्यादा देश में संकट उत्पन्न हो सकता है। युद्ध से भी देश में विभाजन नहीं होता इससे लोगों में एकता उत्पन्न होती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमें अपनी शक्ति बेकार खर्च नहीं करनी चाहिए और सबको मिलकर देश को समृद्ध बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिये।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लि स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Luch till Fourteen of the Clock

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् चार बजे पुनः समवेत हुई।

The Lok-Sabha then reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री चं० चु० देसाई (साबरकंठा) : राष्ट्रपति जी के मुख यह कहलवाना कि देश का भविष्य उज्जवल है, केवल कल्पना मात्रा है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में उज्ज्वलता नहीं दिखाई देती। सब जगह लोगों का यही विचार है कि देश पता नहीं किस ओर जा रहा है। इस सबके लिए कांग्रेस दल ही उत्तरदायी है क्योंकि 20 वर्ष से कांग्रेस ही सत्तारूढ़ रही है। कांग्रेस देश की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ सिद्ध हुई है। यदि हमारे नेतागण वास्तव में देश का कल्याण करने के इच्छुक हैं तो उन्हें यह ध्यान देना चाहिये कि देश किस ओर जा रहा है।

वर्तमान प्रधान मंत्री देश की समस्याओं का सामना करने में असमर्थ रही हैं। अतः अब अधिक कुशल एवं सक्षम व्यक्ति को प्रधान मंत्री के पद पर नियुक्त करना चाहिये।

कांग्रेस सरकार ने ही भाषा विधेयक संकल्प प्रस्तुत किया है । वह किसी समझौते के आधार पर प्रस्तुत किया गया था । जब कुछ व्यक्तियों तथा मंत्रियों ने संशोधन के लिए दबाव डाला तो प्रधान मंत्री दबाव में आ गईं और विधेयक और संशोधन दोनों ही में संशोधन किये गये। मद्रास में लोगों ने "जन गण मन" के गाने पर भी आपत्ति की क्यों कि वह हिन्दी में है।

यदि हिन्दी भाषा वाले अपनी बात पर अड़े रहे तो यह हिन्दी विरोधी भाषी और राज्यों जिनमें गुजरत भी शामिल है फैल जायेगा ।

बंगाल में सरकार ने कई दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की । अन्त में वहां राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया गया। मुझे आशा है वहां मध्यवर्ती चुनावों की कोई जल्दी नहीं होगी ।

सरकार को पश्चिमी बंगाल में स्वस्थ सरकार बनाने के लिये प्रयत्न करना चाहिये । सरकार को तभी राज्य में मध्यावधि चुनाव कराने चाहिये जबकि राज्य साम्यवादी तत्वों से मुक्त हो जाये ।

अब सरकार की कमजोर विदेश नीति के सम्बन्ध में मैं कुछ कहूँगा। सरकार ने पश्चिमी ऐशिया में संकट के समय इसराइल द्वारा अपने कब्जे में किये गये क्षेत्र को खाली करने के लिए कहा । इस सम्बन्ध में हमारा कोई मतभेद नहीं है। यदि सरकार का वास्तव में तटस्थता और गुटों से दूर रहने की नीति में विश्वास है तो उसे अरब देशों की गलती को भी बताना चाहिये ।

ताइवान ने बहुत प्रगति की है और उसकी मुद्रा सुदृढ़ होती जा रही है । यह बात समझ में नहीं आती कि ताइवान के साथ व्यापार क्यों नहीं करना चाहिये । तथा ताइवान को भी पूर्वी जर्मनी की तरह इस देश में अपना एक व्यापार प्रतिनिधि रखने की अनुमति क्यों नहीं देनी चाहिये ।

इस देश का और पाकिस्तान दोनों का ही भविष्य मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों पर निर्भर है। युद्ध निर्णयात्मक नहीं होते। हमें सुरक्षा पर 1200 करोड़ रुपये और पाकिस्तान को 500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च नहीं करने चाहिये और दोनों देशों के लोगों को आर्थिक विकास के लिये कार्य करना चाहिये ।

मैं इस में विश्वास करता हूँ कि पाकिस्तान से मित्रता स्थापित करनी चाहिये परन्तु उसके लिये हमें अपनी प्रभुसत्ता का बलिदान नहीं करना चाहिये । उससे समझौता करने के दूसरे तरीके भी हैं ।

गुजरात जिले के साबरकण्टा में उगने वाली कपास सारे देश में सबसे अच्छी होती है और वह कपास अमरीका और मिश्र की कपास के मुकाबले में है । परन्तु सरकार द्वारा ऐसी नीति का पालन किया जा रहा है कि इस जिले को संकट का सामना करना पड़ रहा है । इस सम्बन्ध में सरकार को विचार करना चाहिये ।

हम ऐसी सरकार चाहते हैं कि जिस पर जनता का पूरा विश्वास हो ।

श्री राजशेखरन : (कनकपुरा) इस समय हमारा देश गम्भीर संकट का सामना कर रहा है।

राष्ट्रपति ने अपने अभिषाण में कृषि क्षेत्र में प्राप्त सफलताओं का जिक्र किया है। कृषि पर 70 प्रतिशत जनसंख्या आधारित है। खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये अनेक प्रयत्न किये गये हैं। परन्तु इसके लिये और अधिक प्रयास किये जाने चहिये। किसानों के लिये ऋण सम्बन्धी सुविधाओं को बढ़ाया जाना चाहिये। किसानो को दीर्घावधि, अल्पावधि तथा मध्यावधि ऋण दिये जाने चाहिये। कृषि उपकरणों के विकास की भी हम अवहेलना करते जा रहे हैं। कालेजों में कृषि इन्जीनियरी विभाग खोले जाने चाहिये। आज किसानों को ट्रेक्टर आदि की थोड़ी सी गड़बड़ी के लिये भी दूर शहर उसे ठीक कराने के लिये जाना पड़ता है। उपलब्ध कृषि उपकरणों में सुधार पर भी ध्यान नहीं दिया गया। सिंचाई सुविधाएँ बढ़ाई जानी चाहिये। यदि सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध हों तो किसान दो या तीन फसलें भी उगा सकते हैं। एक पूरी योजना सिंचाई पर लगाई जानी चाहिये तभी सिंचाई की समस्या सुलझेगी। देहात के लोगों के सामने अनेक समस्याएँ हैं। 80 प्रतिशत लोग गाँवों में रहते हैं। वहां पर अच्छे-मकान, सड़क, बिजली की सुविधाएं, यातायात के साधन तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायें। सम्पूर्ण ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाया जाये।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह आशा व्यक्त की है कि प्रशासन में समय के अनुसार परिवर्तन होगा और सरकारी कर्मचारी लोगों का विश्वास प्राप्त करेंगे। परन्तु मेरा यह विचार है कि अदक्ष तथा नौकरशाही प्रशासन के कारण सरकार को अधिक सफलताएं मिली हैं। सरकारी अधिकारियों के पास आज जन साधारण की पहुंच नहीं है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षण केन्द्र पहाड़ी स्थानों पर स्थित हैं जबकि वे देहातों में स्थापित किये जाने चाहिये ताकि उन्हें देहात के बारे में कुछ जानकारी और अनुभव हो। मेरा सुझाव है कि प्रशासन के ढाँचे में ऐसा परिवर्तन किया जाना चाहिये, जिससे उसमें दक्षता आये और अधिकारी किसान और जन-साधारण पर उचित ध्यान दें। आज पहली आवश्यकता यह है कि देश के प्रशासन में दक्षता, स्फूर्ति, गतिशीलता तथा देश-भक्ति की भावना का प्रादुर्भाव हो।

मैसूर-महाराष्ट्र के बीच सीमा-विवाद को दृढ़ता से तय किया जाना चाहिये। जब तक इस सम्बन्ध में सरकार की ढुलमुल नीति बनी रहेगी तब इसी प्रकार के आन्दोलन चलते रहेंगे। सीमा–विवाद का निर्णय अन्तिम रुप से कर दिया जाना चाहिये। साथ ही मेरा यह अनुरोध है कि मैसूर को अधिक राशि दी जानी चाहिये जिससे वहां की सिंचाई, कृषि तथा लघु उद्योग सम्बन्धी स्थानीय समस्याओं को सुलझाया जा सके, जिससे मैसूर में अधिक लोगों को रोजगार मिले। केन्द्रीय सरकार को उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिये शीघ्रता करनी चाहिये जो मैसूर राज्य में लम्बे समय से निर्माणाधीन है।

Shri Yajna Datt Sharma (Amritsar): The Address of the President is disappointing as

it does not provide guidance to the Government. It failed to give inspiration and hope to the people of India. It appears that the Government is not prepared to mould its policies and act in the way that will help to solve the problems facing India these days. The Government do not appear to have any intentions to improve the deplorable conditions of our masses. Retrenchment is being effected on large scale in Government departments and undertakings. Government talk of modernization at the cost of unemployment. It will not solve the problem of unemployment. Rather it will increase it.

The employees of Haryana Government intend to launch agitation to press their demand that they should be given dearness allowance at par with that available to Punjab Government Employees. There is great justification in their demand and Government should accept their demand. The Government employees are demanding that Amritsar city should be categorized as 'B' grade city. The Industrialists of Amritsar are complaining for non-availbility of raw material. Government should consider these issues sysmpathetically. The scheme of crop insurance should compulsorily be made applicable to the farmers of Khemkaran sector as it will give a sense of security to the local poeple there

The President has rightly laid stress on the point regarding oneness and integrity in his address. This is the need of the hour particularly at a time when it is being destroyed by commmunal riots. All the political parties should make efforts to bring about integrity and should give up compartmental thinking. Government should also not give full freedom to such people as Shiekh Abdulla who does not call himself an Indian citizen, who always speaks in a way harmful for the unity and integrity of the country. He should not be given undue publicity and importance. Now we should try to recover the territory which is under illegal occupation of Pakistan. We are not prepared to leave even an inch of Kashmir.

Now I take up the Kutch Award. It has gone against India. We objected to the very proposal of arbitration in respect of Kutch dispute, because we know that international awards are not based on justice but they are based on political consideration. Our Government should not agree on giving any territory to any foreign country. Whether the territory in question has fertile lands or barren tracts. The Government should try to solve the problems facing the people of border areas.

श्रीमती ज्योत्सना चंदा (कचार) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश का वास्तविक चित्र अंकित किया गया है। उसके लिये राष्ट्रपति जी धन्यवाद के पात्र है । यह प्रसन्नता और संतोष की बात है कि अब देश बाढ़ और सूखे के दैवी प्रकोप के प्रभाव से बाहर आ रहा है । प्रकृति की अनुकम्पा लोगों के दृढ़ निश्चय तथा सरकार के नेतृत्व की त्रिवेणी के फलस्वरूप देश की स्थिति सुधरती जा रही है।

गत गणतन्त्र-दिवस पर ब्रह्मपुत्र घाटी में जो दुखद दुर्घटनाएँ घटीं, उनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। कुछ युवकों, जिनका गलत मार्ग-प्रदर्शन किया गया तथा कुछ अन्य लोगों ने मिलकर गोहाटी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उपद्रव किये और लूटमार की। इसके लिये न केवल युवक लोग जिम्मेदार हैं, बल्कि राजनैतिक नेता, कुछ बुद्धिजीवी तथा प्रशासक लोग भी जिम्मेदार हैं।

आसाम में संकीर्णता की भावना का प्रचार किया जा रहा है जो बिल्कुल अनुचित है । 'आसाम' असमियों के लिये' एक नारा संकीर्णता का द्योतक है ।

देश के विभाजन के तत्काल पश्चात् ब्रह्मपुत्र घाटी के विरुद्ध बंगाली भाषा बोलने वालों के बड़े व्यवस्थित ढंग से अभियान चलाया गया । इस स्थिति को देखते हुए भी अधिकतर राजनीतिज्ञों ने चुप रहना ही ठीक समझा और शासन तंत्र ने इस सम्बन्ध में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं किया । इसका फल यह हुआ कि वहां पर दंगे और आगजगी की घटनाएँ अत्यधिक हुईं । इस पृष्ठ भूमि में जनवरी, 1968 में हुई घटनाओं का उत्तरदायित्व उन राजनीतिज्ञों और बुद्धिजीवी वर्ग पर है जिन्होंने आसाम के पुनर्गठन के मामले में विद्यार्थियों और युवकों को भड़काया था । आज हमें यह यह प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिये कि क्या हमने स्वयं नफरत और लालच को प्रोत्साहन नहीं दिया है ? जब उत्तरदायी राजनीतिक दल संकीर्णता का प्रचार करे, जब सेवा-निवृत्त असैनिक कर्मचारी गैर-असमिया भाषा-भाषियों के विरुद्ध संघर्ष करने की घोषणा करें, जब राज्य के उच्चधिकारी गणतंत्र-दिवस को जनमत और पहाड़ी जिलों की आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के आधार पर आसाम के पुनर्गठन के निर्णय के लिये प्रधान मंत्री और गृह-मंत्री की आलोचना करें तो अत्यधिक भावुक विद्यार्थियों और युवकों द्वारा इस मामले को सड़कों पर ले जाना असम्भव नहीं होगा ।

पिछले 20 वर्षों में तो यह देखा गया है कि वे बिल्कुल उन्मत्त हो जाते थे, और यहां तक कि देश की स्वतंत्रता और एकता को खतरा हो जाता था । परन्तु इस बार ब्रह्मपुत्र घाटी के कुछ सही दिशा में सोचने वाले व्यक्तियों ने हिंसात्मक कार्यों में भाग लेने से इन्कार कर दिया था और ऐसे लोगों ने हिंसात्मक घटनाओं की खुल कर निन्दा की है ।

गृह-कार्य मंत्री के दौरे से भी वहाँ पर शन्ति स्थापित करने में काफी सहायता मिली है । इस सभा में और बाहर सभी लोगों को यह मांग करनी चाहिये कि गोहाटी, विजयनगर आदि में हुई घटनाओं के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों को कड़ा दण्ड दिया जाये । इन घटनाओं की न्यायिक जाँच की जानी चाहिये जिससे इस प्रकार की दुखद घटनाओं को दोबारा होने से रोका जा सके ।

रेलवे के डिब्बों से अनिवार्य वस्तुओं की चोरी की घटनाओं में हाल ही में बहुत ही वृद्धि हुई है । सिलचर में मैंने सुना भी है और देखा भी है कि जिन डिब्बों में चीनी लादी होती है उनमें बड़े पैमाने पर चोरी होती है जिससे न केवल व्यापारियों की हानि होती है बल्कि उपभोक्ताओं को भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । इस प्रकार की चोरियां सरसों का तेल और गेहूँ आदि ले जाने वाले डिब्बों में भी होती हैं । चोरी करने का तरीका भी नया है । डिब्बे बन्द रहते हैं और उनके नीचे सुराख करके चोरी की जाती है मेरा विचार यह है कि रेलवे के कर्मचारियों को जिनमें रेलवे सुरक्षा बल भी सम्मिलित है, इन चोरियों के लिये जिम्मेदार ठहरा कर और प्रत्येक स्टेशन पर डिब्बों की स्थिति बताने वाले कागजात पर हस्ताक्षर लेकर इन चोरियों को आसानी से रोका जा सकता है ।

आसाम में आने वाले शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि हो रही है । अभी सैकड़ों परिवार कचार जिले के विभिन्न कैम्पों में पड़े रहे हैं । उनके पुनर्वास के लिये कोई योजना नहीं बनाई गई

है । केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार से परामर्श करके इस सम्बन्ध में कुछ करना चाहिये और इस समस्या को असामाजिक तत्वों के हाथों में नहीं जाने देना चाहिये ।

मिजो जिले में अभी असैनिक प्रशासन ठीक ढङ्ग से कार्य नहीं कर रहा है । हम यह नहीं चाहते कि वहाँ पर सदा ही सेना तैनात रहे । इस स्थिति के साथ निपटने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये । इस क्षेत्र का उपयुक्त ढंग से विकास किया जाना चाहिये । देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये वहां पर सीमावर्ती सड़कें आदि बनायी जानी चाहिये ।

मैं अन्त में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे शीघ्र से शीघ्र आसाम के पुनर्गठन के सम्बन्ध में सोचे जिससे गैर-आसामी लोगों पर इस प्रकार के अत्याचार रोके जा सकें ।

श्रीमती सुशीला गोपालन (अम्बलपुजा) : राष्ट्रपति ने वर्तमान स्थिति का एक सुन्दर चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है । परन्तु वस्तु-स्थिति यह है कि अच्छी फसल होने के बावजूद हमारी योजना की स्थिति गम्भीर है । इसलिये चौथी योजना को अप्रैल, 1968 तक स्थगित कर दिया गया है । चावल और चीनी के मूल्यों में वृद्धि हो गई है । सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दो बार मंहगाई-भत्ता दिया है जिससे स्पष्ट है कि उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है । अब भी निहित स्वार्थों को संरक्षण दिया जाता है । निहित स्वार्थ अपना बोझ कर्मचारियों, किसानों और मध्य युग के लोगों पर डाल रहे है । सरकारी और गैर-सरकारी उपक्रमों की अधिक छंटनी हुई है । उद्योगपति कर्मचारियों पर दबाव डाल रहे हैं कि यदि उन्होंने मंहगाई भत्ते में कमी को स्वीकार नहीं किया तो वे कारखाने बन्द कर देंगे । छंटनी के सम्बन्ध में एक बात उल्लेखनीय है और वह यह कि उच्च अधिकारियों की छंटनी नहीं की जाती बल्कि उनकी संख्या बढ़ायी जाती है ।

[श्री गु० सिंह ढिल्लों पीठासीन हुए
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

अब भी सरकार अपनी मूल नीति में परिवर्तन करने के लिये तैयार नहीं हैं राष्ट्रीय नीति से सम्बन्धित वचनों का उल्लघंन किया गया है । यह कहा गया था कि किसी भी परिस्थितियों में विदेशियों को उनके सहयोग से चलाये जा रहे उद्योगों में अधिक हिस्से नहीं दिए जायेंगे । परन्तु इस शर्त में अब ढील दी जा रही है । विदेशियों को केवल अधिकांश हिस्से ही नहीं दिये जा रहे बल्कि उन्हें प्रबन्ध और नियंत्रण भी सौंपा जा रहा है । इस बात का नवीनतम उदाहरण आयात किये गये तरल एमोनिया के आधार पर उर्वरक कारखाने स्थापित करने के बारे में दी गई अनुमति है । यदि यही स्थिति रही तो हमारे देश में अमरीकी साम्राज्यवाद का प्रसार होगा ।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि सरकार की नीति 'राज्य सरकारों के साथ सहयोग करने की नीति है । परन्तु वस्तु-स्थिति इससे भिन्न है । सरकार आरम्भ से ही खाद्यान्न का प्रयोग राजनीतिक प्रयोजनों के लिये करती रही है । केरल को सज़ाई किये जाने

वाले चावल का उन्होंने मूल्य बढ़ा दिया है। उन्होंने चावल और उर्वरकों के सम्बन्ध में राज-सहायता देने के जो वचन दिये थे उनसे वे मुकर गये हैं। अब राज्य सरकार को चावल पर राज-सहायता देने के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष 19 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। आज 145 करोड़ रुपये के बजट में से हमें 19 करोड़ रुपये राज-सहायता के रूप में खर्च करने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, केन्द्र सरकार ने चावल की मात्रा के सम्बन्ध में भी अपने बचन को पूरा नहीं किया। पिछली बारे खाद्य मंत्री ने इस सभा में वचन दिया था कि अक्तूबर तक अनाज की स्थिति में सुधार हो जायेगा और वह 75,000 टन चावल सप्लाई कर सकेंगे परन्तु वह अब तक 75,000 टन चावल नहीं दे सके। अतः यह स्पष्ट है कि वह इस मामले का उपयोग राजनीतिक प्रयोजनों के लिये कर रहे हैं। जब प्रधान मंत्री हाल ही में केरल गयीं थीं तो केरल में शासक दल के प्रतिनिधि उनसे मिले थे, उन्होंने प्रधान मंत्री से चावल का कोटा बढ़ाने के लिये कहा। परन्तु उनको उत्तर मिला कि यदि 3 औंस चावल के हिसाब से भी दिये जाने वाला कोटा बन्द कर दिया जाये तो वे क्या करेंगे ? इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है और राष्ट्रपति का यह दावा है कि वे राज्य सरकारों के साथ सहयोग कर रहे हैं।

जहाँ तक अनाज की वसूली के कार्यक्रम का सम्बन्ध है, केरल सरकार केरल में उपलब्ध चावल की मात्रा को वसूल करना चाहती थी और इसलिये वे उन लोकप्रिय समितियों को कुछ शक्तियां देना चाहते थे जिनमें सभी दलों के प्रतिनिधि होते हैं। चाहे केन्द्रीय सरकार अनुमति दे या न दें, ये लोकप्रिय समितियां अधिक से अधिक चावल वसूल करने के काम में केरल सरकार की सहायता करेंगी। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि केन्द्रीय सरकार राजनीतिक कारणों से राज्य सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रही है। अब केन्द्रीय सरकार ने चौथी योजना में केरल राज्य की योजना के लिये आवंरित धन में कमी कर दी है। फिर चौथी योजना में आवंटन की व्यवस्था के लिये और अधिक धन प्राप्ति के लिये केरल सरकार द्वारा कर लगाया जायेगा। जनता की आर्थिक स्थिति पहले ही बहुत खराब है। केन्द्र सरकार जितना ऋण चाहे, विदेशों से प्राप्त कर सकती है परन्तु वे राज्य सरकार को जमा धन-राशि से अधिक धन लेने की अनुमति नहीं देते। केन्द्रीय सरकार इस प्रकार का सहयोग कर रही है। इन परिस्थितियों में हम भी केन्द्रीय सरकार के साथ सहयोग नहीं कर सकते।

श्री प० मु० सैयद (लक्कदीव-मिनिकोय तथा अमीन-दीव द्वीपी समूह) : श्रीमान्, मैंने दोनों पक्षों के भाषणों को बड़े ध्यान से सुना है। चाहे आर्थिक संकट का मामला हो या साम्प्रदायिक दंगों का हो, विरोधी पक्ष का काम कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाना है। यहां तक कि प्राकृतिक आपदाओं के लिये भी कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है। विरोधी पक्ष का कहना है कि सभी प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों के लिये कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। देखना यह चाहिये कि जब अंग्रेज यहाँ से गये थे, उस समय इस देश की क्या स्थिति थी ? फिर हमें सोचना चाहिये कि 20 वर्षों के दौरान हम क्या कर पाये हैं ? यह ठीक है कि यह प्रगति हमारी आशा के अनुकूल नहीं है। हम बहुत-सी समस्याओं का समाधान

नहीं कर सके । यदि विरोधी पक्ष हमारा साथ देता तो हम उनका समाधान कर सकते थे। राष्ट्रपति ने हमारे सम्मुख बहुत सी बातें रखी हैं। हम सबको उनके बारे में विचार करना चाहिये ।

कांग्रेस सरकार के विरुद्ध आरोप लगाया गया है कि वह गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडलों को अपदस्थ करने के लिये अपने प्रभाव का उपयोग कर रही है । आज प्रातः आचार्य कृपालानी ने ठीक ही कहा था कि वे अर्थात् विपक्षी दल स्वयं ही अपने मंत्रिमंडलों को गिराने के लिये उत्तरदायी हैं । विभिन्न विचारधाराओं के लोग जनता की सेवा करने के लिये नहीं, बल्कि सत्ता बनाये रखने के लिये इकट्ठे हो गये हैं। अन्त में यह हुआ कि कुछ घटक राष्ट्रीय आय के खर्च पर मंत्रिमंडल में और स्थान चाहते हैं । चुनावों के बाद बहुत-से राज्यों में यही स्थिति पैदा हुई है।

इस बार देश में लगभग 950 लाख टन अनाज पैदा होने का अनुमान है । क्या यह कांग्रेस सरकार की सफलता नहीं है ? यह दुर्भाग्य है कि हमारे देश में सैकड़ों धर्मों और रिवाजों का प्रचलन है जिसके परिणामस्वरूप परिवार नियोजन के कार्यक्रम को गम्भीरतापूर्वक नहीं अपनाया जा रहा है । हम यह स्वीकार करते हैं कि हममें कुछ कमजोरियां हैं और हमने गलतियां की है परन्तु हमारी कुछ सफलताएं भी हैं । सफलताओं का जहां तक सम्बन्ध है, इस्पात का उत्पादन पांच गुना बढ़ गया है । इसी प्रकार 'जेट' विमानों के इंजन भी बनाये जा रहे हैं और उद्योग तथा कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान के लिये अणुशक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे तेल-शोधक कारखाने स्वावलम्बी होते जा रहे हैं। रेलवे इंजन और डिब्बे भी देश में बनाये जा रहे हैं । पिछले वर्षों में बहुत सी सड़कें बनायी गयी हैं । ये सब कांग्रेस सरकार की सफलताएं हैं।

आज देश में 80 प्रतिशत बच्चों के लिये प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है । 1951 की अपेक्षा कालेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6 गुना है । सरकार का इरादा बहुत कुछ करने का है परन्तु प्रशासन का ढांचा कुछ ऐसा बना हुआ है कि कार्यवाही करने में देर लग जाती है ।

लक्कादीव द्वीप समूह की कई समस्याएं हैं । वास्तव में केवल तीसरी योजना में इस प्रदेश की ओर ध्यान दिया गया है । लक्कादीव में आज भी न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग-अलग नहीं किया गया। सरकार को इन्हें तुरन्त अलग-अलग कर देना चाहिये जिससे लोगों के साथ न्याय हो सके। आज लक्कादीव का जिला मजिस्ट्रेट बी० ए० पास भी नहीं है और न ही उसकी कोई कानून सम्बन्धी योग्यता है । वहां प्रशासक किसी भी व्यक्ति को नाम निर्देशित कर सकता है। अतः मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रशासनिक और गृह मंत्रालय स्तर पर सलाहकार निकायों का निर्वाचन होना चाहिये।

यदि स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला तो यह स्वाभाविक है कि वहां की जनता निराश होगी। सरकार को विशेषज्ञों का एक दल लक्कादीव भेजना चाहिये जो वहां पर उद्योग

आदि स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाये और उन्हीं के अनुसार धन की व्यवस्था की जाये जिससे उद्योगों की स्थापना की जा सके । मेरा एक और अनुरोध यह है कि वहां पर परिवहन की सुविधाओं में वृद्धि की जाये ।

अन्त में मेरा अनुरोध यह है कि संघ राज्य क्षेत्रों की एक संयुक्त पदालि बनायी जानी चाहिये जिससे एक राज्य क्षेत्र के कर्मचारियों को अन्य राज्य-क्षेत्रों में भेजा जा सके । हमें सभी राष्ट्रीय मामलों को एक दूसरे के विचारों को समझ कर सद्भावना के साथ निपटना चाहिये ।

Shri Mahant Digvijai Nath (Gorakhpur) : Much has been said about communalism. I fail to understand how this question arises in the present context of the situation even after the partition of the country ? This country was divided on two nation theory. The Muslims have got a separate State which is running on the theoritic lines. There is secular State in this country.

Today we talk of communalism at every stage. If we in our own country are called as commnualists, what will be our fate as citizen. Communalism means short mindedness. Hindus are not short minded. The communal disturbances that have taken place in the various parts of our country were planned by some foreign powers. Some fifth columnist are also working in this matter and the Government should be very careful in this regard. This conspiracy is being done for establishing a muslim majority State. In Asam Hindus are being compelled to leave the State while Muslims are being allowed to infiltrate. If this thing continues a time will come when Assam will become a part of Pakistan.

Something must be done to stop it. I, therefore, request you not to indulge in falsenationalism and thereby make the country weak. I told the Prime Minister not to bring language issue at this critical stage. Once you divided Andhra on the language issue which was a very wrong step. We have no grudge for any language. If we fight for our own language it is nothing serious but if we fight for the sake of English it is something serious.

To day Pakistan is being given assistance in money and other aspects by our own people. Whether you may be Kashmiri, Hindu, Punjabi or Bengali, you have to work with the sentiment of Hinduism and then the country can only progress. The Kashmir problem would have not arisen if we had settled a large number of Hindu refugees in that State. Tht Hindus settled ther are requesting to leave that State because they are feeling insecure. Hindus should be protected there. But you are not able to do that.

श्री दामानी (शोलापुर) गत दो वर्ष देश में पर्याप्त वर्षा न होने के कारण देश के लिये बहुत अधिक कठिन रहे । इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि की वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ गये । मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष फसल अच्छी हुई है । अब मूल्य गिरने लगे हैं। मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि मूल्य इतने कम न हो जायें कि इसके परिणामस्वरूप सरकार को कोई लाभ न मिले । यदि किसानों को लाभ होगा तो वह अपना धन फिर खेती में लगायेंगे और उत्पादन में वृद्धि करेंगे । इस सम्बन्ध में सरकार को किसानों की सहायता करनी चाहिये ताकि वे अपने उत्पादनों को उचित मूल्य पर बेच सकें ।

गत 15 वर्षों में देश ने उद्योग और कृषि में बड़ी प्रगति की है । हम बहुत-सी उपभोक्ता की वस्तुओं के सम्बन्ध में आत्मविर्भर हो गये हैं और कुछ वस्तुओं का निर्यात भी करने

लगे हैं। 1951 में हमारे इस्पात का उत्पादन 10 लाख टन था जो अब बढ़ कर 70 लाख टन हो गया है।

इसी प्रकार 1951 में हमारी सीमेंट की उत्पादन क्षमता 30 लाख टन थी जो अब बढ़कर 120 लाख टन हो गई है। इसी प्रकार अन्य उद्योगों के मामलों में भी प्रगति हुई है।

यह सच है कि सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है परन्तु ऐसा किसी का विचार नहीं है कि प्लान्टों में कोई कमी है। प्लान्ट सब प्रकार से ठीक हैं परन्तु उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। उत्पादन मजदूरों पर निर्भर करता है। मजदूरों पर विपक्षी दलों का नियंत्रण है। जब मजदूर लोग लगातार हड़ताल पर रहते हैं तो उद्योग में कैसे लाभ हो सकता है ? वे नहीं चाहते कि सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाले उद्योग लाभ पर चलें।

हमारे देश में औद्योगिक उपकरण बनाने की भी पर्याप्त क्षमता है। परन्तु हमें प्रत्येक वर्ष विदेशों से मशीनों का आयात करना पड़ता। उन मशीनों का आयात कम करने के लिये सरकार को उन मशीनों के निर्माण के विकास में छूट देनी चाहिये। यदि ऐसा किया गया तो देश में निर्यात मशीनरी को प्रोत्साहन मिलेगा और आयात में भी कमी होगी। यदि इस प्रकार का प्रोत्साहन दिया गया तो वास्तव में आयात में कमी होगी

श्री बोरेश्वर कलिता (गोहाटी) : राष्ट्रपति ने अपने भाषण में यह उल्लेख किया था कि पिछला वर्ष एक कठिन और चुनौती का वर्ष रहा है परन्तु, उन्होंने अपने सम्पूर्ण भाषण में यह नहीं बताया कि उस चुनौती का कैसा मुकाबला किया जा सकता है ? उन्होंने जो भाषण दिया वह तो औपचारिक मात्र था। अतः मैं इस धन्यवाद-प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

सरकारी अनुमान के अनुसार इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले 20 प्रतिशत अधिक अनाज उत्पन्न होगा। फिर भी उप-प्रधान मंत्री ने कहा है कि हमें पी० एल० 480 के अन्तर्गत 950 लाख टन अनाज का आयात करना होगा। इस वर्ष यदि अनाज के उत्पादन की इतनी अधिक अच्छी आशा है तो सरकार अमरीका से अनाज का आयात क्यों कर रही है ? सरकार की खाद्य सम्बन्धी नीति क्या है। सरकार की आयात की स्थिति का मुकाबला करने के लिये कोई वसूली नीति नहीं है। एक राज्यकीय क्षेत्र नीति उचित नीति नहीं है।

राष्ट्रपति ने अपने भाषण में यह उल्लेख किया है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि होने के पश्चात् राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हो जायेगी। एक राज्यकीय क्षेत्र की नीति के परिणामस्वरूप हमें अपनी अच्छी फसल पर निर्भर रहना पड़ेगा। पिछले वर्ष अच्छे मौसम के कारण अच्छी फसल हुई है। यह भी कहा गया है कि सरकार किसानों को ऋण देकर भी सहायता कर रही है। गत 20 वर्षों में किसानों के ऋणों में वृद्धि हुई है। सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिये ताकि सामान्य गरीब किसानों को उचित ऋण मिल सके। कृषि उत्पादन के साथ-साथ मूल्यों में भी वृद्धि हुई है। मूल्यों में 30 प्रतिशत वृद्धि के परिणामस्वरूप देश में आन्दोलक व, हड़ताल इत्यादि होंगी। इसके लिये सरकार साम्यवादी दलों को दोषी ठहरायेगी। इंजीनियर बेकार हैं और बहुत से कारखाने बन्द हो गये हैं। राष्ट्रपति के भाषण में उसके

लिये क्या सुझाव दिया गया है ? साम्यवादी नीति से समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। इससे और अधिक संकट उत्पन्न होगा और बेकारी में भी वृद्धि होगी। सरकार कई बार उल्लेख कर चुकी है कि हमारा समाज समाजवादी है। परन्तु देश में कहीं भी समाजवादी ढांचा नजर नहीं आता। एकाधिकारीवादी पूंजीपति देश पर शासन कर रहे हैं।

जैसा कि सर्वविदित है गुजरात और आसाम में तेल के भंडार हैं और हम 1971 तक तेल के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर हो जायेंगे। परन्तु हमें प्रति वर्ष 110 लाख टन तेल, जिसकी कीमत लगभग 110 करोड़ विदेशी मुद्रा है, का आयात करना पड़ता है। यद्यपि आसाम और गुजरात में काफी मात्रा में तेल पाया जाता है तथापि सरकार उनको प्रोत्साहन नहीं दे रही है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

गोहाटी की घटनाओं की मैंने तथा मेरे दल ने निन्दा की है। आसाम के पुनर्गठन के मामले पर ठंडे दिमाग से विचार किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में शान्तिपूर्ण हल खोजना चाहिये।

यह सर्वविदित है कि आसाम एक पिछड़ा प्रदेश है फिर भी सरकार ने उसकी दशा सुधारने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है। आसाम में कोई पूर्ण विकसित विश्वविद्यालय, चिकित्सा कालेज या इंजीनियरिंग कालेज नहीं है। आसाम में एक भी उद्योग नहीं है। वहां कोई बड़ी रेलवे लाइन भी नहीं है। यदि आसाम की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है तो इन सब बातों को दूर करना होगा।

Shri Randhir Singh (Rohatak) : I support the motion of thanks. It is a matter of regret that in the matter of recruitment to Delhi Police the people of area ranging 200 miles have been neglected. During the last fifteen days 231 persons were recruited but none of them was from Haryana. I could not understand why this discrimination was made. against the people of the area considering that they had been very good fighters. This discrimination must go.

The communal riots in Meerut must be condemned. Hindus and Muslims are brothers and must live like brothers. We are living in secular State in which all religion are equal and proud of such a State. It is regretted that our Jawans are very low paid. I request that the salary should be increased. You should give them full facilities. Their salaries should at least be doubled.

There are about 40 thousand unemployed engineers in our country. Government should pay great attention for solving this unemployment problem. If they do not get the employment what would happen to our country. The teachers should be paid well.

A huge amount is being spent on cities while the poor sections of the society cotinue to remain neglected. The conditition of the scheduled castes and backward class is very deplorable. Their income is lesser than what is required for their subsistance even. They should be given proper attention. Their co-operative societies should be organized so that they may earn more and raise their living standard. As regards agriculture I want to say that farmers should be given necessary facilities. Long-term loans, seeds, fertilizers, tractors, tube-well equipment should be made available to the farmers on reasonable rates. If these things are made available to them.

the agriculture production will be doubled to three or four times. The country will become self-sufficient in the matter of foodgrains and then there will be no necessity of importing food-grains from America, Canada or Australia.

Shri Bakshi Gulam Mohammad (Srinagar) : Sir, many hon . membrs expressed their views on the President's Address. The address has been delivered in a conventional form and all conventional matters have been referred to in it. No outstanding problem has been referred to about which one may give vent to his views. Nothing has been stated as to what we have done and what we are going to do. Suerly the hon. members of this House and the country admit that it would have been better if the problems facing the country had been referred to in the President's Address.

I have read throughly this address and I would express my views on the two or three problems which the country is presently facing. The President has referred to the problem of integrity of the nation. The country will prosper if its integrity is maintained. If this integrity is in danger the country would not prosper. We have to face this great problem of paramount importance.

This country was stabilised after independence by great leaders such as Gandhiji, Jwahwarlal Ji Maulana Azad, Pantji and such other leaders. Only few years have passed since the deth of Panditji. If you look at the country you will find it disintegrating gradually. We have faced so many problems. When we faced threat from Paskistan and China one thing was quite evident that the nation stood as one against the onslaught of China and Pakistani aggression. But what about the internal situation ? It destroys the integration of the nation and we are not as well knit today as we were five years ago.

Mr. Nath Pai stated the other day that we do not find an Indian now in the country. We find Kashmiris, Punjabis, Haryanawalas, Maharashtrians, Mysoreans, Assamese, Madras is but no one calls himself an Indian. It is the most dangerous thing for the country. Who is responsible for it ? Internal danger is the most dangerous thing for a nation and if one does not minimise it, it can destroy the entire people. Today our slogan is not " one country, one nation". We are now a victim of regionalism. Th language problem is disintegrating the country. Communalism is raising it a head in a dangerous form. Mahantji is not here now. I want to know whether Muslims have no place in this country for whose freedom millions of people, Hindus, Muslims, Sikhs, Christians and Parsees fought and laid down their lives together. I can only say that it is his ideology and I do not subscribe to it. This nation was honoured by the toil of Ashfaq, Azad, Ahmad Madni, Hifzur Rehman and lakhs of the Mulims who fought for it. They laid down their lives for it. If the Muslims feel that they are treated in this country as aliens then it would be a very dangerous thing. I ask the ruling party that Governments come and go but the country lives for ever and that party should serve the nation and the country.

The language problems is being made complicated daily. We have before us the problems of regionalism too. The problem of border disputes is being made more complicated instead of solving it. We have the problem of Communalism too. What a shameful thing it is that we preached to the world about secularism but there are communal riots in Meerut, Ranchi and at other places. It is not a good thing for us. I would,therefore, plead to the Goverment, the opposition leaders and people belonging to all parties to place the country before other things. If the country is intact these parties can also be there, otherwise nobody would remain alive.

Congrss Party is in power in the country for the last 20 years. I pray to God that it may remain so for many more years. But the temper of the country now indicates that the circumt stances are not favourable to them and the Congress ship would sil smoothly, I have doubt abou-it. My friend Shri Randhir Singh mentioned certain problems such as language problem, border problem, problem of communalism and the problem of unemployment. There is all round unemployment in the country now. It is not only that 50,000 engineers are unemployed in the country but there are others such as students, art students, labour, agricultual labour and the peasantry. You will know about the presantry if you move about in the country. Unfortunately, we mostly travel by air. If one has to reach Calcutta he would go by air and reach in 12 hours. I also plead guilty of this charge. I realise it fully if you go to the country-wide you will know the plight of the peasantry, the factory labourers. If you go to Moradabad you will find that the workers who earn much foreign exhcange for the nation, have to sit for hours before the oven.

There is a strike by teachers and students at many places. It apears that the whole country is restless now. Nobody is justified whether one belongs to Assam, Kashmir, Madras, Delhi or Haryana. But who will solve, all these problems ? You may accuse the Government as much as you like but there is no effect. Criticism has not effect on these people.

It is said that Indias' language should be Hindi. Agreed. Constitution has also recognised that and provided for that. But when a problem has arisen we cannot shut our eyes to that. We have to solve this problem. Language problem is important problem. It has almost isolated the North form the South. Life and property is being detroyed here as well as there. The problem is be fore the whole of India today.

The hon. President said in his Address that 95 million tonnes of foodgrain have been produced in the country. One of our friends has said that this has happened with the grace of God and Lord Indra. Lord Indra was displeased with us 1½ years back, when our food production was only 6 crores tonnes. If he changes his mood, it would then not be possible for us to mention for food prodution was only 6 cores tonnes. If he changes his mood, it would then not be possible for us to mention food production of 9½ or 10½ crores tonnes in the next Address.

It is, therefore, necessary to pay attention to this problem. We should not slacken our efforts on the food front, for weather conditions in our country are very uncertain.

Today, the country is facing recession. Money is disappearing from the country, and is affecting Industry. Industries—big and small—are closing down one after another. Are these not the problems facing the country today ? Also trade and Commerce are declining. Are these problems not to be tackled ? Apart form this there are numerous economic, political and social poblems in the country. But who is there to tackle these problems ? Jawaharlal Nehru died after the Third Plan was framed. Thousands of crores of rupees were spent on the Third Plan. Some may say that India has not made any progress. India has progressed much. India of 1967 is different from India of 1947 and no one can deny it. I do not accuse the planners and the Government nor do I impute motives. But the fact remains that although only three years have passed since Shri Jawahar Lal Nehru passed away, the whole planning, Planning Commission's statistics, man-power reports, man-power committees and all such things have stopped. Today there are 50,000 surplus engineers in the country. I was a member of National Development Council in 1963, at that time Panditji used to say that he was looking for that time when large number of engineers would be available in the country, so that we may march ahead. After four years, we hear from the Government that

there are 50,000 surplus engineers. What should they do ? Whose fault it is ? Crores of Rupees have been invested in L. I. C. and the other allied concerns, which is not being properly utilized. As has been stated by Shri Randhir Singhji, I also stress that this money should be profitably utilized. You can invest this money in building small houses in villages and towns. This would provide employment to the engineers, and provide good investment for the money.

Today, we are going down and try to face manyfold problems with wrong approach. When the approach is wrong the result is bound to be wrong. The issue of Rann of Kutch should not be regarded an ordinary issue. This is a very important matter. To say that it is a report of the arbitrator, therefore it is binding—Agreed that it is binding, but the question is whether all the aspects of the csae had been studied before referring it to arbitration ? Whether any provision of safety was included in the agreement drawn by Government ? As far as I have studied the clauses of the agreement, the Government had put its seal of approval at ten places instead of two. Although 90 percent of Pakistani claim has been rejected, but viewing it from national angle we have lost the Rann of Kutch, whether it is 10,12 or 30 percent. We cannot go in the remaining 90 percent of the Rann as it remains water logged all the year round. But on the other hand the 350 miles to be given to Pakistan is grassland, and habitable land. I am prepared to tolerate the surrender of this territory to Pakistan, provided by doing this we may have permanent peace with Pakistan. But the question remains whether it would really bring peace ?

We have only been indulging in tall talk. When Kashmir became the integral part of this country in 1947, it was an area of 86,000 square miles Now it is 40,000 square miles. We have lost 4600 Square miles of our area, part of it has been snatched by Pakistan and part of it has been grabbed by China. But this heavy loss of territory has not brought the peace. We should understand that peace cannot be purchased, it can only be secured through our internal strength.

In 1949, after Kashmir Conflict Mcnougtan proposals were received here, and Sheikh Abdullah were here to consider them. Pt. Nehru was presiding over that meeting. The hon. Sardar Patel and Maulana Azad were also there, many Army Generals and Secretaries were also present. Question was whether to accept them or reject them. Sir Girja Shanker Bajpai, the the Secretary General had prepared a note recommending to the Government to accept the award. The Sardar heard the report patiently from 9 to 1 Oclock, he stood up at the end and wrapping his shawl around his shoulders, said in his charactersic manner, "Panditji, kindly reject it, it would disintegrate the country and we would be undone, this may be rejected". He had said to at if we are strong internally, only then we would command respect outside, if we have no respect at home, nobody outside, would care for us. The Sadar left the meeting ther eafter, followed by the Maulana. The next day, the Secretary General prepared a report recommending its rejection. Same is the position today. If the country becomes strong and start paying attention to the prolems of the country forgetting the past, ensuring the future, there can be some hope. Once we are addicted to surender, this habit will persist enterally. Insecurity and instability are rampant every where in the country and the temper is very high. I can say tht Arbitration is proper undoubtedly. In the international field treaties are signed between nations. But in our case whatever has happened, we are responsible for it. Our case has gone by default. We did not make full preparations for it. We claim to be legalistic, but on the other hand Pakistan prepared her case more thoroughly. They told the Tribunal that they were also there while in fact they were not there and as a result we lost the case. We met the same fate in 1948.

The problems are manifold, but one important problem has been referred to by Shri Randhir Singh. We are looking after so many things, but terribly lack resources. If the Government can mobilize some resources, they can increase salaries. But we have to go with our mearge resources. Pay Scales of all categories of people have been raised, but the salaries of our Defence Personnel have not been increased. Let me state that our Jawans have done their duty in very difficult terrain and under very difficult circumstanses. Government have done something in this direction, I submit that more attention should be paid to improve their economic condition further. They should be made happy so that they may defend the borders of our motherland with cheerful glee.

Another point which I want to stress is about the declaration of 'Plan Holiday' by Government. Agreed, that finance is not available, loans are not forthcoming, there is foreign exchange difficulty. It is also being said that Fourth Five Year plan would begin from 1969. I think that should have been the end of the Fourth Plan. Every body seems to be on a holiday at present. Sir, I would appeal to Government and all the leaders of opposition Parties in the name of the country to see reality after shedding false notions of presitge, and face problems before us. I would say let there be a file holiday also, we can afford that. The Government functions with all sorts of formalities, all the 24 hours. Heavens would not fall if we have a file holiday along with Plan Holiday. Government would then be able to solve the national problems, the language problem without adopting this attitude that since this is our language therefore it must be accepted. Times are gone when Government should convene a Round Table Conference of the North and the South and try to solve the language problem. They should leave everything, receptions, inviting the VIPs, and concestrate on solving all the national problems. This is the only way to salvation. We have seen that 13 Governments have changed within one year. A person who was a Chief Minister yesterday today has been deprived of even the membership of the legislature. Our Government will also not remain in power for ever, attention shoud be paid towards the national problems. Shri Morarji Deasi runs in one direction, the hon. Prime Minister runs in another direction and all other Ministers run in different direction. This should not happen. National leaders should sit together and solve national problems as best as they can. Do not get out of the room till you find out a solution. This type of attitude should be there.

Maharashtra and Mysore are quarrelling with each other. Tomorrow Punjab and Haryana can quarrel with each other. U.P. can also quarrel. This process will not end. I would therefore submit let all of us unitedly check the disintegration of the country-check regionalims, linguism, communalism. We have given a very beautiful slogan of socialism and secularism to ourselves, but it is regretable that both these things are missing.

But that is our objective, the target towards which we have to march. It is wrong to say that nothing has been done in this direction. Much has been done and much has yet to be done. I, therefore, submit that all these problems need Government's attention. When our standard will improve confidence in Government would increase, and then problems would be solved. Today it is said that food production has touched 95 million tonnes. This is so with the grace of God and monsoons but prices continue to soar higher and higher. There is one price in the morning and a different price at night. One of our cherished desires and objects was to arrest the price line in 1947. Arrest means stop. Has it been stopped ? Let Government decide that prices would not be allowed to go up, whatever may happen. You raise the salary of a teacher by Rs.20 who has a family of five and he spends Rs. 50 more during the same month. Thus he always remains minus and bankrupt.

You raise the salary of a policeman by Rs.25 but prices again shoot up and take away Rs.50. He again remains minus. You have been enmeshed in such fire as has made the solution difficult. Therefore, I may say that success can be achieved if leaders of both sides try to find a solution.

Regarding the question of toppling, they would topple Ajoy Mukerji, others would topple P. C. Ghosh--this would go on happening. But if the problems of the country are to be solved, if the country and its honour is to be saved--the country for the sake of which Gandhi and Jwaharlal sacrificed and we don't wish that those sacrifices should be allowed to go waste--you would have to try to think realisatically. Just think what has happened three years after Shri Jawaharlal Nehu ? Where are ourplans after him ? Where are our Industries and our banners of Secularism and Socialism ? Here, Mahantji has expressed his views. I have great regard for him. May be, there might be 10,20 or 50 people of such thinking. But thistype of thinking has no place in the modern times, though it my be very good. We should keep in mind that India does not belong to Hindus, Muslims or any other community. It is a common heritage of all Indians.

कार्य-मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITIEE

चौदहवां प्रतिवेदन

संसदीय-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं कार्य-मंत्रणा समिति का चौदहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ ।

---

*भाषा सम्बन्धी आन्दोलन में रेलवे सम्पत्ति की क्षति

LOSS TO RAILWAYS DURING LANGUAGE AGITATION

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh) : The properties of Railways is a public property. It is the property of the Nation. It is aregrettable matter that people do nots till have such realistion Now people whenever they want to protest aginstany policy of the Government, first try to estroy the public property. Violent people often make railway property a target of their rage. It is extremely bad to destroy the Railway property. Those elements who indulge in destroying the national property, should be condemned. All people should regard the property of Railways as their own property. It is the duty of State Governments to give full protection to national property. State Government should discharge their duties properly and should make every effort to protect the national property including the Railway property. If Railway property is destroyed in any State, such national loss should be compensated by that State.

---

*आधे घन्टे की चर्चा

*Half-an-hour discussion

The Railway Security and Protection Force Act should be amended. The Railway Protection Force should be given the power to use the fire arms in time of necessity while protecting the railway property. A suitable amendment to this effect should be made in the existing law. Another law should be made which should empower the Government to impose punitive fines on the people of the areas where national property is destroyed. The loss of Railway property is a loss of public property. The functioning of the railways is upset by this loss, which cause embarassment to the passengers because of prolonged delay they have to face. I would like to suggest that a compaign should be launched to tell the people that the property of Railways belonged to themselves and nothing will be gained by destroying it. Instead they themselves will have to pay more taxes to compensate the loss. May I know the effective steps Government propose to take to protect the Railway property ?

Shri Kanwarlal Gupta (Delhi Sadar) : To destroy the public porperty is an unpatriotic action. It is an anti-national action, because public porperty belongs to nation. This problem should be solved rising a tittle high over the political level. A definite scheme should be formulated for it and such a plan can be prepared in a conference of all recognised political parties convened for the purpose. This action should be taken as soon as possible. Thus all political parties should jointly make appeal to the people not to destroy the public property or Railway property.

Another suggestion I would like to make in this respect is that the Railway Potection Force should be given power to use firearms in time of necessity while protecting the Railway property. Thirdly, I want to suggest a legislation should be enacted to the effect that it will be obligatory on the part of the State Government to compensate the loss of Railway property, if public property is destroyed in their jurisdiction. In other words the States in which public property will be destroyed should be held responsible for the loss. I would like to know the reaction of Central Government to this proposal.

Shri Shinkre (Panjim): It appears that there is a conflict between good tendencies and bad tendencies ; between national elements and anti-national elements. The Chief Justice of India advised in a meeting at Bombay that the destruction to public porperty should be checked. It is not proper to say that the public property is always destroyed by political parties. Sometimes anti-social elements or miscreants indulge in such activities. An appeal should be issued by the intellectuals in our country for advising people not to destroy the railway property or any other public poroperty.

Shri Rabi Ray (Puri): The tendecy of destroying the public property should be deplored. The Ministry of Railways have argued that its property was destroyed during language agitations.But the question is whether the Ministry of Railways have taken effective security measures to save its property. Now there is a feeling in the country that the Central Government listen only when people resort to agitational approach or when there is voilence. Action should be taken to remove this feeling. Government should also take steps to increase co-operation between the States police and Railway Protection Force, because it is the responsiblity of both to protect the Railway property. Government should make such legislation which may not further agitate the people, but which may favourably appeal the people and which can be implemented easily. May I know whether Government have considered this question in this context ?

When both the Departments will work with a sense of responisbility, the work will be done smoothly.

The second point is that no work should be done in a hurry.People have been asking for convening a round table conference. Government should first think about the reactions of certain measure. Property worth crores of rupees has been destroyed.I want to know whether Government will think over this or not ?

श्री विश्वनाथन : डी० एम० के० पार्टी गोली चलाये जाने के विरुद्ध है और सार्वजनिक सम्पत्ति को हानि पहुँचाने का भी विरोध करती है । जब भी रेलवे सम्पति को क्षति होती है तो हमें बहुत दुःख होता है । हमारे दल के मंत्रियों ने कई बार जन-सम्पत्ति को क्षति होने से बचाया है । रेलवे सम्पत्ति को हानि केन्द्रीय सरकार की नीति के कारण होती है ।

देश में यह धारणा बन गई है कि केन्द्रीय सरकार हिंसा के आगे झुकती है । एक विचित्र सुझाव दिया गया है कि क्षति का बोझ राज्य सरकारों को सहन करना चाहिये ।

श्री स० कुन्दू : जब रेलवे की सम्पत्ति को क्षति के समाचार प्राप्त होते है तो बहुत दुख होता है । खेद की बात है कि हमारे युवकों में देश के प्रति प्रेम की भावना कम होती जा रहीं है । वे नहीं समझते कि रेलें देश की सम्पत्ति है और किसी व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति नहीं हैं ।

रेलवे हमारा सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि वह जनता में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिये क्या कदम उठा रहे हैं ताकि लोग अपना दायित्व समझें ; रेलवे मंत्री को सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिये कि रेलवे सम्पति की रक्षा करना उनका दायित्व है ।

Shri D. S . Patil (Yeotmal) : The Central Government's property has been destroyed in recent language agitation. State Goverments, property has not ben destoryed. It clearly shows that the State Governments have not taken adequate care in protection of Government property. I suggest that State Governments might be asked to compensate for the loss sustained in their States.

The problem of law and order should not be the sole responsibility of State Governments. The Central Government should think over this matter.

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : इस चर्चा के दौरान मुख्य रूप से दो प्रश्न उठाये गये हैं । सरकारी सम्पत्ति को सुरक्षित रखने के लिये क्या उचित प्रबन्ध किया गया था और क्या राज्य सरकार से पुलिस-सहायता मांगी थी ।

इस सम्बन्ध में मैंने 13 तारीख को एक प्रश्न के उत्तर में भी जानकारी दी थी । भाषा के प्रश्न को ले कर जो गड़बड़ी हुई है उस पर हमें बहुत खेद है । यह आन्दोलन पहले उत्तर प्रदेश म आरम्भ हुआ । हमने राज्य के मुख्य मंत्री से सम्पर्क स्थापित किया और शान्ति स्थापित हुई ; उसके बाद आंध्र प्रदेश में गड़बड़ होने लगी । हमने राज्य सरकार को सावधान किया और स्थिति अधिक नहीं बिगड़ी । 20 दिसम्बर को मदुराई में आन्दोलन आरम्भ हुआ ।

रेलवे अधिकारियों ने राज्य सरकार के अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया और उनसे आवश्यक सहायता मांगी।

रेलवे सुरक्षा दल की शक्तियां समिति हैं। उसे तो मुख्य रूप से निगरानी-कार्य करना होता है; कानून और व्यवस्था बनाये रखना राज्य सरकारों का काम है। खेद की बात है कि लोग अपना रोष रेलवे सम्पत्ति को हानि पहुंचा कर करते हैं। यह ठीक नहीं है। हमें समझना चाहिये कि रेलवे किसी विशेष दल की सम्पत्ति नहीं है। हम सबको चाहिये कि जनता को बतायें कि यह देश की सम्पत्ति है। हम सभी राजनैतिक दलों केनेता ओं का एक सम्मेलन बुलाने पर विचार कर रहें हैं।

कानून के अनुसार हम रेलवे सम्पत्ति की हानि के लिये राज्य सरकार से मुआवजे की मांग नहीं कर सकते। इस विषय पर हमें और ध्यान देना होगा।

*श्री स० कुन्डू.....

*Shri Rabi Roy....

Shri Onkar Lal Berwa : Sir, there is no quorum in the House.

श्री चे० मु० पुनाचा : श्रीमान्, मैंने अपनी बात पूरी कर ली है।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, 22 फरवरी, 1968/ 3 फाल्गुन, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday the 22nd February, 1968 /Phalguna 3, 1889 (Saka).

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया गया।

Printed by Job Printers, 119 Swami Vivekanand Marg, Allahabad.